मैं अखिलेश

डॉ. शीबा ख़ालिद

BlueRose
Publishers

©Sheeba Khalid2021

All rights reserved

All rights reserved by author. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the author.

Although every precaution has been taken to verify the accuracy of the information contained herein, the author and publisher assume no responsibility for any errors or omissions. No liability is assumed for damages that may result from the use of information contained within.

First Published in June 2021

ISBN: 978-93-5427-768-9

Price: INR 500/-

BLUEROSE PUBLISHERS

www.bluerosepublishers.com

info@bluerosepublishers.com

+91 8882 898 898

Cover Design:

Nirmal

Typographic Design:

Namrata Saini

Distributed by: BlueRose, Amazon, Flipkart, Shopclues

प्रस्तावना

हम किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हो, कोई भी भाषा बोलते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम एक परिवार का हिस्सा होते हैं तो हम अपने परिवार के विकास के बारे में सोचते हैं, जब परिवार से बाहर आते हैं तो अपने गाँव या शहर जिसका हम हिस्सा होते हैं उसको विकसित देखना चाहते हैं | जब हम अपने राज्य से बाहर निकल के दूसरे राज्य में जाते हैं तो दूसरे राज्यों से अपने राज्य की तुलना करते हैं और देश छोड़ के बाहर जाते हैं तो अपने देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा देश हर मामले में सबसे आगे हो |

लेकिन ये विकास होगा कैसे ? अगर परिवार को आगे ले जाना है तो परिवार का मुखिया सक्षम होना चाहिए| ताकि वह परिवार कि तमाम कमियों को दूर करके उसे आगे बढाने कि कोशिश करें | देश, राज्य, शहर या गाँव को विकसित करने के लिए उसका मुखिया सक्षम होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए| अगर एक डॉक्टर धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर चिकित्सा करेगा तो कभी भी सही उपचार मरीज़ को नहीं मिलेगा | एक शिक्षक यदि पढ़ाने में या अंको को देने में भेदभाव रखेगा तो कभी भी अपने पद के साथ न्याय नहीं कर सकता और उसको उस पद पर बने रहने का कोई हक नहीं होता | उसी प्रकार यदि राज्य को या देश को चलाने वाला नेता किसी भी प्रकार का भेदभाव करता है चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, जाति या वर्ग का हो तो उसे हमारे देश या राज्य कि कमान सँभालने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए |

अपने देश में बढ़ते हुए भेदभाव और रोज़ कि अजीब घटनाओं को देखती हूँ तो बहुत दुःख होता है, आंखें बंद करके सोचती हूँ कि क्या कोई ऐसा नेता है जो इस भेदभाव की, तुष्टिकरण की राजनीति से हट कर हमारे समाज को विकास कि तरफ ले जाये, इस तकनीकी युग में हमारे युवाओं को सही दिशा दिखा सके |

तब एक ही चेहरा, एक ही नाम मेरे मन में, मेरे दिमाग में आता और वो है अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ विकास कि बातें कि और उनपर काम करने कि कोशिश की | ५ सालो के बहुत ही कम समय में उन्होंने शिक्षा, तकनीकी, सड़क से जुडी हुई समस्याएं, ब्रिज, एक्सप्रेस वे, बिजली. पानी, सुरक्षा के साधन, महिलाओं कि सुरक्षा, बुजुर्गो की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा और बहुत से कार्य जिन्हें कि उन्होंने समझा कि ये हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य समस्याएं हैं उसे दूर करने कि कोशिश की | कभी भी उनके एक भी भाषण में मैंने उन्हें धर्म या जाति की बात करते नहीं सुना बस युवाओं को आगे लाने की या राज्य को विकसित करने की

बात की | क्या धर्म के नाम पर लोगों को बाँट कर या अपने भाषणों में धर्म का नारा लगाकर ही हम ये साबित कर पाएंगे कि हम कितने धार्मिक हैं या सिर्फ हम ही हैं जो अपने धर्म के रक्षक हैं ? इसमें गलती उनकी नहीं जो हमें धर्म के नाम पर बाँट रहे इसमें गलती हमारी है कि हम उनकी तुष्टिकरण की राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं और अपनी सुख शांति के दुश्मन खुद ही बन के बैठे हैं |

इस किताब को लिखने का मकसद किसी पार्टी को बढ़ावा देना नहीं है बस ये बताना है कि एक नयी सोच लाने कि ज़रूरत है, हमें हमारी पहचान को बनाने कि ज़रूरत है, और पहचान हमारी हमारे राज्य से है, हमारे देश से है | हमारा विकास तभी संभव है जब हम सबका विकास हो, हमारे राज्य का विकास हो, तभी हमारे देश का भी विकास सही मायनों में होगा | हम विकासशील देशों की श्रेणी से निकल कर विकसित देशों कि श्रेणी में तब ही आ सकते हैं, जब हम भेदभाव से निकल के विकास के बारे में सोचें **"सोच बदलने से ही देश बदलेगा, नयी सोच, विकसित देश" |**

एक युवा नेता जिसको सिर्फ ५ साल मिले और उसने हमारे राज्य के विकास के लिए दिन रात एक कर दिया, अगर हमने उन्हें एक मौक़ा और दिया होता तो आज हमारा राज्य कैसा होता? एक कंप्यूटर या स्मार्ट फ़ोन तो देश का बच्चा-बच्चा चला रहा लेकिन उस कंप्यूटर और स्मार्ट फ़ोन का सही प्रयोग सिर्फ एक विशेषज्ञ ही बता सकता है, जो कि अखिलेश जी ने साबित किया अपने कामो से कि एक शिक्षित मुखिया कितनी भली भांति सूझ बूझ के साथ अपने काम को करता है|

इस किताब में मैंने अखिलेश जी द्वारा किये गए और घोषणा किये गए दोनों कार्यो को बताने कि कोशिश कि है जो कि मैंने खुद से नहीं लिखे बल्कि हमारी मीडिया द्वारा छापे गए कार्यों को एकत्रित करने का प्रयास किया है | बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके कार्यकाल में ही समाप्त हो गए थे और कुछ ऐसे काम हैं जो समय कि कमी के कारण पूरे नहीं हो पाए पर जिनका शुभारम्भ हो चुका था |

इस आशा के साथ मैंने इस किताब को लिखने कि हिम्मत कि है कि हम अपने हक का सही प्रयोग कर सकें और सोचें कि हमारा नेता कैसा हो ? हमें क्या चाहिए ? सही शिक्षा प्रणाली, प्रगति, रोजगार या भेदभाव |

"सोच हमारी, देश हमारा, राज्य हमारा और चयन भी हमारा"|

डॉ. शीबा खालिद

जिस दिन से चला हूँ मेरी मंज़िल पे नज़र है
आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा
(बशीर बद्र)

मुख्य मंत्री अखिलेश यादव के बारे में प्रख्यात व्यक्तियों के विचार

"उत्तर प्रदेश सरकार कि कई योजनायें ऐसी हैं जिससे समाज के कई वर्गों को फायदा पहुँचेगा | सभी राज्यों को चाहिए कि वे इस तरह कि योजनाओं को अपने यहाँ लागू करें | अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम कर रहे हैं |"

ममता बनर्जी, मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल

"उत्तर प्रदेश में समाज वादी सरकार का कामकाज और मुख्य मंत्री अखिलेश यादव का नजरिया प्रशंसा के योग्य है |"

स्वo जय ललिता (पूर्व मुख्य मंत्री, तमिल नायडू)

उत्तर प्रदेश की तस्वीर बहुत तेज़ी से बदल रही है विकास कि रफ्तार देख के मैं बहुत खुश हूँ | देश के सबसे बड़े प्रदेश को लेकर मेरी भावनाएं बहुत खूबसूरत हैं| मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रगतिशील सोच की वजह से प्रदेश में असंभव काम को संभव किया गया। जब भी मैं प्रदेश में आता हूं तो कुछ नया देखता हूं। पहले उत्तर प्रदेश की तुलना पिछड़े राज्यों में होती थी लेकिन अब अगण राज्यों में इसकी तुलना होती है।

रतन टाटा, प्रमुख उद्योगपति

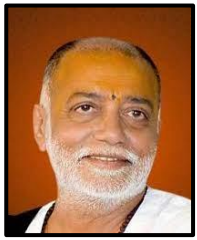

मैं देश में अनेकों मुख्य मंत्रियों से मिल चूका हूँ, परन्तु अखिलेश यादव जैसा सरल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति मुझे कोई और नहीं मिला | मुझे बेहद आश्चर्य है कि अखिलेश अंगूठी, घड़ी नहीं पहनते और कलावा भी नहीं बांधते हैं |

विख्यात संत मुरारी बापू

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में महाकुंभ के दौरान विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक मण्डली की मेजबानी के बाद, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित करने तथा 55-दिवसीय कार्यक्रम के आयोजन की कहानी साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया |

हार्वर्ड विश्विद्यालय, अमेरिका

अनुक्रमणिका

एक नज़र में जीवन परिचय..... 1
योग्यताएं जो एक नेता के रूप में अखिलेश यादव को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाती हैं..... 5
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उनके कार्यकाल में आरम्भ किए गए व पूर्ण किए गए कार्य..... 14
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे..... 15
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे..... 19
आगरा इनर रिंग रोड..... 21
4.8 किमी एलिवेटेड रोड नोएडा..... 23
10 किमी एलिवेटेड रोड गाजियाबाद..... 25
चार लेन सड़क के साथ जिला मुख्यालय को जोड़ना..... 26
राष्ट्रीय राजमार्ग -24..... 28
उत्तर प्रदेश में साइकिल ट्रैक..... 31
भारत का पहला साइकिल राजमार्ग: इटावा से आगरा..... 34
लखनऊ मेट्रो..... 36
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो लिंक की नींव रखी..... 39
सेक्टर 62-सिटी सेंटर मेट्रो..... 41
गाजियाबाद नया बस अडडा मेट्रो..... 43
बस सेवा पहले मॉडल स्टेशन के साथ हाई-टेक हो जाती है..... 45
दिल्ली की तुलना में नोएडा में अधिक उच्च तकनीक वाली बसें शुरू की गईं..... 47
सैदपुर पुल का उद्घाटन..... 48
5 करोड़ वृक्षारोपण..... 50
55 लाख पेंशन योजना..... 53
सीएम अखिलेश ने किया अवध शिल्प ग्राम का उद्घाटन..... 55
अमूल डेयरी प्लांट स्थापना: कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, सैफई..... 57
आजमगढ़ चीनी मिल..... 59

भूमि सेना योजना 61
मजदूरों को सीएम अखिलेश का तोहफा, समाजवादी थाली 10 रुपये में और शुरू की पेंशन योजना 63
लखनऊ में ड्राइवरों को ई-रिक्शा बांटते सीएम अखिलेश यादव 64
सीएम अखिलेश यादव ने विशेष रूप से विकलांग बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित की 66
सीएम अखिलेश द्वारा साइकिल वितरण और मध्याह्न भोजन योजना 68
बीज सब्सिडी के लिए यूपी का डीबीटी (DBT) मॉडल 71
कामधेनु योजना 73
कन्या विद्या धन 75
किसान बाज़ार 77
लोहिया आवास योजना 79
समाजवादी जल संचय योजना 81
बेरोजगारी भत्ता 86
यूपी सीएम अखिलेश ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष 'महिला बाजार' की योजना बनाई 87
यूपी सरकार (अखिलेश यादव) ने 2015-16 को 'किसान वर्ष' के रूप में मनाया - कृषि प्रगति, बीमा कवरेज और क्रेडिट सुनिश्चित किया 88
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीब परिवारों के लिए पेंशन योजना शुरू की 91
बुदेलखंड राहत पैकेज (समाजवादी राहत पैकेज) 92
हौसला पोशन योजना यूपी 2016- गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन 94
डायल 100 96
देश का सबसे हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम 99
शीरोज़ कैफे लखनऊ, (रेस्टोरेंट रन बाई एसिड अटैक सर्वाइवर्स) 102
यूपी वेब-आधारित उद्योग क्लीयरेंस सिस्टम-निवेष मित्र 105
उत्तर प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर लखनऊ 107
महिला हेल्पलाइन 1090 109
जीआर नोएडा में 5 हज़ार करोड़ का सेल फोन यूनिट 111
सीएम की महत्वाकांक्षी समाजवादी अभिनव विद्यालय परियोजना 114
बेनेट विश्वविद्यालय की स्थापना 117
लखनऊ में कैंसर संस्थान 119

भारतीय सांकेतिक भाषा और बधिर अध्ययन केंद्र 121
चक गंजरिया परियोजना 123
मथुरा में चंद्रोदय मंदिर 125
मुख्यमंत्री अखिलेश ने संतों को दिया उपहार, अयोध्या में बना 5000 सीटों का भजन संध्या स्थल 127
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया में एक स्पोर्ट्स कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक पावर स्टेशन की नींव रखी 129
विद्युत उत्पादन में उपलब्धि 131
लखनऊ में फिल्म टीवी संस्थान 137
फिल्म प्रचार नीति 139
गोमती नदी सौंदर्यीकरण 141
हेरिटेज जोन 143
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ 144
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सैफई 146
लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम 148
अंतर्राष्ट्रीय इत्र पार्क कन्नौज 150
अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल सैफई 151
आईटी सिटी लखनऊ 153
जनेश्वर मिश्र पार्क 155
जेपी इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ 160
कुशी नगर हवाई अड्डा (अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा) 162
लैपटॉप वितरण योजना 164
लेदर पार्क कानपुर 167
लायन सफारी इटावा 169
मैत्रेय परियोजना-कुशीनगर 172
मुगल संग्रहालय 174
नये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज 176
न्यू हाईकोर्ट लखनऊ 178
न्यू लखनऊ सचिवालय 180
उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज 183
उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेज 185

प्लास्टिक सिटी, औरैया परियोजना 188
समाजवादी स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेंस) 191
सरस्वती हाई-टेक सिटी इलाहाबाद 194
शिक्षा मित्र नियुक्ति-1.75 लाख शिक्षक नियुक्ति 196
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय 198
कौशल विकास मिशन (कौशल विकास योजना) 200
सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि 202
स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई 205
ताजगंज प्रोजेक्ट 207
ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट उन्नाव 208
वरुणा नदी की कायाकल्प 211
एकीकृत पोर्टल 'जन-सुनवाई' (jansunwai.up.nic.in) का शुभारंभ किया 214
कुछ अन्य प्रोजेक्ट 216
संदर्भ 221

एक नज़र में जीवन परिचय

अखिलेश यादव 1 जुलाई, 1973 को मुलायम सिंह यादव और मालती देवी जी के घर, सैफई में पैदा हुए, अखिलेश यादव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के धौलपुर सैन्य स्कूल में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बैचलर डिग्री मैसूर विश्वविद्यालय और सिविल एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री सिडनी विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त किया।

मार्च, 2012 में, उन्हें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था। 38 वर्ष की आयु में, वह उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। यादव ने 24 नवंबर 1999 को डिंपल यादव से शादी की और उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। डिंपल एक राजनेता भी हैं।

2012 से 2017 तक, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के 20 वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने 15 मार्च 2012 को आधिकारिक जिम्मेदारियों को स्वीकार किया और 38 साल की उम्र में यह पद संभालने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 2000 में कन्नौज का लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की।

2017 के यूपी राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान, अखिलेश ने लगभग 10,000 किलोमीटर की यात्रा की और यूपी में 800 रैलियों का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश की नई छवि ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने और किसानों और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए उनकी सक्रिय भागीदारी का एक ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने युवा पीढ़ी के कल्याण में कई अच्छे कदम उठाए हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय राजनीति में युवा चेहरों में से एक माना जाता है।

- 2017 अखिलेश यादव ने सपा-कांग्रेस गठबंधन का नेतृत्व किया।
- उन्हें 10 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था।

- वह 15 मार्च 2012 को उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उनकी उम्र 38 वर्ष थी।
- 2009 को तीसरे कार्यकाल के लिए 14 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया।
- 2007 फिर से विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति के सदस्य बने।
- 2002 उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले उन्होंने दो साल तक आचार समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया।
- 2012 उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए 15 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया।
- 2004 उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए 14 वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। बाद में वह विभिन्न समितियों जैसे शहरी विकास समिति, सांसदों के लिए कंप्यूटर के प्रावधान पर समिति, दलों के कार्यालयों, लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों, आदि के सदस्य बने।
- 2000 में उपचुनाव में कन्नौज से 13 वीं लोकसभा के लिए चुने गए।
- मई 2019 में आजमगढ़ लोकसभा से सांसद चुने गए|

विचारधारा

समाजवादी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक दर्शन के साथ समानता के सिद्धांत पर काम करते हुए समाजवादी समाज का निर्माण करने में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान पर लगातार काम हो रहा है और यह सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से खड़ी है।

स्वतंत्रता सेनानी, कम्युनिस्ट और महान सांसद श्री राम मनोहर लोहिया, समाजवादी पार्टी के लिए एक मार्गदर्शक हैं। श्री राम मनोहर लोहिया की ईमानदारी, भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके निस्वार्थ संघर्ष और समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने की उनकी क्षमता ने पार्टी के नेताओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं को बहुत प्रभावित किया है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, लोहिया को कई बार अंग्रेजों ने कैद किया और उन्होंने पूरे जीवन सामाजिक समानता के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी के विचारों ने लोहिया को गहराई से प्रभावित किया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखने के लिए स्वतंत्र आंदोलन के दौरान अथक रूप से काम किया, जिससे यूरोप के साम्राज्यवाद में चेतना बढ़ी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, उन्होंने खुद को जमीनी स्तर की राजनीति के लिए प्रतिबद्ध किया जिसमें किसानों के विकास का काम और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। उन्होंने पूंजीवादी-सामंतवादी प्रवृत्तियों को भी समाप्त करने की मांग की। सत्याग्रह पर उनके उग्र लेखों और

सामाजिक समस्याओं के बारे में उनकी सहज जानकारी के साथ, लोहिया की लोगों को जगाने की क्षमता ने उन्हें भारत का अग्रणी समाजवादी नेता बना दिया। समाज के गरीब, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सामाजिक उत्थान के लिए अपनी लड़ाई में, लोहिया की करो या मरो 'की भावना समाजवादी पार्टी के लिए एक प्रेरणा और एक प्रेरणा शक्ति है।

योग्यताएं जो एक नेता के रूप में अखिलेश यादव को सबसे अधिक प्रभावशाली बनाती हैं

उपरोक्त विषय को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले मैं अच्छे नेता की विशेषताओं और गुणों को परिभाषित करना चाहूंगी । मेरे शोध के आधार पर, मैंने पाया है कि महान नेताओं के पास ये 10 मुख्य नेतृत्व कौशल अवश्य होने चाहिए:

अखंडता

सत्यनिष्ठा का महत्व स्पष्ट होना चाहिए। अखंडता व्यक्ति, संगठन और देश के लिए आवश्यक है। यह शीर्ष स्तर के नेताओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो विशेष रूप से देश के पाठ्यक्रम को चार्ट कर रहे हैं और अनगिनत अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। मेरे शोध से पता चलता है कि अखंडता वास्तव में संगठनों या देश के लिए एक संभावित महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

विरोधियो द्वारा ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में होने पर अपराधियों का हाथ होता है। लेकिन जब अखिलेश ने 2012 के चुनावों के लिए प्रचार किया, तो उन्होंने सुनिश्चित किया कि वह इस 'छवि' के साथ दूर रहेंगे | मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान, अखिलेश ने भ्रष्टाचार के आरोपियों को भी मंत्री पद से दूर रखा "कौमी एकता दल" के साथ गठबंधन करने में अखिलेश का यू-टर्न इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अखिलेश यादव वास्तव में पार्टी की छवि को साफ करने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सभी नेताओं को बाहर का दरवाजा दिखाने के लिए गंभीर हैं। उन्होंने हमेशा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे किसी भी गतिविधि में लिप्त न हों, जो सरकार या सपा की छवि को खराब करता हो।

इस सब ने अखिलेश को एक साफ छवि वाला नेता बना दिया, जिसका विकास एजेंडा था और न कि जाति-आधारित राजनीति का अनुयायी।

प्रतिनिधित्व करने की क्षमता

प्रतिनिधित्व एक नेता की मुख्य जिम्मेदारियों में से एक है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो सकता है। लक्ष्य केवल अपने आप को महत्व देना नहीं है - यह आपकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट को सक्षम करने, टीम वर्क को सुविधाजनक बनाने, स्वायत्तता प्रदान करने, बेहतर निर्णय लेने के लिए नेतृत्व करने और आपकी प्रत्यक्ष रिपोर्ट को बढ़ने में मदद करने के लिए भी है। अच्छी तरह से प्रतिनिधि बनाने के लिए, आपको अपनी टीम के साथ विश्वास बनाने की भी आवश्यकता है।

हर दिन जब अखिलेश यादव राजनीतिक सलाहकारों के साथ अपने जनता दरबार, जो कि लखनऊ का 5 कालिदास मार्ग था सलाहकारों और वफादारों के साथ जनता दरबार में पेश होने का समय था । एक मोटिवेट लॉट, उनमें उनके विश्वसनीय नौकरशाह, पिता मुलायम सिंह यादव के समाजवादी सहयोगी, एक चाचा, चचेरे भाई और उनके समाजवादी 'यूथ' के शूरवीर शामिल थे ।

चार साल तक विपक्ष ने समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार पर उत्तर प्रदेश में "साढ़े चार मुख्यमंत्री" होने का आरोप लगाया था । जैसा कि यादव परिवार का झगड़ा महीनों बाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों में सामने आया, यह सबसे कठिन समय था । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का राजनीतिक जोर राज्य मंत्रिमंडल से असंतुष्टों की अलोक प्रिय बर्खास्तगी के लिए अपने अभियान की शुरुआत करने के निर्णय जैसे , यादव ने कई तूफानी फैसले लिए|

विवाद के बीच सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाले पुराने नेता बनाम अखिलेश यादव के नेतृत्व में युवा नेतृत्व के बीच रस्साकशी रही , दोनों ही पार्टी की बागडोर संभालने के लिए तैयार थे । जैसे-जैसे परिवार का राजनीतिक ड्रामा तेज होता जा रहा था , अखिलेश यादव पार्टी पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अंतिम प्रयास

कर रहे थे , जिससे पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष और उनके चाचा शिवपाल यादव का सामना हुआ |

संचार

प्रभावी नेतृत्व और प्रभावी संचार आपस में जुड़े हुए हैं। आपको अपने लोगों को कोचिंग देने के लिए जानकारी संचारित करने से लेकर कई तरह से संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। और आपको भूमिकाओं, सामाजिक पहचान और अधिक लोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को सुनने, और संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। आपके संगठन में संचार की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सीधे आपकी रणनीति की सफलता को प्रभावित करती है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में परिपक्वता के साथ शासन करते रहे ।

अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में सत्ता संघर्ष में जीत हासिल की, जो भारत के कुछ सबसे धुरंदर राजनेताओं से बेहतर जीत रही ।

स्व जागरूकता

यह एक अधिक आंतरिक रूप से केंद्रित कौशल है, नेतृत्व के लिए आत्म-जागरूकता सर्वोपरि है। आप खुद को जितना बेहतर समझेंगे, आप उतने ही प्रभावी होंगे। क्या आप जानते हैं कि दूसरे लोग आपको कैसे देखते हैं, या आप काम में कैसे दिखते हैं?

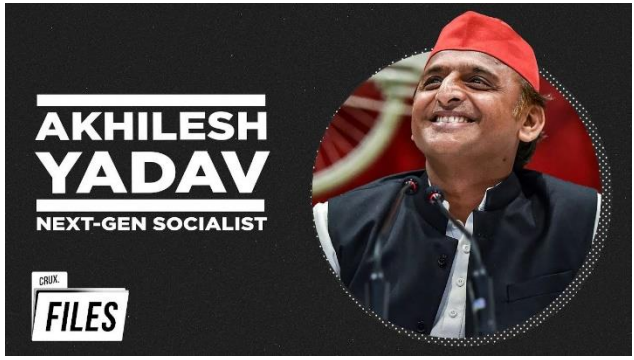

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में गरीब लोगों की समस्याओं के बारे में पता था और इसलिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई। उपचार की उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए गरीब लोगों को कभी-कभी अपने कृषि क्षेत्र को बेचना पड़ता है, सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के माध्यम से वित्तीय मदद भी देती है।

अखिलेश पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित थे क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में उन्हें उत्तर प्रदेश की समस्याओं के बारे में बेहतर समझ और जागरूकता थी । अखिलेश यादव एक सैनिक स्कूल में पढ़े , मैसूर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, एक किराए के क्वार्टर में तीन साथियों के साथ रहते थे, और जो उनका छात्र जीवन था वो आम तौर पर मध्यम वर्ग का था। उनके कुछ कॉलेज के साथी - हालांकि मित्र नहीं थे - मीडिया में यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि वे नहीं जानते कि वह एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे जब तक कि उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं किया। यादव उच्च अध्ययन के लिए विदेश गए, लेकिन तब तक उनका व्यक्तित्व बन चुका था और उनके व्यक्तित्व में युवा भारत के सपनों और चिंताओं की झलक मिलती थी । मुख्यमंत्री बनने से पहले Rediff.com को दिए एक लंबे साक्षात्कार में, यादव ने कहा, "मैं नई पीढ़ी के दृष्टिकोण से चीजों को देखता हूं और समझता हूं... अब मोबाइल फोन हैं, कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इन दिनों हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। मेरे पिता के दिन में, ये चीजें नहीं थीं। "

कृतज्ञता

आभारी होने से, धन्यवाद देने से आप एक बेहतर नेता बन सकते हैं। आभार उच्च आत्मसम्मान, अवसाद और चिंता को कम कर सकता है और यहां तक कि बेहतर नींद भी प्रदान कर सकता है। कुछ लोग नियमित रूप से काम पर "धन्यवाद" कहते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि वे एक प्रशंसनीय बॉस के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होंगे।

अखिलेश यादव ने अपने लिए एक ऐसी छवि बनाई है, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव से उल्लेखनीय है। अखिलेश यादव ने अपनी छवि को बदलने नहीं दिया , भले ही उनके परिवार के बुजुर्ग उनसे सहमत न हो |

देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कई लोगों के लिए बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ मायनों में उनकी दया और करुणा और उदारता से दिल जीतते हुए दिखाए देते हैं ।

वह कभी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं, जो उत्कृष्ट समर्थन और पार्टी की सफलता के लिए काम करते हैं ।

चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के समर्थन के लिए मायावती को धन्यवाद देने के बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने यहां बसपा नेता के आवास पर जाकर उनके प्रति आभार व्यक्त किया।

सीखने की दक्षता

सीखने की चपलता यह जानने की क्षमता है कि जब आप नहीं जानते कि क्या करना है। यदि आप "त्वरित अध्ययन" कर रहे हैं या अपरिचित परिस्थितियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो आप पहले से ही चुस्त हो सकते हैं। लेकिन कोई भी अभ्यास, अनुभव और प्रयास के माध्यम से सीखने की क्षमता को बढ़ावा दे सकता है।

मुलायम सिंह यादव को पिता और पार्टी अध्यक्ष के रूप में देखना और दोनों ही रिश्तो के बीच सामंजस्य स्थापित करने में अखिलेश यादव की कार्य कौशल की सभी लोग सराहना करते हैं । उन्हें परिवार और पार्टी दोनों ही तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मुज़फ्फरनगर दंगों से पहले और बाद में अनगिनत अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, यूपी के मुख्यमंत्री ने मुश्किल समय में भी अपना आपा नहीं खोया और सूज बूझ के साथ कठिनाइयों का सामना करते हमेशा मुद्दों को शानदार ढंग से सुलझाने की कोशिश करते रहे ।

प्रभाव

कुछ लोगों के लिए, "प्रभाव" एक गंदे शब्द की तरह लगता है। लेकिन तार्किक, भावनात्मक या सहकारी अपील के माध्यम से लोगों को समझाने में सक्षम होना एक प्रेरक, प्रभावी नेता होने का एक घटक है। प्रभाव हेरफेर से काफी अलग है, और इसे प्रामाणिक और पारदर्शी रूप से किए जाने की आवश्यकता है।

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के शब्दों में पार्टी की छवि को "गुंडों की पार्टी" के रूप में बनाने की कोशिश शामिल थी। अखिलेश ने यूपी चुनावों में खुद जनता के बीच के जाने वाले उम्मीदवारों पर जोर दिया, अपने अभियान के माध्यम से उन्होंने कानून और व्यवस्था को अपनी पार्टी के अग्रणी एजेंडे के रूप में बताया और सपा की जीत के बाद गुंडा राज से यूपी की आजादी का वादा किया। उनके पास अन्य चुनौतियाँ थीं। तीन साल पहले, 2009 के आम चुनावों से पहले, सपा ने कहा था कि वे अंग्रेजी के उपयोग और कंप्यूटर के उपयोग के खिलाफ है। 2012 तक, स्कूल-छोड़ने वाले छात्रों के लिए लैपटॉप और टैबलेट का वादा करने वाला घोषणापत्र सबसे पहले सपा का ही था। घोषणा पत्र शिक्षा के एजेंडा के साथ आगे बढ़ा और यादव जूनियर ने वादा किया कि इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और अपने इस वादे को उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारियो के साथ निभाने का काम भी किया |

सहानुभूति

सहानुभूति प्रदर्शन और एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ सहसंबद्ध है भावनात्मक बुद्धि, नेतृत्व, प्रभावशीलता और सहानुभूति सीखी जा सकती है, और यह आपको अधिक प्रभावी बनाने के अलावा, यह आपके और आपके आस-पास के लोगों के लिए भी काम में सुधार करती है । देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कई लोगों के लिए बहस का विषय हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव कुछ मायनों में उनकी दया और करुणा से दिल जीत लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, मुख्यमंत्री ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह कई मदद की है, मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष और अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से, कई लोगों के लिए कई जानलेवा स्थितियों में उनकी मदद् सराहनीय है |

चार साल की बच्ची पर सर्जिकल प्रक्रिया करवाने में उसकी मदद और समर्थन: यह मामला उनकी जानकारी में आया, एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जिसके बाद यादव ने अपने कार्यालय में अधिकारियों से स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने और "ज़रूरतमंदों को मदद दिलाने" के लिए कहा। लड़की, रेणु, के सिर के ऊपर एक फुटबॉल के आकार का ट्यूमर था जो एक छोटे से पुट के रूप में शुरू हुआ था |अब उसकी आंखों की रोशनी और यहां तक कि उसके जीवन को भी खतरा था । उसके पिता, एक मजदूर जो बस्ती के झिनकान गांव में रहते हैं, को कुछ छात्रों ने अपने सोशल नेटवर्किंग पेज पर मुख्यमंत्री को याचिका देने की सलाह दी। कुछ अन्य लोगों ने उन्हें लड़की की तस्वीरें पोस्ट करने में मदद की। यादव ने याचिका दायर करने के बाद तुरंत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में भर्ती होने के लिए कहा, जहां उनका ऑपरेशन हुआ था। लड़की अब वापस सामान्य स्थिति में आ गई है और अपनी माँ को जल्द से जल्द स्कूल भेजने के लिए कह रही थी। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था क्योंकि उसके माता-पिता ने उसे बड़े ट्यूमर की वजह से स्कूल में प्रवेश होने नहीं दिया था।

साहस

काम पर बोलना कठिन हो सकता है, चाहे आप किसी नए विचार को आवाज़ देना चाहते हों, किसी प्रत्यक्ष रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देना चाहते हों या अपने से ऊपर के

किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात रखने का साहस होना बहुत कठिन विषय है । यही कारण है कि साहस अच्छे नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल है। समस्याओं से बचने या संघर्ष को रोकने की अनुमति देने के बजाय, साहस नेताओं को सही दिशा में कदम बढ़ाने और चीजों को स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।

अखिलेश यादव ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है, जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव से उल्लेखनीय है। कुछ मामलो में भले ही उन्हें अपने परिवार के बुजुर्गों के खिलाफ जाना पड़ा, पर उन्होंने साहस नहीं छोड़ा |

उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बहादुर चेहरा यह कहते हुए पेश किया कि 'समाजवादी परिवार' सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट है। "समाजवादी परिवार पहले की तरह ही एकजुट हैं और आने वाले दिनों में, राज्य और सरकार के सामने चुनौतियों के लिए तैयार है , सांप्रदायिक ताकतें (जो) किसी भी तरह से प्रवेश करना चाहती हैं, का सामना एकजुट रूप से किया जाएगा | समाजवादी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी कि समाजवादी सरकार सत्ता में लौटे और राज्य को विकास और समृद्धि की दिशा में ले जाए।

आदर करना

दैनिक आधार पर लोगों के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना सबसे महत्वपूर्ण काम है जो एक नेता कर सकता है। यह तनाव और संघर्ष को कम करेगा, विश्वास पैदा करेगा और प्रभावशीलता में सुधार करेगा। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उनसे ये उम्मीद कि जाने लगी कि वह यादव समाज को पुरानी धारणाओ और विचारो से बाहर निकाल कर उनमे नयी सोच का संचार करेंगे बिना उनके आदर और सम्मान को ठेस पहुचाये हुए ये यादव समाज के लिए बहुत ही गर्व कि बात है कि उनका अपना अखिलेश यादव जिसका मूल लक्ष्य आधुनिकता विकास और कानून व्यवस्था को लागु करना है|

आधुनिकता की भाषा, प्रौद्योगिकी और विकास के लिए अपने अभियान में प्रकट, कानून और व्यवस्था के लिए प्रधानता के इस दृष्टिकोण से, यादव आधुनिकता और परंपरा के बीच का सेतु है। न तो उनकी जाति और न ही क्षेत्रीय पहचान उनके महानगरीयपन से प्रभावित हुई है। सब एक साथ उनके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो प्रामाणिक रूप से उनकी छवि में दिखाई देते है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा उनके कार्यकाल में आरम्भ किए गए व पूर्ण किए गए कार्य

वैसे तो अखिलेश यादव जी ने अपने ५ साल के कार्यकाल में अनेको विकास के कार्य किये जिनको कि एक किताब में लिखना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा परन्तु उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे

अनुबंध के अनुसार, परियोजना की निर्माण अवधि 36 महीने थी। जबकि इस परियोजना को कम समय में पूरा किया गया था और 21.11.2016 को सीएम अखिलेश यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था|

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किमी लंबा एक्सप्रेसवे है जिसे यूपी सरकार (सीएम अखिलेश यादव) अपने संसाधनों से विकसित किया । एक्सप्रेस-वे का विकास राज्य सरकार के वित्त पोषण के माध्यम से किया जा गया , बजाय निजी विक्रेता वित्तपोषित आधार के, डेवलपर कंपनियों को एक्सप्रेस-वे पर मुफ्त भूमि पार्सल के प्रावधान के बिना राजमार्ग आगरा के आंतरिक रिंग रोड पर शुरू होता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव जिले से गुजरता है और यह SH-40 पर लखनऊ में समाप्त होता है। एक उच्च गति वाले गलियारे की सुविधा दी गई है, जो राज्य की राजधानी लखनऊ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी, नई दिल्ली से जोड़ता है। आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय 03 घंटे कम होकर और यमुना एक्सप्रेसवे से नई दिल्ली तक 5 1/2 घंटे हो गया है।यात्रा के समय में कमी होने के कारण, ईंधन की खपत में काफी बचत हुई है और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आई है। एक्सप्रेसवे में निकास / प्रवेश के लिए इंटरचेंज को प्रमुख सड़कों के साथ क्रॉसिंग पर प्रदान किया गया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे 302.222 किलोमीटर लंबा 6 लेन (08 लेन तक विस्तार योग्य) एक्सेस कंट्रोल (ग्रीनफील्ड) एक्सप्रेसवे के 08 लेन के भविष्य के विस्तार के लिए 08-लेन चौड़ी संरचनाओं वाला एक्सप्रेसवे है।

एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा के लिए 04 नग वेदरसाइड सुविधाएं, 02 नग एक्सप्रेसवे के प्रत्येक कैरिजवे के साथ, लखनऊ से 75 किलोमीटर और 198 किलोमीटर और आगरा से 101 किलोमीटर और 218 किलोमीटर की दूरी पर विकसित किया गया है। विविध सेवाएं, अर्थात व्यापक पार्किंग क्षेत्रों, सार्वजनिक शौचालय, फूड कोर्ट, ढाबा, होटल, विश्राम्ग्रह, और ईंधन स्टेशन के साथ प्रत्येक वॉइसाइड सुविधाओं में कार्यात्मक हैं।

स्थानीय समुदाय की सुविधा के लिए, मेजर ब्रिज और आरओबी स्थानों को छोड़कर, एक्सप्रेस-वे के पार एक्सप्रेसवे सर्विस रोड प्रदान किए गए ।

एक्सप्रेसवे के चौबीसों घंटे गश्त करने और दुर्घटना पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए, यूपीडा ने 120 पूर्व सेवा सदस्यों के साथ 15 इनोवा तैनात की । इसके अतिरिक्त, एक्सप्रेस-वे पर गश्त करने के लिए पुलिस विभाग द्वारा 27 डायल -१११ वैन भी तैनात की गई । यूपीडा द्वारा किसी दुर्घटना के पीड़ितों का समर्थन करने के लिए 04 एम्बुलेंस जुटाई गई , इसके अलावा, उनकी ओर से टोल संग्रह एजेंसी द्वारा 10 गश्ती वाहन और 05 एम्बुलेंस तैनात किए गए । इसलिए, UP-112 के अलावा, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कुल 25 गश्ती वाहन और 09 एम्बुलेंस तैनात हुयी ।

परियोजना में दी जाने वाली प्रमुख सुविधाएं

- सीमित प्रवेश / निकास बिंदुओं के साथ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे।
- कैरिजवे - 06 लेन डिवाइडेड कैरिजवे (08 लेन तक विस्तार योग्य) सभी संरचनाओं के साथ 8 लेन चौड़ी।
- आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय लगभग 3-5 घंटे तक कम हो जाता है।
- वाहनों के लिए अंडरपास, पैदल यात्री और पशु के लिए प्रमुख इंटरचेंज की व्यवस्था कि गई |
- एक्सप्रेसवे के साथ-साथ सभी प्रमुख पुलों के दोनों तरफ सर्विस रोड हैं |

- एक्सप्रेसवे के दोनों ओर प्रत्येक स्थानों पर टॉयलेट ब्लॉक, पेट्रोल पंप, सर्विस स्टेशन, रेस्तरां और शॉपिंग आर्केड आदि के लिए प्रावधान के साथ साइड सुविधाएं दी गई हैं ।
- आपात स्थिति में लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए हवाई पट्टी का प्रावधान।
- उन्नत ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉल बॉक्स (ईसीबी), डिजिटल मैसेज स्क्रीन, वीडियो मॉनिटरिंग और इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम, जीपीएस आधारित एम्बुलेंस सेवा आदि शामिल हैं।
- सभी रोशनी उद्देश्यों के लिए हरित ऊर्जा (सौर) का उपयोग।
- एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर ग्रीन बेल्ट का विकास और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था।
- एक्सप्रेसवे के उपयोग से मंडी का दो स्थानों पर विकास (कन्नौज और मैनपुरी)।

भारतीय वायु सेना के 03Mirage-2000 और 03SU-30 विमानों द्वारा नवनिर्मित आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर 'टच एंड गो' शो चलाया गया | एक्सप्रेसवे का निर्माण आरसीसी द्वारा किया गया है और विमान लैंडिंग की सुविधा के लिए इसे सुदृढ़ और उचित रूप से चिह्नित किया गया है। एक्सरसाइज का उद्देश्य किसी कारण के लिए एक्सप्रेस वे की वैकल्पिक व्यवहार्यता के रूप में इस्तेमाल किया गया, जो किसी भी कारण से आपात स्थिति या रनवे की अनुपलब्धता के मामले में वैकल्पिक हवाई पट्टी के रूप में उपयोग किया सकता है।

© BCCL 2021. ALL RIGHTS RESERVED.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

मई 2015उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ-आज़मगढ़-बलिया एक्सप्रेस की घोषणा की।

लखनऊ-आज़मगढ़-बलिया एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 8-लेन, विभाजित और नियंत्रित राजमार्ग है। प्रस्तावित राजमार्ग बलिया और आज़मगढ़ के ऐतिहासिक शहरों को राज्य की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगा। इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास और प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जाना प्रस्तावित है। यह 343 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा और यह बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों से होकर लखनऊ को बलिया से जोड़ेगा और बलिया जिले के भरौली गांव में समाप्त होगा।

एक्सप्रेसवे को लखनऊ से बाराबंकी तक 43.1 किमी में 8 पैकेजों में बांटा गया है। बाराबंकी से अमेठी 43.1 किमी से 86.0 किलोमीटर तक। अमेठी से जिला सुल्तानपुर 86.0 किलोमीटर से 130.0 तक। सुल्तानपुर में रतनपुर से आजमगढ़ तक। आजमगढ़ से बस्ती की दूरी 217.9 किमी से 261.4 किमी। मऊ से गाजीपुर 261.4 किमी से 304.5 किमी, गाजीपुर से बलिया 304.5 किमी से 348.1 किमी।

परियोजना घटनाक्रम

- **मई 2015:** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ-आजमगढ़-बलिया एक्सप्रेस की घोषणा करते है।
- **अक्टूबर 2015:** यूपी सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए तीन प्रस्तावित संरेखण अंतिम रूप दिया है|
- **नवंबर 2015:** लखनऊ-आजमगढ़-बलिया एक्सप्रेस का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया गया ।
- **फरवरी 2016:** राज्य सरकार ने बजट में एक्सप्रेसवे के लिए 1,500 करोड़ आवंटित किए।
- **दिसंबर 2016:** उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस परियोजना का शिलान्यास किया।

आगरा इनर रिंग रोड

सीएम अखिलेश यादव 27 नवंबर 2016 को आगरा पहुंचे और इनर रिंग रोड का शुभारंभ किया। यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे फतेहाबाद रोड पर ताजमहल के पास इनर रिंग रोड बनाया गया है, जिससे पर्यटक सीधे एक्सप्रेस-वे से ताजमहल पहुंच सकेंगे और जाम में नहीं फंसेंगे। फतेहाबाद रोड से कुबेरपुर तक सड़क तैयार है।

इनर रिंग रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग -2, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे को ग्वालियर रोड से जोड़ने की योजना है। परियोजना पर काम 2015 में शुरू किया गया था।

24 किमी प्रस्तावित, यह सड़क तीन चरणों में पूरी होगी। राजमार्ग के निर्माण के पीछे का विचार ताजमहल की ओर ट्रैफिक आंदोलन को सुव्यवस्थित करना है। इनर रिंग रोड का पहला चरण जो 11 किमी का है, पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम प्रगति पर है। अब तक, तीसरे चरण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की गई है।

4.8 किमी एलिवेटेड रोड नोएडा

सेक्टर -28 विश्व भारती स्कूल से सेक्टर -61 शॉप्रिक्स मॉल तक 4.80 किमी लंबी एलिवेटेड रोड 125 खंभों पर टिकी हुई है। यह नोएडा की पहली एलिवेटेड रोड है, जिसका उद्घाटन 14 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। पुनः इसका उद्घाटन 28 जून 2017 को राज्य में योगी सरकार के गठन के बाद किया गया |

छह लेन की इस एलिवेटेड रोड को बनाने के लिए 79 हजार मेट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया और 26 हजार टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। परियोजना का काम 15 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, जिसे 14 अक्टूबर 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खास बात यह थी कि लक्ष्य से चार महीने पहले काम पूरा हो गया था।

नोएडा शहर की 4.8 किमी लंबी एलिवेटेड रोड पर सिग्नल-फ्री सवारी सुनिश्चित करने के लिए, नोएडा प्राधिकरण ने मास्टर प्लान रोड- II के डिजाइन को मंजूरी दी । एलिवेटेड रोड शहर की सबसे व्यस्त सड़क में से एक है। एलिवेटेड रोड पर हजारों यात्रियों को योजना के कार्यान्वयन से लाभान्वित किया गया , विशेष रूप से सेक्टर - 30, 27, 26, 25, 31, 33, 23, 52, 58 और 61 में। यात्रियों को अब लंबे समय तक प्रतीक्षा का सामना नहीं करना पड़ता है, खासकर व्यस्त समय के दौरान । जब एलिवेटेड स्ट्रेच सिग्नल-फ्री हो जाता है, तो यह DND या कालिंदी कुंज रोड के माध्यम

से गाजियाबाद, हापुड़ और दक्षिणी दिल्ली के बीच आने वाले हजारों लोगों को लाभान्वित करता है।

सेक्टर 30, 27, 26, 25, 31, 33, 23, 52, 58 और 61 में रहने वाले निवासियों को, योजना से सबसे अधिक लाभ हुआ । यह छह लेन की 10.5 मीटर चौड़ी एलिवेटेड रोड सेक्टर 28 में विश्व भारती पब्लिक स्कूल से शुरू होती है और सेक्टर 61/58 के गोल चक्कर के पास फ्लेक्स क्रॉसिंग पर खत्म होती है। सेक्टर 62 क्षेत्र से लगभग एक लाख वाहन गुजरते हैं। एनएच -24 और पूर्वी दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद पहुंचने के लिए यात्रियों का इस्तेमाल होता है। कई सौ वाहन सिटी सेंटर और यूफ्लेक्स मार्ग से फिल्म सिटी से ग्रेटर नोएडा पश्चिम क्षेत्र की ओर भी जाते हैं।

10 किमी एलिवेटेड रोड गाजियाबाद

बहुप्रतीक्षित भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड जिसे सीएम अखिलेश यादव ने लागू किया था |10.3 किलोमीटर लंबी हिंडन एलिवेटेड रोड की प्राथमिक वस्तुनिष्ठता गाजियाबाद से नई दिल्ली तक ट्रैफिक को कम करना है। हिंडन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट सिर्फ भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड होने का दावा नहीं करता , बल्कि यह हकीकत में एक घंटे के सफर को सिर्फ 18 मिनट तक कम करता है|

देश में सबसे लंबी एलिवेटेड रोड का निर्माण नवंबर 2014 में शुरू हुआ था। 227 सिंगल पिलरों पर बनी 10 किलोमीटर छह लेन की सड़क को पूरा करने में तीन साल और चार महीने का समय लगा। शुरुआती दिनों में इस सड़क पर केवल दो और चार-पहिया वाहनों की अनुमति थी ।

यह छह लेन की एलिवेटेड रोड, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आवागमन आसान बनाती है | इसके अलावा, यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) 58 से NH 24 तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। ऐसा अनुमान है कि हर घंटे लगभग 4,000 वाहन इस एलिवेटेड रोड पर खड़े हों सकते हैं |

चार लेन सड़क के साथ जिला मुख्यालय को जोड़ना

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मंत्र: "यदि आप गति को दोगुना कर सकते हैं, तो आप अर्थव्यवस्था को तीन गुना गति प्रदान कर सकते हैं।"

आर्थिक विकास को बाधित करने और उत्तर प्रदेश को भारत के विकसित और औद्योगिक राज्यों की लीग में प्रवेश करने से रोकने वाले मुद्दों में से कुछ जैसे सड़कें, ऊर्जा की कमी, एक कमजोर नीति ढाँचा, और अनुकूल निवेश जलवायु की अनुपस्थिति हैं।

मार्च 2012 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद, समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार ने नई टाउनशिप, मंडियों और विकास समूहों के रूप में, परिधि में वृद्धि को प्राथमिकता देने के लिए सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता पर ले लिया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली चार-लेन की सड़कों के निर्माण कार्य को निर्धारित सीमा के भीतर नदियों पर पुल एवं जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सडको को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया |

"अच्छी सड़कें विकास को गति देने में मदद करती हैं। यादव ने सड़कों और पुलों के निर्माण की समीक्षा के दौरान कहा कि सड़कें न केवल आवागमन के समय को कम करती हैं बल्कि राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी मदद करती हैं।

यादव ने कहा कि सपा सरकार हमेशा अच्छी सड़कों पर जोर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जब हम सत्ता में आए थे, तो हमारी पहली प्राथमिकता सड़कों को सुधारना और नदियों पर पुल का निर्माण करना था। हमने सुनिश्चित किया कि सभी जिला मुख्यालयों को ऑल-सीजन फोर-लेन सड़कों से जोड़ा जाए।"

उन्होंने अधिकारियों को विशिष्ट निर्देश दिए कि वे नवंबर 2016 तक चित्रकूट, अक्टूबर 2016 तक देवरिया, दिसंबर 2016 तक बलरामपुर और मार्च 2017 तक लखीमपुर खीरी, हरदोई और गोंडा को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण करने को कहें।

अक्टूबर तक वाराणसी के बलुआ घाट पर पुल का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए गए थे। बीएचयू के रामनगर के गेट के सामने घाट का नवीनीकरण भी अक्टूबर 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए। यादव ने अधिकारियों को गाजीपुर, बहराइच, मिर्जापुर, फिरोजाबाद और बलिया में पुलों के निर्माण को पूरा करने का भी निर्देश दिया।

"इन सभी को चार-लेन वाली सभी सीज़न सड़कों पर होना चाहिए और निर्दिष्ट समय के भीतर पूरा किया जाना चाहिए,"|

राष्ट्रीय राजमार्ग -24

राष्ट्रीय राजमार्ग -24 के प्रस्तावित कार्य ने अगस्त 2016 में उड़ान भरी। इसे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के रूप में भी जाना जाता है, यह 438 किलोमीटर लंबा राजमार्ग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर और सीतापुर के माध्यम से लखनऊ से जोड़ता है। यद्यपि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में राजमार्ग को तेजी से विकसित किफायती आवास गलियारे के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसके विस्तार की योजना को लगातार ट्रैफिक जाम और सार्वजनिक परिवहन की कमी के मद्देनजर अधिक महत्वपूर्ण माना जाताहै।

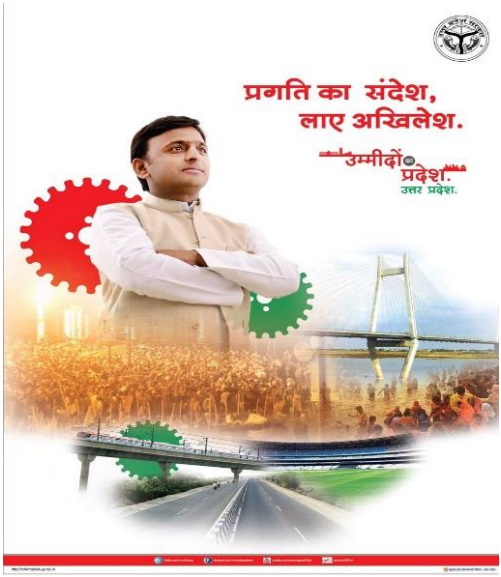

नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 63 के बीच बसे, NH24 ने दिन के सभी घंटों में भारी यातायात का अनुभव किया। पीक ऑवर्स के दौरान, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीड़ चारों ओर से सैकड़ों मीटर लंबी कतारों के साथ बिगड़ जाती, एनएच 24 पर टी-जंक्शन नोएडा से दिल्ली, गाजियाबाद, इंदिरापुरम और मोहन नगर तक जाने के लिए मुख्य प्रवेश मार्ग है। यातायात को आसान बनाने के लिए, नोएडा प्राधिकरण ने NH24 के नीचे एक अंडरपास के निर्माण की योजना बनाई। इस सिग्नल-फ्री अंडरपास का निर्माण 28 फरवरी, 2014 से शुरू हुआ। इस अंडरपास का विकास पूरी तरह से बॉक्स पुश और डायाफ्राम वॉल तकनीक पर निर्भर रहा है। बॉक्स पुशिंग प्रणाली एक

तकनीकी विधि है जिसका उपयोग विशेष रूप से प्रबलित सीमेंट कंक्रीट बक्से के आकार के द्वारा सबवे या अंडरपास के निर्माण के लिए किया जाता है, फिर इसे मैनुअल खुदाई और भारी शुल्क वाले हाइड्रोलिक जैक का उपयोग करके डाला जाता है। नए अंडरपास ने हर दिन नोएडा जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत दी। "अंडरपास ने नोएडा पहुंचने में लगने वाले समय को कम कर दिया। एक नियमित दिन पर, NH24 ने हर दूसरे मिनट में ट्रैफिक जाम का अनुभव किया। स्थिति और खराब हो जाती थी जब विजय नगर से आने वाले वाहन CISF चौराहे पर इंदिरापुरम से आने वाले ट्रैफ़िक में विलय हो जाते थे। CISF क्रॉसिंग और मॉडल टाउन क्रॉसिंग के बीच 150 मीटर लंबे खंड पर लगातार जाम, सेक्टर -63 से बाएं मोड़ से नोएडा की ओर जाने वालों के लिए भी जाम लगा करता। नए अंडरपास ने हर दिन नोएडा जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत दी। "अंडरपास ने नोएडा पहुंचने में लगने वाले समय को कम कर दिया|

एनएच -24 के प्रमुख पहलू

- **लंबाई:** निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होती है दिल्ली और डासना तक जारी है
- **आवास:** कम-मध्य-खंड आवास विकल्प सस्ती संपत्ति की कीमतों पर उपलब्ध हैं
- **समयरेखा:** यह परियोजना ढाई साल में पूरी होती है।
- **परियोजना का दायरा:**87 किलोमीटर की इस परियोजना में छह-लेन एक्सप्रेसवे और 4 + 4-लेन राजमार्ग, सर्विस रोड, साइकिल ट्रैक, फ्लाईओवर, एलिवेटेड सेक्शन, और मामूली पुल, रेलवे ओवरब्रिज, वाहनों के अंडरपास और पैदल मार्ग शामिल हैं।

हाउसिंग मार्केट पर प्रोजेक्ट का प्रभाव

- **किफायती आवास:** NH-24 एक्सप्रेसवे के विकास से किफायती आवास खंडों में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 1-1 और 2-बीएचके श्रेणियों में 15 लाख रुपये से

30 लाख रुपये की कीमत सीमा के भीतर। अलग-अलग बजट में परियोजनाएं खिंचाव के साथ भी उपलब्ध हैं।

- **ट्रैफ़िक:**मार्ग का चौड़ीकरण यातायात परिदृश्य को सुव्यवस्थित करेगा और विशेष रूप से गाजियाबाद से दिल्ली तक आवागमन के समय को कम करना ।
- **कीमतें:** किफायती आवास बाजार की कीमतों में सबसे अधिक सराहना की संभावना है।
- **संभावित लाभार्थी:** परियोजना से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में इंदिरापुरम, वैशाली, नोएडा सेक्टर -62, क्रॉसिंग रिपुबलिक, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, सिद्धार्थ विहार और हाई-टेक और एकीकृत टाउनशिप शामिल हैं। NH-24 एक घनी आबादी वाला मार्ग है और आवास परियोजनाओं की संख्या के साथ-साथ खरीदार भी बढ़ गए हैं।
- **कनेक्टिविटी:** मार्ग ने गाजियाबाद को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान की है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, मेरठ और हापुड़ तक जाता है।

उत्तर प्रदेश में साइकिल ट्रैक

उत्तर प्रदेश में साइकिल ट्रैक, राज्य के क्षेत्रों को साइकिल चालको के अनुकूल बनाने के लिए एक परियोजना है |

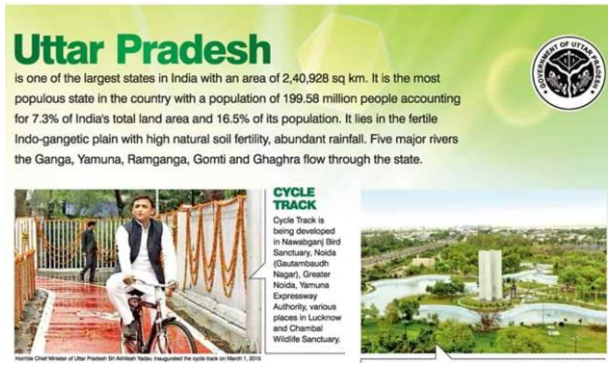

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सितंबर 2014 में एम्स्टर्डम का दौरा किया और देखा कि नीदरलैंड में साइकिल चलाना एक आम तरीका था। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे परिवहन के लिए एक हरियाली दृष्टिकोण लेने के लिए साइकिल गलियारों की योजना बनाएं। लखनऊ में पहले साइकिल ट्रैक का उद्घाटन 1 मार्च 2015 को कालिदास मार्ग में किया गया था।

नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में साईकिल ट्रेक का निर्माण किया गया । नोएडा का लक्ष्य 62.32 किलोमीटर था , जिसमें परियोजना में उन्नयन और 7.4 किमी पुराने साइकिल ट्रैक में सुधार -

शशि चौक से सेक्टर 71 क्रॉसिंग, महामाया फ्लाईओवर से शशि चौक और अन्य सड़कें शामिल हैं।

समाजवादी पार्टी (सपा) का साईकिल के प्रति प्रेम इसे उनके चुनाव चिन्ह के रूप में उपयोग करने से परे है। कार्यालय में अपने वर्षों के दौरान सपा की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य भर के विभिन्न शहरों में कई साइकिल ट्रैक बनाए थे और हमेशा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ एक प्रमुख परियोजना के रूप में इसकी मार्केटिंग की।

समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में सड़कों के साथ साइकिल ट्रैक का निर्माण किया गया था। हालांकि, जब 2017 में भाजपा के योगी आदित्यनाथ राज्य की सत्ता में आए, तो उन्होंने पटरियों को खत्म करने का फैसला किया। सरकार ने शिकायत की कि ये साइकिल ट्रैक यातायात के सुचारू प्रवाह में एक बड़ी बाधा साबित हो रहे थे।

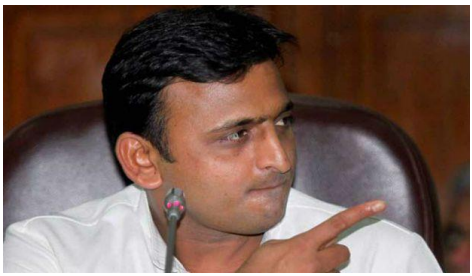

इन साइकिल ट्रैक की परियोजना पर यूपी ने कई बहसें देखी हैं। 2017 में जब योगी सरकार ने उन्हें खत्म करने के इरादे की घोषणा की, तो अखिलेश यादव ने फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और उन्होंने कहा कि सत्ता में लौटने पर, उनकी पार्टी की सरकार साइकिल चलाने को प्रोत्साहित करेगी और राज्य में साइकिल ट्रैक का विस्तार करेगी।

यादव यही नहीं रुके और यह भी वादा किया कि उनकी सरकार फिर से सत्ता में आने के बाद किसी दुर्घटना में मारे गए किसी भी साइकिल चालक को 10 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान करेगी और कहा कि साइकिल के माध्यम से पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाएगा।

भारत का पहला साइकिल राजमार्ग: इटावा से आगरा

वर्ष 2016 में, उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री (अखिलेश यादव) ने इटावा और आगरा के बीच भारत में एक साइकिल राजमार्ग बनाने की योजना की घोषणा की। विकसित देशो में साइकिल राजमार्ग आम हो सकते हैं लेकिन यह हमारे देश में पहला है ।

एशिया का पहला साइकिल राजमार्ग 2016 में उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया था। जो कि इटावा और आगरा के बीच है, यह 207 किलोमीटर लंबा है। इसका निर्माण यूपी लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था और 7 फुट चौड़ा राजमार्ग मुख्य राजमार्ग के समानांतर चलता है। राजमार्ग के साथ, आगरा शहर में ताजमहल, बटेश्वरनाथ मंदिर, राजा-भोज-की-हवेली और नौगावा-का-किला सहित अधिकांश महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण शामिल हैं। यह ट्रैक चंबल और यमुना नदियों के गहरे नालों के साथ-साथ एक सुरम्य दृश्य भी देगा। विशेष रूप से, राजमार्ग आगरा में ताजमहल को इटावा में लायन सफारी से जोड़ता है।

ईको-टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने आगरा में ताजमहल से इटावा में लायन सफारी तक 197 KM लंबा साइकिल राजमार्ग बनाने का निर्णय लिया।

भारत में अपनी तरह का पहला, आगरा-इटावा मुख्य मार्ग के साथ यह साइकिल राजमार्ग कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को कवर करेगा।

ताजमहल के पूर्वी द्वार से शुरू होकर, यह राजा भोज की हवेली, बटेश्वरनाथ मंदिर, मेला कोठी जरार, नौगावा का किला और इटावा में लॉयन सफारी का नेतृत्व करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों सहित पर्यटन स्थलों पर चलेगा। हाइवे पर्यटकों के लिए एक ट्रीट होगा। ताजमहल से लेकर इटावा के शेरों की सफारी तक, वे आगरा और ग्रामीण उत्तर प्रदेश के मनोरम दृश्य का अनुभव करेंगे। इस नई पर्यटन पहल के लिए राज्य सरकार की मंजूरी से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की एक बड़ी संख्या के आकर्षित होने की उम्मीद है।

लखनऊ मेट्रो

यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव से वादा किया था कि परियोजना समय पर शुरू होगी। जैसा कि अखिलेश ने लखनऊ मेट्रो के प्राथमिकता क्षेत्र के काम को शुरू करने के लिए "भूमि पूजन" का आयोजन किया, उन्होंने कहा: "हमने जो वादा किया था, उस पर हमने काम किया है। हमने परियोजना को अनुसूची पर शुरू करने के लिए समय पर भूमि की मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को हटा दिया ।"

सितंबर 2008 में उत्तर प्रदेश की सरकार को लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) द्वारा पहली बार सुझाव दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में जून 2013 में लखनऊ मेट्रो के निर्माण के लिए राज्य ने मंजूरी दे दी।

लखनऊ मेट्रो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक तेजी से पारगमन प्रणाली है जो लखनऊ शहर की सेवा करती है। लाइन का निर्माण 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किलोमीटर (5.3 मील) के साथ शुरू हुआ, जिसने 5 सितंबर 2017 को वाणिज्यिक सेवा शुरू की, जिससे यह देश की सबसे तेजी से विकसित मेट्रो रेल प्रणाली बन गई।

लखनऊ मेट्रो 22 स्टेशनों के साथ 22.87 किमी की दूरी तय करती है। यह दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नम्मा मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, नोएडा मेट्रो और कोच्चि मेट्रो के बाद भारत में आठवां सबसे लंबा परिचालन मेट्रो नेटवर्क है।

लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (LMRC) ने यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पाने में सहायता के लिए 35 ग्राहक संबंध सहायक नियुक्त किए हैं।

एलएमआरसी ने सभी स्टेशनों पर मुफ्त आरओ पेयजल, शौचालय, एस्केलेटर और लिफ्ट की भी व्यवस्था की है।

एक बार पूरा होने के बाद, लखनऊ मेट्रो में 2 लाइनें (1 ए और 1 बी), लंबी लाल (उत्तर-दक्षिण) लाइन होगी, जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंशी पुलिया चौराहा तक 22.87 किमी (14.21 मील) की कुल लंबाई के साथ चल रही है। ब्लू (पूर्व-पश्चिम) लाइन, चारबाग रेलवे स्टेशन से वसंत कुंज तक चलती है। चारबाग रेलवे स्टेशन दो लाइनों के बीच जंक्शन स्टेशन के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, मेट्रो फेज 2 और 3 में 74 किलोमीटर की 6 लाइनें शामिल हैं ।

पुरस्कार

- लखनऊ मेट्रो को दिल्ली मेट्रो के बाद नई दिल्ली में 5 वें वार्षिक मेट्रो रेल शिखर सम्मेलन में 'बेस्ट मेट्रो इन एक्सीलेंस इन इनोवेटिव डिज़ाइन' के लिए दूसरा स्थान दिया गया। इसने देश की अन्य मेट्रो परियोजनाओं जैसे मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो आदि के साथ भी प्रतिस्पर्धा की।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (LMRC) को यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च (ESQR) चॉइस प्राइज अवार्ड 2016 में गोल्ड श्रेणी, एक वैनिटी अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने उत्तर -साउथ कॉरिडोर (चरण 1 ए) के "प्राथमिकता गलियारे" को पूरा करने और तीन साल से कम के रिकॉर्ड समय में परियोजना को चालू करने के लिए मेट्रो रेल श्रेणी में 2017 में डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफ्रा पुरस्कार जीता।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अंतर्राष्ट्रीय 'रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स' (RoSPA) पुरस्कार जीता। LMRC को वर्ष 2018 के लिए प्रोजेक्ट / इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में अपने चरण 1 ए (उत्तर-दक्षिण गलियारे) के लिए रजत पुरस्कार दिया गया।

- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) द्वारा उच्चतम हरी रेटिंग (यानी प्लेटिनम रेटिंग) से प्रमाणित किया गया था।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के पास अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) 14001: 2004 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (ओएचएसएएस) 18001: 2007 आईएसओ और ओएचएसएएस मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन में संगठन के एकीकृत प्रबंधन प्रणाली की मान्यता में प्रमाण पत्र है।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को नवंबर 2017 में हैदराबाद, तेलंगाना में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत 10 वें शहरी मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी और कॉडैटू XVII (CODATU XVII) सम्मेलन के दौरान "बेस्ट अर्बन मास ट्रांजिट" परियोजना से सम्मानित किया गया।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक, कुमार केशव को लखनऊ बुक फेयर के आयोजकों द्वारा 'शान-ए-लखनऊ' पुरस्कार से सम्मानित किया गया और लखनऊ मेट्रो के लोगो, प्रतीक और प्रतीक के रूप में एक विशेष डाक लिफाफा जारी किया गया।
- लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने 15 अक्टूबर 2016 को इनोवेशन ऑन इनोवेशन पर पहला डॉ एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल अवार्ड जीता

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो लिंक की नींव रखी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से नोएडा के सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-V तक 15 किलोमीटर लंबी मेट्रो लिंक की आधारशिला रखी। सीएम ने 3.9 किलो मीटर बॉटनिकल गार्डन-कालिंदी कुंज मेट्रो परियोजना का भी उद्घाटन किया। (हिंदुस्तान टाइम्स, दिसंबर 15, 2016, 16:04 IST)

नोएडा मेट्रो, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत में एक तीव्र पारगमन प्रणाली है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जुड़वां शहरों को जोड़ती है। मेट्रो नेटवर्क में 21 स्टेशनों की सेवा करने वाली एक लाइन (एक्वा लाइन कहा जाता है), जिसकी कुल लंबाई 29.7 किलोमीटर (18.5 मील) है।

सेवाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को, ट्रेनें सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच उपलब्ध होती हैं। 10 ट्रेनों के बेड़े का उपयोग करके सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 163 यात्राएं की जाती हैं और पीक आवर्स के दौरान आवृत्ति 10 मिनट (8:00 -11:00 am और शाम 5:00 PM -8:00 PM) और ऑफ-पीक के दौरान 15 मिनट होती है। शनिवार और रविवार को आवृत्ति 10 मिनट है।

नोएडा मेट्रो भारत में स्थापित होने वाली 11 वीं मेट्रो प्रणाली है, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के बाद दूसरी है। दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, नम्मा मेट्रो और कोलकाता मेट्रो के बाद, यह भारत में छठा सबसे लंबे समय तक चलने वाला

मेट्रो नेटवर्क है। NMRC परियोजना के लिए नींव अक्टूबर 2014 में रखी गई थी, जिसके निर्माण की शुरुआत दिसंबर 2014 के अंत तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा की गई थी।

सेक्टर 62-सिटी सेंटर मेट्रो

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि दोनों मेट्रो मार्गों को 30 सितंबर, 2014 को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आधिकारिक मंजूरी मिली थी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) और नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों ने दो मेट्रो लिंक के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए- नोएडा सिटी सेंटर से सेक्टर 62 और नोएडा सिटी सेंटर से ग्रेटर नोएडा |

लखनऊ में एक कैबिनेट बैठक में, अखिलेश ने नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना के लिए नोएडा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सीईओ रामकरण को अधिकृत किया |

नोएडा में टीपीसी मेट्रो को मंजूरी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दी गई तीन महीनों में दूसरी थी । जून 2014 में उन्होंने 3.9 किमी, के बॉटनिकल गार्डन कालिंदी कुंज मेट्रो लिंक को मंजूरी दी थी। नोएडा-ग्रेटर नोएडा लाइन को दो प्राधिकरणों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिटी सेंटर से सेक्टर 62 की लाइन सेक्टर 32, 34, 35, होशियारपुर, सेक्टर 51, 52, 71, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन मार्ग, सर्फाबाद, सेक्टर 60, 61, 62, 63 और एनएच -24 से कनेक्टिविटी प्रदान करती है।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो ट्रैक ने नोएडा में सेक्टर 50, 51, 78, 101, 81, दादरी रोड, 83, 85, 137, 142, 143, 144, 147, 153 और सेक्टर 149 से कनेक्टिविटी प्रदान की है।

BIG NUMBERS
NOIDA CITY CENTRE TO GREATER NOIDA
Length | 29.7km
Cost | ₹5,604cr
Deadline | 2017
NOIDA CITY CENTRE TO SECTOR 62
Length | 6.7km
Cost | ₹1,816cr
Deadline | 2017

गाजियाबाद नया बस अडडा मेट्रो

उत्तर प्रदेश सरकार (सीएम अखिलेश यादव) ने जून 2014 में गाजियाबाद में दिलशाद गार्डन से न्यू बस स्टैंड तक प्रस्तावित 9.41 किलोमीटर लंबे मेट्रो विस्तार को मंजूरी दी। जीटी रोड पर एक ऊंचे खंड पर एक लाख से अधिक यात्रियों को गाजियाबाद के शहीद नगर, शालीमार गार्डन, राज नगर, राज नगर एक्सटेंशन, सियानी, मोहन नगर और अर्थला क्षेत्रों के निवासियों के लिए दिल्ली को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की। इस मेट्रो कॉरिडोर में सात मेट्रो स्टेशन हैं - शहीद नगर, राज बाग, राजेंद्र नगर, श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला और न्यू बस अडडा।

इस नए कारिडोर के बारे में जानने के लिए यहां कुछ बातें बताई जा रही हैं जो दिल्ली मेट्रो के गाजियाबाद के अंदरूनी हिस्सों को चिह्नित करती हैं:

- यह खंड 25.09 किलोमीटर रिठाला-दिलशाद गार्डन कॉरिडोर या रेड लाइन का विस्तार है, जिसमें 21 स्टेशन हैं। इस खंड के खुलने के बाद, दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 244 मेट्रो स्टेशनों के साथ 336.5 किमी है।
- नए एलिवेटेड सेक्शन में आठ स्टेशन शामिल हैं- शहीद नगर, राज बाग, राजेंद्र नगर, श्याम पार्क, मोहन नगर, अर्थला, हिंडन रिवर स्टेशन और न्यू बस अडा।
- दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अनुसार, इसका निर्माण एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि यह व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर चलती है, जो पूरे दिन लगातार यातायात देखती है। इसलिए अधिकांश निर्माण गतिविधियों को 4-5 घंटे से अधिक रात में करना पड़ता था।

- दिलशाद गार्डन (दिल्ली) से नई बस अडडा तक की कुल यात्रा में लगभग 16 मिनट लगेंगे और महानगरों में छह घंटे और बारह सेकंड की पीक-टाइम फ्रीक्वेंसी उपलब्ध होगी। डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक, अनुज दयाल ने कहा, "पूरे रिठाला-न्यू बस अडा रेड कॉरिडोर पर कुल 35 छह-कोच वाली ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा।"

- इस नए कॉरिडोर के साथ छह स्टेशन - शहीद नगर और हिंडन नदी को छोड़कर - राजमार्ग के दोनों ओर स्टेशन भवनों के साथ विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए हैं। प्लेटफ़ॉर्म प्रत्येक स्टेशन बिल्डिंग से जुड़े होते हैं, दोनों ओर फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) की मदद से।
- हिंडन नदी को छोड़कर, इन सभी स्टेशनों पर संघटक स्तर पर एफओबी को भुगतान किया गया है और अवैतनिक वर्गों में विभाजित किया गया है - जिसका उपयोग क्रमशः मेट्रो यात्रियों द्वारा प्लेटफॉर्म और आम जनता तक सड़क पार करने के लिए किया जाता है।
- हिंडन नदी स्टेशन एकमात्र मानक है जिसमें एकल इमारत और उसके अंदर का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर एफओबी मेट्रो यात्रियों और आम जनता दोनों के लिए आम है। यह एकमात्र स्टेशन है जहां संरेखण सड़क से हट गया है।
- 2014 की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, इस मार्ग पर दैनिक सवारियों की संख्या 1.2 लाख होने की उम्मीद है। इसके अलावा, नया बस अडडा स्टेशन 50,000 यात्रियों के फुटफॉल के साथ सबसे व्यस्ततम है।
- दिल्ली से वैशाली को जोड़ने वाली ब्लू लाइन के बाद गाजियाबाद में यह दूसरी मेट्रो लाइन है। नया खंड साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र से होकर गुज़रता है और निकटता में पड़े आवासीय क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

बस सेवा पहले मॉडल स्टेशन के साथ हाई-टेक हो जाती है..

शहर को कैसरबाग में एक हवाई अड्डे जैसा मॉडल बस स्टेशन मिला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो मंजिला बस स्टेशन को लोगों को समर्पित किया।

उन्होंने इस अवसर पर दस मार्गों पर गांवों और साधारण बस सेवाओं के साथ कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए लोहिया बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। नई सेवाएं चारबाग और कैसरबाग बस स्टेशनों से लखनऊ-हरदोई-सांडी, लखनऊ-मल्लावां-कन्नौज, लखनऊ-बहराइच, लखनऊ इटावा-आगरा-जयपुर, लखनऊ - शाहगंज-आज़मगढ़, लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद और लखनऊ-कानपुर-औरैया-इटावा रूट पर संचालित होंगी।

राज्य का पहला मॉडल बस स्टेशन यूपी राजकीय निर्माण निगम द्वारा विकसित किया गया है। यात्रियों को पूरी तरह से वातानुकूलित यात्री शेड में प्रवेश करने की अनुमति दी गई । जबकि, छह एलईडी स्क्रीन यात्रियों को विभिन्न बस सेवाओं के बारे में जानकारी के लिए अद्यतन करेंगी ।

इस स्टेशन से 800 से अधिक बस सेवाएं संचालित होंगी जो 40Kva सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ सौर ऊर्जा-सक्षम है।

बस स्टेशन की इमारत में पहली मंजिल पर एक कैफेटेरिया है, जिसमें यात्रियों को बस समय और स्थिति के बारे में सचेत करने के लिए स्क्रीन है। 32 सीसीटीवी कैमरों के साथ हाई-टेक स्टेशन परिसर का ऐतिहासिक जुड़ाव है। इसके स्तंभों को शहर के स्मारकों जैसे बाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, लोक भवन, विधान भवन, चारबाग रेलवे स्टेशन और घंटाघर के चित्रों के साथ चित्रित किया गया है। स्टेशन में हाईएंड बस सेवाओं के यात्रियों के लिए एक अलग प्रतीक्षालय है।

आठ दुकानों और एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और एक एटीएम के साथ एक शॉपिंग आर्केड है।

एक अलग प्रवेश और निकास, यहां तक कि अलग-अलग एबल्ड के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगा। स्टेशन के पास एक भूमिगत पार्किंग है और छोटी कारों को सीधे पोर्च तक ड्राइव करने की अनुमति होगी।

दिल्ली की तुलना में नोएडा में अधिक उच्च तकनीक वाली बसें शुरू की गईं

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से उद्घाटन किया, नोएडा की सड़कों पर दौड़ीं 50 हाई-टेक बसें

दिल्ली की बसों में भले ही सीसीटीवी नहीं लगा हो, लेकिन अब नोएडा में सीसीटीवी से लैस बस का संचालन शुरू हो गया है, जैसे ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से उद्घाटन किया, 50 हाई-टेक बसें नोएडा की सड़कों पर दौड़ गईं। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने नोएडा ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया, जिसके साथ 50 लो फ्लोर सिटी बसें सड़क पर आ गई हैं। अब आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक बहुत कम किराया में यात्रा कर सकते हैं।

नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक संतोष यादव ने कहा कि इतने सारे फीचर्स वाली इस बस का किराया भी बहुत कम है, इस पूरी तरह से वातानुकूलित बस का किराया 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे लखनऊ से लॉन्च किया

सैदपुर पुल का उद्घाटन

यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने अपने आवास से गाजीपुर में बने गंगापुल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिज कॉर्पोरेशन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कई लोग पूछते थे कि यह पुल कब बनेगा। यह पुल बनाया गया है, अब लोगों को आसानी होगी और साथ ही क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सैदपुल लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था और अब हमारे पास इसका उद्घाटन करने का मौका मिला है।

यह पुल गंगा नदी पर बना है। ब्रिज का निर्माण ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। वहीं, इसकी लंबाई 1755 मीटर है। अखिलेश ने पुल के निर्माण के लिए ब्रिज कॉर्पोरेशन को भी बधाई दी।

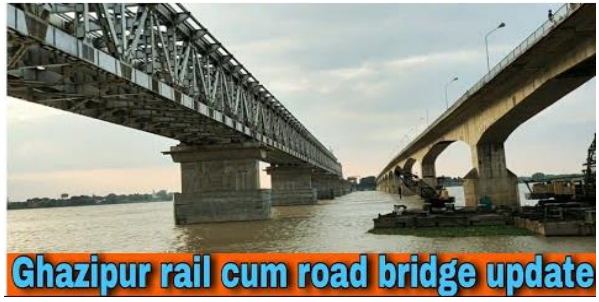

अखिलेश ने रिलीज के मौके पर कहा कि लोग कहते थे कि सैदपुर का पुल कब बनेगा। अब इसे बनाया गया है ।- इस पुल का काम सालों से रुका हुआ था। सपा सरकार ने इस पुल का निर्माण कराया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई पुल

बनाए गए थे। अब यह पुल लोगों की समस्याओं को दूर करेगा। - पुल नए डिजाइन के अनुसार बनाया गया है। यूपी सरकार ने रिकॉर्ड समय में एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया। इंजीनियरों ने बहुत अच्छा काम किया है। इस विभाग का नाम बहुत बड़ा है, यह विभाग ऊंचा होना चाहिए।

श्री यादव ने कहा कि लोग सड़कों और पुलों के अच्छे नेटवर्क से लाभान्वित होते हैं। वे समय और आर्थिक परिवर्तनों को बचाते हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि अधूरे पुलों का निर्माण तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय के साथ, प्रौद्योगिकी और डिजाइन के स्तर पर निर्माण संबंधी कार्य बदल गए हैं, जिन्हें अपनाकर हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं।

5 करोड़ वृक्षारोपण

अखिलेश सरकार ने एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाकर अपने हरित सपने को पूरा किया

10:00 पूर्वाह्न, 11 जुलाई, 2016 से शुरू होने वाले 24 घंटे बहुत ही नेक काम के लिए सभी की याद में रहेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया, जिसमें इन 24 घंटों में राज्य भर में 6000 से अधिक स्थलों पर 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए । यह पहल ग्रीन यूपी क्लीन यूपी अभियान के तहत की गई।

हमारे सांसदों की प्राथमिकता सूची में यह उच्च पर्यावरणीय संरक्षण था। लेकिन अफसोस! हमारे चुने हुए अधिकांश प्रतिनिधि क्षुद्र प्रचार स्टंट, शब्दों का केवल खेल, मुद्दों पर मनमुटाव और झगड़े पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत व्यस्त हैं, जो आम आदमी की चिंता नहीं करते हैं। लेकिन सबने उम्मीदें नहीं खोई हैं। यहां भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पर्यावरण

को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से लोगों और आने वाली पीढ़ियों पर एक ठोस प्रभाव बनाने के लिए दृढ़ संकल्प किया।

"हम एक हरे रंग की विरासत बनाएंगे।" - अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

छात्रों, सांसदों, सरकारी अधिकारियों, गृहिणियों और स्वयंसेवकों सहित 800,000 से अधिक लोगों ने देश की सड़कों और राजमार्गों, रेल पटरियों और वन भूमि के साथ नामित स्थानों पर पौधे लगाने के लिए अच्छी तरह से प्रचार अभियान में भाग लिया। राज्य के 85 वन प्रभागों में 81,000 हेक्टेयर में 6,166 स्थलों पर वृक्षारोपण किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने ड्राइव के हर मिनट को ठीक उसी समय से फिल्माया, जब वन विभाग ने फरवरी के अंत में पेड़ लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई शुरू की थी। 11 जुलाई को प्रत्येक साइट पर वृक्षारोपण का टीम द्वारा फोटो और शूट किया गया था। वृक्षारोपण के लिए प्रारूप और ले-आउट योजना गिनीज और वन विभाग द्वारा दी गई थी। इस कार्य ने राज्य को 24 घंटे के भीतर 11 जुलाई को 5.5cr पेड़ लगाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने में मदद की ।

डिजिटल सीएम अखिलेश यादव ने इस अभियान को बड़ी सफलता दिलाने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ अपनी हरी विरासत को जोड़ा । वास्तव में, मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति, आदि के आधार पर वैज्ञानिक वृक्षारोपण पद्धति का पालन किया गया, और वृक्षारोपण के वास्तविक समय के निरीक्षण के लिए एंड्रॉइड मोबाइल ऐप का उपयोग किया । इस पहल को सक्रिय रूप से वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली और नर्सरी प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने के लिए नियोजित किया, ये प्रकिया वृक्षारोपण की पहुंच, प्रभावशीलता और दक्षता को अधिकतम करती है।

यही नहीं, पूरा अभियान एक कागज रहित पहल था । यह देखकर खुशी होती है कि कर दाताओं की गाढ़ी कमाई को एक ऐसे कारण के रूप में निवेश किया गया जो आज के साथ-साथ आने वाले कई पीढ़ियों के लिए भी फल देगा।

वृक्षारोपण अभियान में तीसरे पक्ष की एजेंसियों की भागीदारी भी है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान (TERI), स्थिरता की दिशा में काम करने वाली सबसे बड़ी विकासशील देश संस्था है, जिसने वृक्षारोपण के लिए किए गए मिट्टी के काम की निगरानी की । केपीएमजी द्वारा ड्राइव का ऑडिट भी किया गया । अखिलेश यादव जी की सरकार ने इस पहल को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी |

दरअसल, राज्य में जल आरक्षित और नदियों को पुनर्जीवित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार की यह पहली पहल नहीं थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरिया की राजधानी सियोल में पानी की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान `प्लाक ऑफ एप्रिसिएशन' प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त, वन महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वन ई-लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया और राज्य पक्षी 'सरस' पर एक फिल्म का अनावरण किया। अन्य राज्यों के नेताओं को यूपी के सीएम अखिलेश यादव का उदाहरण देना चाहिए।

55 लाख पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जनवरी 2014 को "समाजवादी पेंशन" योजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य राज्य के 55 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ देना था।

समाजवादी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड में शामिल हैं:

1.) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला कोई भी परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

2.) परिवार उत्तर प्रदेश में स्थित होना चाहिए।

3.) उत्तर प्रदेश में निवास का वैध प्रमाण आवश्यक है।

4.) मुख्य लाभार्थी के पास एसबीआई या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ एक बैंक खाता होना चाहिए।

यह योजना रु500 की मासिक पेंशन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रदान करती है । पेंशन राशि वित्तीय वर्षों में 50 रु बढ़ जाती है. समाजवादी पेंशन योजना द्वारा दी जाने वाली अधिकतम पेंशन सीमा रु .750 प्रति माह है। परिवारों का चयन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए बनाई गई । उत्तर प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक खाता अनिवार्य है। पेंशन का भुगतान एक परिवार के मुखिया को किया जाएगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाता है।

समाजवादी पेंशन योजना ऑनलाइन उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के सभी जिले इस योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसटी / एससी समूह से 12 लाख परिवार, 10 लाख अल्पसंख्यक समूह और सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से 18 लाख परिवारों को शामिल करने का फैसला किया। समाजवादी पेंशन योजना मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की श्रेणियों के लिए लक्षित है।

लगभग 55 लाख परिवार इस योजना के अंतर्गत आते हैं। शुरुआत में 40 लाख परिवारों को शामिल करने की योजना थी। योजना का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि राशि सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित की जाती है। इससे शून्य भ्रष्टाचार हुआ है और इसलिए यह राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद तबके की मदद करने में बहुत प्रभावी है। यह अखिलेश जी की अब तक लॉन्च की जाने वाली सबसे लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है।

सीएम अखिलेश ने किया अवध शिल्प ग्राम का उद्घाटन

शनिवार, 20 अगस्त 2016 | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को राज्य की राजधानी में 'अवध शिल्प ग्राम' का उद्घाटन किया और कारीगरों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा करने के अलावा उनकी समाजवादी पार्टी सरकार की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

परियोजना को राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शिल्पों और मध्यम, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के कारीगरों को वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया । लखनऊ हाट परियोजना के तहत, अवध शिल्प ग्राम परियोजना का निर्माण 20 एकड़ के क्षेत्र में किया गया था ताकि शिल्पकारों को उनके उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और युवा रोजगार के नए रास्ते खोलने के साथ-साथ हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। अवध शिल्प ग्राम में वातानुकूलित और गैर-एसी दुकानें हैं, जिनमें 209 की संख्या के साथ अलग-अलग पुरुषों और महिलाओं के डॉर्मिटरी में आने वाले कारीगरों के ठहरने की व्यवस्था है। फूड-कोर्ट; अवध शिल्प ग्राम में डॉरमेट्री के साथ-साथ क्राफ्ट कोर्ट और प्रदर्शनी हॉल का निर्माण किया गया था। फूड-कोर्ट; अवध शिल्प ग्राम में डॉरमेट्री के साथ शिल्प

दरबार और प्रदर्शनी हॉल बनाया गया । उन्हें बाहरी उद्यमियों की सुविधा के लिए साइन-बोर्ड लगाने के लिए निर्देशित किया गया था।

शिल्प ग्राम का 20 एकड़ का विशाल परिसर दुकानों का एक विशाल परिसर है जहाँ राज्य भर के कारीगर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर सकते हैं। लाल पत्थर में निर्मित, 'हाट' ने इसके उद्घाटन के दिन हजारों लोगों को वहां आते देखा। मुख्यमंत्री ने कारीगरों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनके विकास और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने घोषणा की कि उनके लिए कई कल्याणकारी पहल जल्द ही राज्य द्वारा शुरू की जाएंगी।

अमूल डेयरी प्लांट स्थापना: कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, सैफई

अखिलेश यादव सरकार ने राज्य में कई स्थानों पर अमूल मिल्क प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया |

दूध और इसके मिश्रित उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक - अमूल - राज्य सरकार द्वारा सुल्तानपुर रोड पर चक गंजरिया खेत की 20 एकड़ जमीन पर 200 करोड़ रुपये की आधुनिक डेयरी स्थापित करने के लिए चुना गया ।

इस पहल के तहत, प्रति दिन 5 लाख लीटर दूध की क्षमता वाली चार इकाइयां स्थापित करने का निर्णय लिया गया । इन इकाइयों की स्थापना सुल्तानपुर मार्ग पर चकजारिया में, कानपुर ग्रामीण के जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में, वाराणसी जिले में वाराणसी-भाग्यवार्ता मार्ग पर हवाई अड्डे के पास और जिला इटावा में सैफई में की गई ।

इन परियोजनाओं से लाखों किसान सीधे लाभान्वित हुए । दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध की उचित दरें मिलेंगी और उपभोक्ताओं को बिना पोषण वाले दुग्ध उत्पाद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुग्ध उत्पाद संयंत्र लगभग 150 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ स्थापित किया जाएगा और अप्रत्यक्ष रोजगार के अलावा, 20,000 नई नौकरियों का सृजन होगा, लगभग 7 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित होने की उम्मीद है, एक बार में सभी चार इकाइयां स्थापित हो जाएंगी ।

योजना के अनुसार, राज्य सरकार की कामधेनु योजना के समन्वय में, प्रत्येक इकाई के आसपास के 100 किलोमीटर के गांवों में दूध संग्रह केंद्र स्थापित करेगी। किसान इन संग्रह केंद्रों पर अपना दूध बेच सकेंगे जिसके लिए उन्हें नकद भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को सालाना बोनस के रूप में अर्जित लाभ का एक हिस्सा दिया जाएगा। इसके बाद पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र सहित राज्य के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में बड़े कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई गई ।

स्थिति:

कानपुर और लखनऊ में संयंत्रों का संचालन किया गया है। एक साथ प्लांटो में लगभग दस लाख लीटर दूध प्रसंस्करण क्षमता होगी। यूपी में अखिलेश सरकार ने डेयरी विकास के लिए अमूल को आमंत्रित करने के बाद, बनास डेयरी ने कानपुर में 40 एकड़ भूमि और लखनऊ में 20 एकड़ भूमि पर डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिग्रहण किया। कामधेनु योजना के कारण दुग्ध उत्पादन में वृद्धि प्रमुख वृद्धि है और पूरे यूपी में इतने सारे डेयरी संयंत्र स्थापित करने का एक कारण है। दुग्ध विकास के लिए एक किसान प्रशिक्षण केंद्र सफई में चार एकड़ में स्थापित किया गया है।

आजमगढ़ चीनी मिल

अखिलेश यादव ने 22 मार्च 2016 को सठियांव (आजमगढ़) में चीनी मिल का उद्घाटन किया

चीनी मिल नहीं चल पाई, लेकिन अखिलेश सरकार ने इसे चलाकर दिखाया। इस कदम से किसानों को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मार्च 2016 को सठियांव चीनी मिल और 15 मेगावॉट के एक को-जेनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। 338 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक प्लांट और मशीनरी के साथ मिल का नवीनीकरण किया गया। उसी परिसर में चीनी मिल का नवीनीकरण किया गया है। मिल में एक डिस्टिलरी यूनिट और 15 मेगावाट क्षमता का सह-उत्पादन बिजली संयंत्र भी है। मिल की पेराई क्षमता 3,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी।

सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रस्तावित मिल, पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी पुरानी चीनी मिल को समाप्त करने के बाद आएगी। महत्वाकांक्षी परियोजना में न केवल प्रतिदिन 3,500 टन क्रशिंग (TCD) की एक मिल स्थापित करना शामिल है, बल्कि 5,000 TCD क्षमता तक की-बल्कि 15MW पॉवर प्लांट की स्थापना भी शामिल है। डिफंक्शन मिल की क्रशिंग क्षमता केवल 12,500 TCD थी। नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए बंद मिल की भूमि को पर्याप्त पाया गया । 2014 में इस परियोजना के लिए सरकार ने प्रारंभिक सर्वेक्षण किया था। आसपास के गाँव जो मिल को गन्ना प्रदान करेंगे, का भी सर्वेक्षण किया गया था। सह चीनी कारखाने -ऑपरेटिव सेक्टर का निर्माण 1975 में किया गया था और पिछले एक दशक से बंद था।

भूमि सेना योजना

उत्तर प्रदेश में राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 8 अगस्त 2013 को भूमि सेना योजना शुरू की गई थी। यह योजना 5, कालिदास मार्ग, लखनऊ में बंजर, (क्षारीय मिट्टी) और उबड़-खाबड़ भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए आयोजित एक समारोह में शुरू की गई थी। इस योजना से राज्य में खेती के क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली |10-14 जिलों में क्लस्टर दृष्टिकोण बनाकर 44000 हेक्टेयर बंजर और उबड़-खाबड़ जमीन को उपयोगी बनाने के उद्देश्य से 2013-14 के वित्तीय वर्ष के लिए यह योजना शुरू की गई थी।

2012-13 के दौरान राजकोषीय बाढ़ से प्रभावित, ऊबड़-खाबड़, बंजर जमीनों का लगभग 35000 हेक्टेयर उपयोग करने के लिए दुरुस्त किया गया और खेत के काम के लिए इसे बहाल किया गया । इसने 50 करोड़ के निवेश पर लगभग 70000 सीमांत और औसत किसानों को लाभान्वित किया।

इस योजना में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं

- लघु और सीमांत किसानों की भूमि, छोटे और सीमांत किसानों की भूमि भू-सेना की योजना के तहत उनकी भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ आय में वृद्धि और उनके परिवार के खाद्यान्न की उपलब्धता का उपचार।

- वानिकी / कृषि वानिकी, बागवानी आदि के क्षेत्र कवरेज को बढ़ाने के लिए भूमि सैनिकों के माध्यम से खेती योग्य भूमि का उपचार।
- जल कृषि के लिए तालाबों का पुनर्निमाण यानी मत्स्य और सिंघाड़ा की खेती और जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर में सुधार।
- जब भी आवश्यक हो, वांछित प्रशिक्षण देकर भूमि, और जल प्रबंधन, जल संचयन, लघु सिंचाई, गाद की सफाई, आपदा प्रबंधन, वानिकी के लिए वांछित प्रशिक्षण देकर एक संगठित, अनुशासित और सक्रिय बल के रूप में भूमि सेना का गठन। प्रत्येक घर में एक वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का रोजगार।

मजदूरों को सीएम अखिलेश का तोहफा, समाजवादी थाली 10 रुपये में और शुरू की पेंशन योजना

यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस पर मजदूरों को एक हजार रुपये महीने की पेंशन देने की घोषणा की और 10 रुपये में समाजवादी थाली की सुविधा भी शुरू की । सीएम ने मजदूरों के बीच एक हजार साइकिलें भी बांटी ।

योजना के तहत श्रमिकों को सरकार की ओर से हर महीने एक हजार रुपये पेंशन के रूप में दिए गए । इस अवसर पर, अखिलेश ने कहा कि पेंशन योजना से श्रमिकों को लाभ होगा और वे अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकेंगे। मजदूर दिवस, अखिलेश यादव मजदूरों के साथ बैठे और जमीन पर बैठकर खाना खाया। अखिलेश विधान सभा के सामने पहुँचे और वहाँ उन्होंने मध्याह्न भोजन योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के नए भवन में काम करने वाले मजदूरों को पहले दिन मुफ्त भोजन दिया गया। खुद सीएम ने भी मजदूरों के साथ भोजन किया। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने कड़ी धूप में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत मजदूरों को अब 10 रुपये में एक थाली मिलेगी।

लखनऊ में ड्राइवरों को ई-रिक्शा बांटते सीएम अखिलेश यादव

लखनऊ, 20 अगस्त 2015 : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में रिक्शा चालकों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में उन्हें मुफ्त ई-रिक्शा वितरित किए। लोगों को संबोधित करते हुए, अखिलेश ने कहा कि मुफ्त ई-रिक्शा का वितरण राज्य के समग्र विकास के लिए उनकी सरकार का एक और प्रयास था।

सीएम ने ट्राइसिकल रिक्शा के स्वामित्व वाले खींचने वालों को 100 बैटरी चालित ई-रिक्शा दिए। लाभार्थियों को लखनऊ, कन्नौज, रामपुर, इटावा और आजमगढ़ सहित 10 जिलों से चुना गया था।

यूपी सरकार योजना के पहले चरण में 27,000 ई-रिक्शा वितरित की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की।

सीएम अखिलेश यादव ने विशेष रूप से विकलांग बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित की

'विश्व विकलांगता दिवस' के अवसर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में विशेष रूप से विकलांग बच्चों को ट्राई साइकिल वितरित की। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित किया गया था, जहां बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उपहार भी दिए गए ।

सीएम अखिलेश ने कार्यक्रम में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को त्रि-चक्र वितरित किया। कार्यक्रम में सीएम अखिलेश ने अलग-अलग अंग वाले कृत्रिम अंग भी वितरित किए।

मुख्यमंत्री अखिलेश ने लगभग 30 दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए।

16 साल बाद, दिव्यांग के लिए राज्य-स्तरीय पुरस्कार में 16 हजार रुपये की वृद्धि की गई । अब राज्य स्तर के पुरस्कारों में 21 हजार रुपये नकद अलग-अलग तरह से दिए गए ।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर पुरस्कार राशि को 16,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। पुरस्कार राशि को 16 साल बाद बढ़ाया गया ।

सीएम ने यहां कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पांच दिव्यांगों को व्हील चेयर, 10 को श्रवण यंत्र, 15 को ट्राई साइकिल और आठ को बैसाखी वितरित की। कार्यक्रम में विकलांग विकास मंत्री साहेब सिंह सैनी ने कहा कि सपा सरकार 18 साल से कम उम्र के बच्चों या उनके माता-पिता को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ दे रही है। वहीं, कुष्ठ रोगियों को 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की योजना शुरू की गई है।

सीएम अखिलेश द्वारा साइकिल वितरण और मध्याह्न भोजन योजना

2013 में, सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में लगभग तीन लाख मजदूरों को मुफ्त साइकिल वितरित करने की योजना शुरू की थी। जिन लोगों को लाभ के लिए पात्र बनाया गया था, उनमें कारखाने के श्रमिक, उद्योग के मजदूर, राजमिस्त्री, बढ़ई जैसे कुशल मजदूर शामिल थे, जो श्रम विभाग में पंजीकृत हैं। छात्रों को मुफ्त लैपटॉप वितरित करने के बाद, अखिलेश यादव सरकार ने अब राज्य में लगभग 3 लाख मजदूरों को मुफ्त साइकिल वितरित की।

दिलचस्प बात ये है कि साईकिल समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है । कारखाने के श्रमिक, उद्योग के मजदूर, राजमिस्त्री के रूप में कुशल श्रमिक, बढ़ई, यांत्रिकी, जो श्रम विभाग के साथ पंजीकृत हैं, फ्रीबी के लिए पात्र होंगे।

श्रम विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 2,92,632 पंजीकृत मजदूर हैं। एक चक्र की औसत लागत लगभग 2,500 रुपये होने की उम्मीद है। इस प्रकार, इस योजना की लागत लगभग 7.5 करोड़ रुपये हो सकती है। तीन प्रमुख साइकिल निर्माताओं, अर्थात् हीरो साइकिल, एटलस और हरक्यूलिस ने राज्य सरकार को साइकिल की आपूर्ति में रुचि दिखाई है।

मजदूर दिवस पर अखिलेश यादव ने मजदूरों को तोहफा दिया । उन्होंने इस अवसर पर कई योजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर एक समारोह में मजदूरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उन्हें एक हजार साइकिल वितरित की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों के साथ खाना भी खाया।

सीएम ने दिया ये तोहफा ...

- श्रमिकों को अब श्रम विभाग से पेंशन मिलेगी, जो 60 वर्ष के हैं और जो पहले से ही श्रम विभाग के साथ पंजीकृत हैं। पेंशन राशि हर महीने 1000 रुपये होगी। यह अधिकतम 1250 रुपये तक बढ़ सकता है।

सीएम ने कार्यक्रम में पेंशन पत्र भी दिए।

- अब साइट्स पर काम करने वाले मजदूरों को 10 रुपये में पूरा लंच मिलेगा।

हालांकि, सीएम चाहते थे कि इसे मुफ्त दिया जाए, लेकिन यह संभव नहीं था।

उन्होंने कहा कि हमने राज्य में 4 लाख से अधिक साइकिलें वितरित की हैं और उन्हें अभी भी वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक को 1000 रुपये पेंशन का भुगतान करने जा रहे हैं।

यही नहीं, हमने 5 लाख महिलाओं को पेंशन भी दी है। खास बात यह है कि यह पैसा सीधे उनके खाते में जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है।

-सरकार हर चीज पर ध्यान दे रही है, चाहे वह खाने-पीने की व्यवस्था हो या सामाजिक सुरक्षा। सरकार ने हर दिशा में काम किया है।

-अखिलेश यादव ने श्रम विभाग के अधिकारियों और मंत्री को भी बधाई दी।

मिड-डे मील मेनू

श्रमिकों के दोपहर के भोजन में दो प्रकार के मेनू रखे गए। इसमें केवल उन्हीं मजदूरों को शामिल किया गया जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड से जुड़े थे । पहले मेनू में 6 रोटियां, 2 सब्जियां, गुड़, सलाद, अचार और मिर्च शामिल थे । इसी समय, दूसरे मेनू में दाल, चावल (400 ग्राम), गुड़, सलाद, अचार और मिर्च शामिल थे ।

अखिलेश यादव ने मजदूरों के साथ खाना खाया - सीएम विधानसभा के सामने निर्माणाधीन नए सचिवालय भवन में पहुंचे। जब वह मजदूरों के बीच पहुंचे तो उनका

मूड काफी अच्छा था। वहां पहुंचते ही सीएम मजदूरों के साथ कालीन पर बैठ गए । इसके बाद, अधिकारियों ने सीएम सहित सभी मजदूरों को टिफिन वितरित किया।- अखिलेश ने पास में बैठे मजदूर सुमन लता से पूछा, तुम्हें खाना कैसा लगा, तो उसने कहा- यह बहुत अच्छा है सर ।- सुमनलता ने dainikbhaskar.com को बताया कि यह पहली बार है कि राज्य के सीएम ने हमारे साथ भोजन किया है।

बीज सब्सिडी के लिए यूपी का डीबीटी (DBT) मॉडल

उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन में एक निर्णायक के रूप में बदल रही थी ।

2014-15 के पेराई सत्र के दौरान मिलों को आपूर्ति किए गए गन्ने के लिए यूपी में किसानों को राज्य सरकार से 28.60 रुपये प्रति क्विंटल मिला। 2,127.25 करोड़ रुपये का भुगतान, उनके उत्पादकों की मिलों द्वारा प्रदान की गई सूचियों के आधार पर किया गया, जो गन्ने की मात्रा के साथ थी।

यह जानकारी - जिला गन्ना अधिकारियों और सहकारी समितियों द्वारा सत्यापित की गई जिनके माध्यम से खरीद की गई - का उपयोग उत्पादकों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भुगतान करने के लिए किया गया।

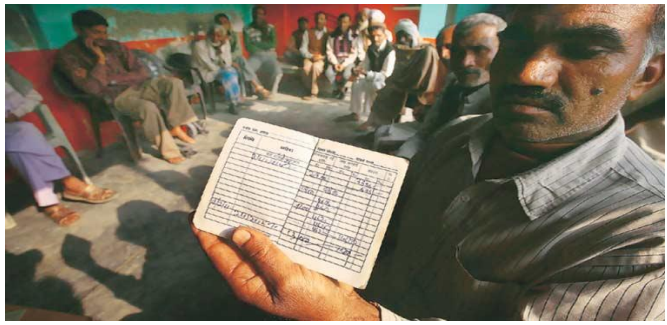

मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील के छजलेट गाँव के एक 12 बीघा (दो एकड़) के किसान ज़हीर अहमद ने 15 नवंबर को उत्तर प्रदेश के उच्च-उपज वाले एचडी - 2967 गेहूं के विभिन्न प्रकार के बीज के दो 40-किलोग्राम बैग खरीदे। कृषि विभाग के स्थानीय बीज भंडार, उसे 2,400 रु। 26 नवंबर को, उन्होंने प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अपने खाते में 1,120 रुपये जमा किए, जिसमें पासबुक प्रविष्टि एनईएफटी या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के रूप में यूपी के खजाने से दिखाई गई।

“मुझे बिना किसी समस्या के पैसा (बीज पर सब्सिडी) मिला। अहमद कहते हैं, "यह 1,280 रुपये में खरीदने से बेहतर है कि मैं दो बैग के लिए प्रभावी रूप से भुगतान कर रहा हूं।"

लेकिन 2,400 रुपये का अग्रिम भुगतान कैसे किया जाता है और फिर 1,280 रुपये पर सीधे खरीदने से बेहतर 1,120 रुपये का दावा किया जाता है? "यह आसान है। अगर कुछ रियायती दर पर दिया जाता है, तो इसे व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है और अधिक कीमत पर खरीदा जाता है। इधर, डायवर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बीज बाजार दर पर बेचे जा रहे हैं और किसानों को, व्यापारियों को नहीं, सब्सिडी उनके बैंक खातों में अलग से हस्तांतरित हो रही है,” वे बताते हैं।

नई प्रणाली में, किसान नकद भुगतान करता है और बीज भंडार प्रभारी से उसकी खरीद के लिए रसीद एकत्र करता है। बाद की जमा राशियाँ सभी किसानों से राज्य सरकार के नामित राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में अगले दिन मिलती हैं। वह जिला कृषि अधिकारी को अपने संबंधित सब्सिडी के दावों के साथ किसानों की सूची को ऑनलाइन जमा करता है, जो डीबीटी पोर्टल में पहले से दर्ज जानकारी के अनुसार इनका सत्यापन करता है। जिले के लिए कृषि उप निदेशक के अगले स्तर पर दावों की जांच की जाती है, जो सीधे किसान के खाते में किए जाने वाले खजाने से भुगतान को मंजूरी देता है।

कामधेनु योजना

यह उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सीएम अखिलेश यादव की सबसे लाभकारी योजना है, जिसके कारण अब उत्तर प्रदेश भारत में दूध उत्पादन में नंबर वन है।

राज्य सरकार ने कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है जो उत्तर प्रदेश के बाहर से अधिग्रहित 100 उच्च उपज वाली पशु डेयरी इकाइयों की स्थापना करती है। उद्यमियों को कामधेनु योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण और सब्सिडी भी दी जाती है। कामधेनु योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश में 100, 50 और 25 मवेशियों के 2000 से अधिक डेयरी फार्म स्थापित किए गए । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की राष्ट्रीय डेयरी योजना (NDP) उत्तर प्रदेश की इकाई के अंतर्गत आती है।

डेयरी की खेती के लिए 'कामधेनु, मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु योजनाएं' उत्तर प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा शुरू की गई थीं।

29 फरवरी 2016 तक कामधेनु डेयरी योजना के तहत स्थापित डेयरी इकाइयों की संख्या 276 थी ।

29 फरवरी 2016 तक मिनी कामधेनु डेयरी योजना के तहत स्थापित डेयरी इकाइयों की संख्या 1461 थी ।

29 फरवरी 2016 तक माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना के तहत स्थापित डेयरी इकाइयों की संख्या 813 थी ।

कामधेनु योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश राज्य में 100, 50 और 20 मवेशियों के 2,000 से अधिक डेयरी फार्म स्थापित किए गए हैं। इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर एक दूध उत्पादक राज्य बन गया।

कन्या विद्या धन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मेधावी छात्राओं को संशोधित कन्या विद्या धन योजना के लाभ के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।

मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर 16 और 17 अगस्त २०१६ को जिला / तहसील मुख्यालय में मंत्री / विधायक प्रभारी की उपस्थिति में, वर्ष २०१६ में इंटरमीडिएट / समकक्ष मेधावी छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जिले को नियमानुसार एक चेक के माध्यम से योजना के तहत 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई।

मेधावी छात्रों के लिए कन्या विद्या धन योजना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई और प्रत्येक जिले के आईसीएसई बोर्ड के साथ-साथ यूपी मदरसा परिषद और यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को भी शामिल किया गया।

रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए इससे बेहतर उपहार और क्या हो सकता था उन्हें 30,000 रुपये का चेक सौप कर सहायता प्रदान की | हालांकि कन्या विद्या धन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पुरानी योजना है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने जिस बड़े पैमाने पर इसे लागू किया, निश्चित रूप से आधी आबादी को एक बड़ा बढ़ावा दिया । हर कोई लड़कियों के लिए अध्ययन करने और अपने पैरों पर खड़े होने की बात करता है, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से इसे आगे बढ़ाया है, आपको शायद ही ऐसे उदाहरण मिलेंगे। उस समय रक्षा बंधन यूपी की बेटियों के लिए खुशी के पल लेकर आया। रक्षा बंधन से पहले, राज्य सरकार ने उन्हें न केवल कन्या विद्या धन का उपहार देने के

लिए तैयारी शुरू कर दी, बल्कि लखनऊ में ही कन्या विद्या धन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दीप प्रज्वलित किया। इससे पहले, राज्य के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने रक्षा बंधन से पहले दो दिनों के लिए अभियान चलाकर कन्या विद्या धन के चेक वितरित करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे, जिसे जोर-शोर से शुरू किया गया । गौरतलब है कि सीएम की इस योजना के तहत प्रत्येक तहसील और जिला मुख्यालयों पर प्रोत्साहन वितरण कार्यक्रम आयोजित किए गए , इसलिए इस पूरे अभियान में 89,100 छात्रों को 30,000 रुपये का चेक दिया गया । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा 2 बिलियन 67 करोड़ 30 लाख रुपये। जारी किए गए, जो निश्चित रूप से मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित किया|

किसान बाज़ार

अखिलेश यादव सरकार ने 2016 में, उत्तर प्रदेश के शहरों में किसान बाज़ारों की स्थापना की, ताकि किसानों को उत्पाद और उपकरण खरीदने के लिए एक खुला और आसान बाज़ार उपलब्ध कराया जा सके।

किसान बाज़ारों खरीदारों और किसानों के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करते हैं, जहां सभी सामान किसानों द्वारा वैध दरों पर बेचे जाते हैं। यह एक स्थिर मंच प्रदान करता है जहां किसान अपनी उपज को अच्छी दरों पर आसानी से बेच सकते हैं, जो सामूहिक रूप से तय किया जाता है ताकि कीमतों में उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप कोई भी किसान प्रभावित न हो।

किसान बाजार मंडी में कुल 5197 परियोजनाओं का उद्घाटन-फाउंडेशन स्टोन:

मुख्यमंत्री अखिलेश ने आगे संबोधन में कहा कि, किसानों के लिए पानी और सिंचाई मुफ्त की गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश में महंगाई को केवल किसान ही दूर कर सकते हैं।

लोहिया आवास योजना

2012 में, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने पिछली बसपा सरकार की महामाया आवास योजना और महामाया सर्वजन आवास योजना को रद्द करने का फैसला किया, और ग्रामीण गरीबों के उद्देश्य से एक एकल आवास योजना शुरू की जिसका नाम है 'लोहिया आवास योजना'।

लोहिया आवास योजना, एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य यूपी में ग्रामीण गरीबों के लिए आवास प्रदान करना था। योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए योजनाओं में अंतर किया जाता है, क्योंकि योजनाओं का एक अलग सेट शहरी गरीबों के लिए है। यह योजना उन उम्मीदवारों के लिए प्रदान की गई जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में घर उपलब्ध कराए जाने थे।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और प्रमुख योजना।

इस योजना को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से वर्ष 2012-13 में शुरू किया था।

योजना का उद्देश्य उन घरों को मुफ्त में घर उपलब्ध कराना था , जिनकी वार्षिक आय रु 36,000 / -से कम है और इंदिरा आवास योजना के लिए तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल नहीं किया गया है। हाउस का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं के अनुसार किया जाना है|

निर्धारित डिजाइन। प्रत्येक घर का कवर क्षेत्र 30 वर्ग मीटर है। आवास की लागत के लिए सरकारी सहायता रुपये सहित प्रत्येक घर के लिए 03 लाख 05 हजार रुपये है। सौर ऊर्जा पैक के लिए 30 हजार।

प्रत्येक घर में दो कमरे, एक रसोई और एक बरामदा है। 03 एलईडी लाइट, 01 डीसी सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ सोलर पैनल और बैटरी का प्रावधान उपलब्ध कराया गया । पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक घर के साथ शौचालय का निर्माण अनिवार्य रूप से किया गया ।

90 दिनों की अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गई । आवास की लागत के अलावा सभी लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 14,0000 वित्तीय वर्ष 2014-15 से, क्लस्टर में घरों का निर्माण किया गया और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अलग से धन उपलब्ध कराया गया ।

समाजवादी जल संचय योजना

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड की खाली पड़ी जमीनों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में 100 विलुप्त तालाबों का कायाकल्प करने का आदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने इस योजना का नाम 'समाजवादी जल योजना योजना' रखा। पूरा बुंदेलखंड गंभीर सूखे की स्थिति से गुजर रहा था। आगे किसी भी विवाद से बचने के लिए, मुख्यमंत्री ने एक रिकॉर्ड अवधि के भीतर 100 तालाबों को फिर से बनाने का आदेश दिया और काम के लिए समय सीमा निर्धारित की । बुंदेलखंड में पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री दोनों चिंतित थे।

बुंदेलखंड में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड क्षेत्र में 40 दिनों में 100 तालाबों की खुदाई का काम पूरा किया । इसमें 60 mcm पानी की स्टोरेज पावर हुयी ।

समाजवादी श्रवण यात्रा

सीएम अखिलेश ने समाजवादी श्रवण यात्रा के माध्यम से राज्य के बुजुर्गों को चारधाम की मुफ्त यात्रा प्रदान की

राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने एक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की जिसका उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आसान तीर्थ यात्रा प्रदान करना था। यह योजना यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू की गई । नेक योजना उन बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी जो वित्तीय और अन्य बाधाओं के कारण उन्हें स्वयं करने में असमर्थ थे । यह एक मुफ्त तीर्थयात्रा योजना थी जहां वरिष्ठ नागरिक यात्रा के लिए नामांकन कर सकते थे ।

तीर्थ यात्रा योजना के तहत, देश भर में कई पवित्र तीर्थस्थलों का चयन किया गया। तीर्थ यात्राओं का संचालन सरकार द्वारा प्रायोजित ट्रेनों और बसों द्वारा किया गया बहुत पहले यात्रा की शुरुआत 14 मार्च, 2015 को हुई थी जिसमें हरिद्वार और हृषिकेश के पवित्र मंदिरों को शामिल किया गया ।

यूपी सरकार ने हालांकि तीर्थयात्रा योजना में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड के बारे में कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए थे । सभी आवेदकों को उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। उन्हें निवास का प्रमाण या एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी एक निवास प्रमाण पत्र प्रदान करना था । यूपी सरकार द्वारा तीर्थ यात्रा योजना के रूप में केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए थी , इसलिए सभी आवेदकों की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हालांकि, योजना के आवेदकों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं थी । योजना के तहत तीर्थ यात्रा में शामिल होने के लिए, सभी आवेदकों को चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए था । इसलिए, सरकारी अस्पताल या प्रतिष्ठित निजी अस्पताल के पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा फिटनेस का प्रमाण पत्र एकत्र करना आवश्यक था ।

समाजवादी श्रवण यात्रा के तहत दी गई सुविधाएं

योजना के पंजीकृत आवेदकों को मुफ्त में पूरी तीर्थ यात्रा प्रदान की गई । आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, लाभार्थियों को सूचित किया गया और आगामी यात्रा और कार्यक्रम का विवरण दिया गया । राज्य परिवहन की बसों ने यात्रियों को उनके निकटतम बस स्टॉप से बिठा लिया था और उन्हें लखनऊ, राज्य की राजधानी, जहां से तीर्थ यात्रा शुरू हुई थी, ड्रॉप कर दिया गया । टूर ऑपरेटर और अटेंडेंट ने अपने साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सभी प्रकार के भोजन, नाश्ता, पीने का पानी इत्यादि मुफ्त में प्रदान किया । उन्होंने दर्शनीय स्थलों और स्थानीय यात्रा की व्यवस्था भी प्रदान की थी। इस योजना के तहत होटलों में आवास भी नि: शुल्क प्रदान किए गए । यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक वस्तुओं से युक्त एक मुफ्त यात्रा किट मिली थी। सभी यात्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के तहत यात्रा के लिए मुफ्त आकस्मिक बीमा प्रदान किया गया । इस यात्रा बीमा को पूरी यात्रा के दौरान सभी ट्रेन के साथ-साथ बस यात्रा के लिए भी प्रदान किया गया । यात्रा की समाप्ति के बाद, यात्रियों को फिर से उनके निवास के निकटतम बस स्टॉप पर ड्रॉप दिया गया।

समाजवादी
श्रवण यात्रा
अब कीजिए अजमेर शरीफ एवं पुष्कर (राजस्थान) की
निःशुल्क तीर्थ यात्रा
अजमेर शरीफ
पुष्कर (राजस्थान)
प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले वरिष्ठ एवं मूल निवासियों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने का सराहनीय निर्णय लिया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी श्रवण यात्रा, भारतीय रेलवे के उपक्रम आई.आर.सी.टी.सी. के माध्यम से कराई जा रही है, जिसमें चयनित यात्रियों को निःशुल्क यात्रा तथा यात्रा के दौरान निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था तथा साथ ही निःशुल्क भोजन, नाश्ता उपलब्ध कराया जायेगा।
• चयनित यात्रियों को एक विशेष रेलगाड़ी द्वारा लखनऊ से अजमेर एवं पुष्कर (राजस्थान) तक यात्रा कराई जाएगी।
• यात्रियों को उनके गृह जनपद से लखनऊ तक आने जाने की व्यवस्था।
• आवेदन पत्र वेबसाइट www.samajwadishravanyatra.upgov.info पर ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 07 जुलाई, 2015 तथा सम्बंधित जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 10 जुलाई, 2015 है।
• पहले आओ–पहले पाओ तथा वरिष्ठता को प्राथमिकता।
• यात्रा हेतु कुल 1044 व्यक्तियों का चयन किया जायेगा।
• यात्रा की निर्धारित तिथि 23 जुलाई, 2015 है।
उरे
NR
twitter.com/cmofficeup
facebook.com/cmouttarpradesh
youtube.com/user/upgovtofficial
upnews360.in
http://information.up.nic.in
बन रहा है आज, सँवर रहा है कल
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

बेरोजगारी भत्ता

बेरोजगारी भत्ते का वितरण उत्तर प्रदेश में 09 सितंबर 2012 से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ते के वितरण की शुरुआत करके समाजवादी पार्टी सरकार की इस बहुप्रतीक्षित योजना की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने संयुक्त रूप से लखनऊ के कॉल्विन तालुकेदार कॉलेज मैदान में मंच से 44 लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ता चेक देकर योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान, राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग दस हजार लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 1000 रुपये के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने घोषणापत्र में जनता से किए गए वादों को एक-एक कर पूरा किया।

यूपी सीएम अखिलेश ने महिला उद्यमियों के लिए विशेष 'महिला बाजार' की योजना बनाई

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों के लिए एक 'उपहार' स्वरुप योजना चलाई | गोमती नगर में अंबेडकर स्मारक के पास एक विशेष 'महिला बाज़ार' बना, जहाँ महिला उद्यमियों को अपने माल और हस्तशिल्प के प्रदर्शन के लिए जगह मिली ।

गोमती के समानांतर चलने के बाद से लखनऊ की मरीन ड्राइव के नाम से मशहूर इस सड़क पर एक पंक्ति में ग्रेनाइट से बने एक दर्जन से अधिक हॉल हैं। लोगों को फास्ट फूड बेचने की अनुमति देने के लिए मायावती के शासनकाल के दौरान सड़क का विकास किया गया था, लेकिन यह विचार लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका | हॉल वास्तव में बिना शटर या दरवाजों के खुले बरामदे हैं।

अब श्री अखिलेश यादव के निर्देश देने के साथ, महिला उद्यमियों को स्थान आवंटित किया गया ।

लखनऊ में इस साल दो और 'हाट' (खुले बाजार) का शुभारंभ हुआ । इन हब में गोमतीनगर के विभूति खंड में 25 एकड़ में फैले 'लखनऊ हाट' और शहीद पथ के पास 'अवध शिल्प ग्राम' शामिल हुए ।

यूपी सरकार (अखिलेश यादव) ने 2015-16 को 'किसान वर्ष' के रूप में मनाया - कृषि प्रगति, बीमा कवरेज और क्रेडिट सुनिश्चित किया

मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने कहा कि, " एक राज्य अपने किसानों की समृद्धि के बिना प्रगति नहीं कर सकता"।

राज्य के बजट 2015-16 को प्रस्तुत करते हुए, अखिलेश यादव ने इसे उत्तर प्रदेश का "किसान वर्ष" घोषित किया। उन्होंने कई किसान-कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की, जिनमें मुफ्त सिंचाई की सुविधा, वन-स्टॉप शॉप योजना के तहत कृषि उत्पादों की 1,000 वन-स्टॉप दुकानें, प्रमाणित बीजों के लिए 131 करोड़, किसानों के दुर्घटना बीमा के लिए 600 करोड़ और 778 करोड़ शामिल थे । राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके अलावा, राज्य सरकार ने अनिवार्य किया था कि ऋणों को वसूलने के लिए बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार के कठोर उपायों का इस्तेमाल न किया जाए। किसानों की ऋण माफी योजना के तहत provision 1650 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे फसल क्षति के लिए बढ़े हुए मुआवजे के साथ लगभग 8 लाख किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया जा सके।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हमारी सरकार पूरी तरह से गांवों और किसानों के विकास पर केंद्रित है। उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षित किया जा रहा है, और उनकी उपज के अच्छे दाम दिलाने के लिए एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है"|

" Peasant fares " जिलों में आयोजित किए गए, जहां किसानों को नई तकनीकों और वैज्ञानिक प्रगति के बारे में सिखाया गया। इसके अलावा, किसानों को हाइब्रिड बीज, जैव-उर्वरक, रसायन आदि के लिए अनुदान दिया गया | "भूमि सेना" योजना ने अपने एकमात्र उद्देश्य के साथ बंजर भूमि के पुनर्ग्रहण का लक्ष्य रखा । बुंदेलखंड क्षेत्र में, किसानों को सिंचाई के लिए वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और सब्सिडी दरों पर स्प्रिंकलर सेट और एचडीपीई पाइप प्रदान किए गए । इसके अलावा, सरकार ने राज्य के शहरी इलाकों में पाइप जलापूर्ति के तहत 10,000+ की आबादी वाले गांवों को कवर करने का फैसला किया ।

उत्तर प्रदेश में गन्ना सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जबकि चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट आई, फिर भी यूपी सरकार ने 1152 करोड़ का भुगतान किया और किसान समाज को मुआवजे के रूप में 442 करोड़ प्रदान किए।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड रखने वाले किसानों को 20,000 करोड़ का ऋण देने के निर्देश दिए । एक अभूतपूर्व कदम में, उन्होंने बैंकों को यह भी निर्देशित किया था कि किसान के किसी भी कार्ड को ऋण से वंचित नहीं किया जा सकता है। संवितरण योजना 10 करोड़ के लक्ष्य वितरण के साथ 800 से अधिक ब्लॉकों में शिविरों का आयोजन किया, जिसके बाद जिला मुख्यालय में शिविरों के माध्यम से 1000 करोड़ वितरित किए गए।

सरकार ने एक नई बीमा योजना, समाजवादी बीमा सेवा योजना भी शुरू की थी। इस योजना के कारण, उत्तर प्रदेश के लगभग 3 करोड़ किसान लाभान्वित हुए। यह कार्ड 75,000 प्रति वर्ष से कम आय वाले प्रत्येक किसान को दिया गया । सरकार प्रीमियम का भुगतान करेगी, और बीमा कंपनियां दुर्घटना की स्थिति में किसानों का बीमा करेंगी। परिवार के मुखिया के साथ-साथ परिवार के 4 सदस्यों को भी कवर किया जाएगा।

सरकार ने बाजारों में किसानों की सुरक्षा के लिए भी पहल की । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ, सैफई और मैनपुरी में किसान बाजार का उद्घाटन किया। इन बाज़ारों में, किसान सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को सस्ती दरों पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उपज को बेचने के लिए एक आसान बाज़ार तक पहुँच सकते हैं। ये बाज़ार हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉलों की भी मेजबानी करेंगे।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को मुख्यमंत्री किसान बीमा योजना के तहत एक दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी प्रदान की थी। इस योजना के तहत, सरकार बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु पर 5 लाख का रिफंड, और विकलांग व्यक्तियों को 2.5 लाख का अनुदान देगी। इस योजना में लगभग ₹ 897 करोड़ की धनराशि वितरित की गई।

इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान वर्ष कार्यक्रम के तहत कई कदम उठाए , जिनमें से सभी ने यह सुनिश्चित करने में योगदान दिया कि क्षेत्र में किसानों की स्थितियों में परिवर्तन आ सकता है। यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक कदम था, और किसानों को आगे आने वाले समय के लिए खुशी की उम्मीद थी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गरीब परिवारों के लिए पेंशन योजना शुरू की

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी समाजवादी पेंशन योजना शुरू की, जिसके तहत राज्य में लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपये दिए गए ।

उन्होंने कहा कि इस योजना का वार्षिक बजट 2,424 करोड़ रुपये है।

अखिलेश ने इस योजना को शुरू करते हुए कहा, "यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा देश में शुरू की गई पहली योजना है, जिसके तहत धन सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।"

योजना के तहत, लाभार्थी को 500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह राशि 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ाकर अधिकतम 750 रुपये कर दी जाएगी।

हालाँकि, इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य और साक्षरता से संबंधित शर्तें थी । परिवार के मुखिया को 70 प्रतिशत उपस्थिति, 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण और गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के साथ-साथ बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करना होगा।

बुदेलखंड राहत पैकेज
(समाजवादी राहत पैकेज)

मुख्यमंत्री (अखिलेश यादव) ने बुंदेलखंड क्षेत्र में अंत्योदय परिवारों को हर महीने समाजवादी सूखा राहत सामग्री वितरित करने की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड क्षेत्र में अंत्योदय परिवारों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री प्रदान करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने मार्च 2016 में महोबा और चित्रकूट की यात्राओं के दौरान समाजवादी सूखा राहत आपूर्ति का वितरण शुरू किया। मुख्यमंत्री ने इस सामग्री से गरीब परिवारों को दी गई राहत और वहां के लोगों की मांग पर यह निर्णय लिया था ।

समाजवादी सूखा राहत सामग्री में, प्रत्येक अंत्योदय परिवार को 10 किलो आटा, 05 किलो चावल, 05 किलो ग्राम दाल, 25 किलो आलू, 05 लीटर सरसों का तेल, 01 किलो शुद्ध देशी घी और 01 किलो दूध पाउडर प्रदान किया गया । यह बुंदेलखंड क्षेत्र के सभी सात जिलों के 2 लाख 30 हजार अंत्योदय परिवारों के लिए उपलब्ध था।

बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली

मुख्यमंत्री ने उस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था सुनिश्चित करने और बुंदेलखंड के सभी जिलों के ग्रामीण

इलाकों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करने के लिए सभी संभव उपाय करने के निर्देश दिए। ।

सीएम अखिलेश ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भुखमरी से नहीं मरे। भुखमरी के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यह संबंधित जिले के जिला कलेक्टर की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह वास्तव में सीएम अखिलेश यादव की बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे उन्होंने खुद बुंदेलखंड क्षेत्र से लॉन्च किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को भुखमरी से बचाने में मदद करना था।

हौसला पोशन योजना यूपी 2016- गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन

हौसला पोशन योजना 2016 में अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो पहले ही बहुत प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना था।

हौसला पोषन योजना मुख्य विशेषताएं

- गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को हौसला पोशन योजना के तहत पका हुआ भोजन और एक फल मिलेगा।
- इस योजना के कार्यान्वयन के लिए श्रावस्ती जिले के एक गाँव को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लिया था।
- गांव को राज्य पोषण मिशन के तहत अपनाया गया ।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस योजना के तहत भोजन पकाएंगे।
- आंगनवाड़ी केंद्र इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पका हुआ भोजन और एक फल प्रदान करेंगे।
- 48000 से अधिक, गर्भवती महिलाओं ने इस योजना के तहत दाखिला लिया ।
- इस योजना के तहत, स्कूल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को खाना बनाने के लिए खाना पकाने की जगह प्रदान करेंगे।
- इस योजना के तहत 7,840 से अधिक ग्राम सभाओं को अपनाया गया ।

हौसला योजना योजना का उद्देश्य

भारत में उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए हौसला पोषन योजना एक महान योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखभाल करना था। योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, योजना लक्ष्य समूह को भोजन की सुविधा प्रदान कर रही थी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं को उपयोगी सलाह और परामर्श भी दे रही थीं। साथ ही कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को उपयोगी टिप्स दिए गए। कुपोषित बच्चों के लिए नियमित वजन जांच की सुविधा भी उपलब्ध थी।

डायल 100

अखिलेश यादव सरकार को राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर राजनीतिक आग का सामना करना पड़ रहा था और 'यूपी 100' परियोजना को गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा था। टेक महिंद्रा से आउटसोर्स की गई (केवल) महिलाएं - 700 युवा - लखनऊ के बाहरी इलाके में एक अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष में 600 टेलीफोन लाइनों पर आपातकालीन संकट कॉल पर उपस्थित रहते थे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार 19 नवंबर 2016 को बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट UP-100 योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के शुरू होने के बाद, अगर कोई समस्या है, तो पुलिस15 मिनट में शहरों तक और 20 मिनट में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएगी।

इसके तहत पुलिस 24 घंटे और सातों दिन जनता की सेवा के लिए तैयार रहेगी। यह परियोजना सबसे पहले 11 जिलों में शुरू की गई ।

जनता की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस योजना की लागत प्रति व्यक्ति प्रति माह एक रुपये है। इसके अत्याधुनिक कॉल सेंटर में, 200 लोगों को बैठने और प्रति दिन एक लाख कॉल प्राप्त करने की व्यवस्था की गई ।

यह एकीकृत कॉल सेंटर देश का सबसे आधुनिक केंद्र है। पहले चरण में, यह योजना 10 जिलों में शुरू की जानी थी, लेकिन रामपुर को भी एक अवसर पर जोड़ा गया।

रामपुर शहर विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज़म खान का क्षेत्र है। इसलिए इस छोटे जिले का नाम बड़े जिलों के साथ जोड़ा गया है। शेष 10 जिले लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, मुरादाबाद और झांसी हैं।

देश का सबसे हाईटेक पुलिस कंट्रोल रूम

गोमतीनगर में मॉडर्न कंट्रोल रूम, जो शहर में डायल 100 हेल्पलाइन का प्रबंधन करता है, लखनऊ पुलिस का सबसे हाईटेक प्रोजेक्ट है।

शहर में सबसे प्रभावी आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों में से एक है , पुलिस की डायल 100 सुविधा 10 मिनट से कम समय में प्रति क्रिया करती है यह गोमतीनगर में आधुनिक नियंत्रण कक्ष (MCR) है, जो सड़क पर नवीनतम पुलिस वैन द्वारा सहायता प्राप्त डायल 100 हेल्पलाइन को नियंत्रित करता है। इसे सबसे हाईटेक पुलिस के रूप में भी जाना जाता है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार, देश में नियंत्रण कक्ष का "नवंबर 2014 में उद्घाटन किया गया था, नियंत्रण कक्ष 100% संकल्प दर के साथ प्रति दिन औसतन 400-700 कॉल को संभालता है।

जैसे ही हम नियंत्रण कक्ष में प्रवेश करते हैं, हमें दो विशिष्ट खण्ड दिखाई देते हैं। "यहाँ 15 लाइनें हैं जो एक साथ चलती हैं। सिविल पुलिस कर्मी - दिन के दौरान महिलाएं और रात में पुरुष - कॉलर्स की मदद करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स में विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, छह महीने के लिए रिफ्रेशर कोर्स के साथ। उनके सामने दो कंप्यूटर स्क्रीन होती हैं, जिनमें से एक पर कॉल करने वाले की जानकारी प्रदर्शित और दर्ज की जाती है, और दूसरा, विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया डिजिटल मैप जो कॉल करने वाले के स्थान को चिह्नित करता है। यह सारी जानकारी फिर दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है जो कॉल करने वाले की समस्या के समाधान का आदेश देती है, इस अभ्यास की अवधि एक मिनट है। "

शिकायतों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - सामान्य, प्राथमिकता और आपातकाल। स्थिति की गंभीरता के आधार पर अधिक वाहनों या बल को बुलाया जाता है। एक सड़क विवाद सामान्य श्रेणी में आता है, जबकि पूर्व संध्या या महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध को आपातकाल माना जाता है।

दूसरा वर्ग डायल 100 वाहनों के प्रेषण के लिए जिम्मेदार है - विशेष रूप से लखनऊ पुलिस के लिए डिज़ाइन किए गए टैब, एमडीटी या मोबाइल डेटा टर्मिनल पर गश्ती कार द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। इस अभ्यास में दो मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है।

प्रत्येक डायल 100 गश्ती कार या बाइक अपने स्वयं के एमडीटी के साथ आती है, जिसके माध्यम से इसे नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाता है। ये MDT हाई-एंड, GPS-इनेबल्ड टच-स्क्रीन टैब हैं, जो अपने डेटा कनेक्शन और एक कैमरा के साथ आते हैं। वर्तमान में, लखनऊ पुलिस के पास चार पहिया वाहनों के लिए 75 एमडीटी (प्रत्येक `2 लाख की लागत) और दोपहिया वाहनों के लिए 75 रुपये (प्रत्येक` 1 लाख की लागत) है। "एक बार जब कार्रवाई के लिए कॉल उसके एमडीटी पर गश्त कार द्वारा प्राप्त की जाती है, तो गश्ती कार में अधिकारी - एक ड्राइवर, एक कांस्टेबल और एक

उप-निरीक्षक - को इसकी गतिविधियों पर नियंत्रण कक्ष को अद्यतन रखने और गंतव्य तक पहुंचने के लिए माना जाता है। पाँच से सात मिनट के भीतर। जब वे कॉलर के स्थान पर जाते हैं, तो वे "ऑन रूट" बटन पर टैप करके इसके बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करते हैं। इसी तरह, जब वे स्थान पर पहुंचते हैं, वे इसे 'आगमन' बटन दबाकर नियंत्रण कक्ष में पहुंचा देते हैं। जब तक एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) कंट्रोल रूम को नहीं भेजी जाती, तब तक वाहन को लगे रहने के लिए दिखाया गया है। यह एटीआर एक वॉयस मैसेज, एक टेक्स्ट रिपोर्ट या यहां तक कि अपराध के दृश्य की छवियों के रूप में हो सकता है।

पतिपुष्टि व्यवस्था

सुविधा को नागरिक-हितैषी बनाने के लिए, प्रत्येक कॉल करने वाले से अनुरोध किया जाता है कि उनके कॉल के संबोधित करने के बाद प्रतिक्रिया दें “हर सुबह 8 बजे से, पिछले दिन के कॉल करने वालों से प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए एक अलग टीम जिम्मेदार होती है। फीडबैक तीन मोर्चों पर लिया जाता है - पुलिस समय पर पहुंची या नहीं, पुलिस कर्मियों का व्यवहार और क्या शिकायतकर्ता द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है या नहीं। इस तरह, जनता का विश्वास सिस्टम में बना हुआ है और हम इस फीडबैक सिस्टम के माध्यम से यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त बनी रहे।

शीरोज़ कैफे लखनऊ, (रेस्टोरेंट रन बाई एसिड अटैक सर्वाइवर्स)

बिल्कुल वैसा नहीं जैसा आपने सोचा था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा! लखनऊ में शेरोज कैफे एक ही टेबल पर कॉफी और प्रेरणा दोनों परोसता है।

विवाहित महिलाओं के लिए नौकरी की व्यवस्था में क्रांति लाने की हमेशा जरूरत थी। वे, जो शादी के बाद या बच्चे पैदा करने या त्रासदी झेलने के बाद काम पर वापस जाना चाहते थे, उन्हें अपने करियर को फिर से शुरू करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज एक महिला के करियर के प्रति थोड़ा कांटेदार है। अफसोस की बात है, यह एक अनसुलझा तथ्य है। लेकिन, हम सौभाग्यशाली हैं कि गोमती नगर में डॉ० अंबेडकर पार्क के सामने स्थित लखनऊ में शीरोज़ कैफे जैसी पहल की गई है।

यह एक पहल है, जो शीरोज़ के संस्थापक आलोक दीक्षित और छांव फाउंडेशन द्वारा की गई है। यह तब अस्तित्व में आया जब उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने इस विचार को सहमति दी और इसका समर्थन किया |

शीरोज़ लखनऊ को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम के सहयोग से खोला गया था। अखिलेश यादव ने महिलाओं के समर्थन के लिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कैफे खोलने के बारे में सोचा।

यह एक उद्यमशीलता परियोजना है जिसे प्रशिक्षण और भविष्य के लिए तैयार करके अपने कैरियर में जीवित बचे लोगों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है, बहादुर महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। वे मजबूत और अधिक साहसी साबित हुए हैं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि वे अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे।

ये बहादुर महिलाएं, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, शीरोज़ कैफे के अस्तित्व को इतना खास बनाती हैं।

यह एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा चलाया जाता है, जो महिलाएं अपनी जिंदगी जीने की हिम्मत रखती हैं। ये महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों से आती हैं, और कुछ ने यहां काम करने से पहले एक रेस्तरां का दौरा भी नहीं किया है।

वे "पीड़ितों" का टैग निकाल रहे हैं और इसे सेनानियों के रूप में बदल रहे हैं। यह लखनऊ शहर का एक कैफे है जहां प्रेरणा और कॉफी एक ही टेबल पर परोसे जाते हैं।

यह एक तरह की जगह है जहाँ पढ़ने के लिए पुस्तकों से भरा शेल्फ है। यहां तक कि बच्चों की किताबें शीरोज़ कैफ़े लखनऊ में उपलब्ध हैं।

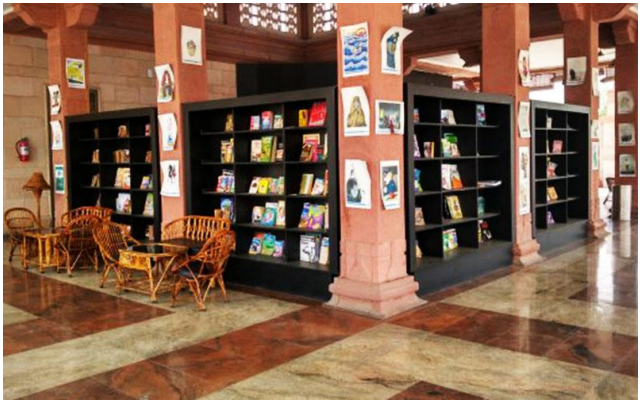

यह शाम के समय सबसे अच्छा है, जहाँ एक कॉफी मग के साथ, आप शांति से बैठ कर काफी और किताबो का आनंद ले सकते है |

यह एक प्रेरणादायक हैंगआउट है, जहां आप वास्तव में अपनी आंतरिक शांति पा सकते हैं। यह हमें इन बहादुर उत्साही महिलाओं की कहानियां बताता है जो झुकने से इनकार करती हैं और इसके बजाय उत्तरजीवी से योद्धा बन जाती हैं।

यूपी वेब-आधारित उद्योग क्लीयरेंस सिस्टम- निवेष मित्र

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, अखिलेश यादव ने सभी 75 जिलों को वेब-आधारित एकल खिड़की सुविधाएं प्रदान की हैं। सभी जिलों में ऑनलाइन सुविधाओं का उद्देश्य उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव को तेज करना है।

यूपी सरकार ने राज्य में उद्योग और उद्यमों की सुविधा के लिए विविध उपाय शुरू किए । निवेश मित्र की ई-पहल के तहत, इसे और अधिक परिणाम उन्मुख बनाने के लिए प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया | राज्य सरकार ने निवेश मित्र बनाने के लिए प्रावधान किये , जिसमे मंजूरी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन सुविधा, अधिक कुशल है। यह देखा गया है कि कई निवेशक और साथ ही सरकारी विभाग अभी भी उद्यम स्थापित करने से पहले विभिन्न अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए मैनुअल मार्ग का उपयोग कर रहे थे । इसलिए, 01 मई 2014 से, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के विभाग, उद्यमियों और उद्योगपतियों से मैन्युअल रूप से मंजूरी के आवेदन स्वीकार नहीं किये गए ।

यह न केवल प्रसंस्करण और मंजूरी जारी करने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करेगा, बल्कि प्रक्रिया में तेजी लाएगा। इस दिशा में, सभी जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में 'हेल्प डेस्क' की मौजूदा सुविधा उन आवेदकों की सहायता के लिए मजबूत की गई जो किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तेजी से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए यूपी को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे , जिसके लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक विनिर्माण को प्रोत्साहन की आवश्यकता थी । इसलिए, राज्य सरकार ने उन मेगा इकाइयों को लाभ के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया जो भू-क्षेत्र परियोजनाओं सहित विविधीकरण या विस्तार करने का इरादा रखती थी । यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। चूंकि राज्य कई कृषि फसलों का उत्पादन करता है। सरकार ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का फैसला किया, यूपी कृषि उत्पन्ना मंडी अधिनयम, 1964 में संशोधन करके। इस अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया गया कि अब नए संयंत्र की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी में `5 करोड़ से कम का निवेश-प्रसंस्करण इकाई मंडी शुल्क से छूट के लिए पात्र होगी। इसके अलावा, निर्यात उन्मुख कृषि प्रसंस्करण उद्योग भी मंडी शुल्क और विकास उपकर में छूट का लाभ उठा सकेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस हेड क्वार्टर लखनऊ

सिग्नेचर बिल्डिंग को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस इमारत में चार मीनारें हैं। फिटनेस सेंटर, हेलीपैड के अलावा, इसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं।

गोमतीनगर एक्सटेंशन के सेक्टर -7 में स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग लगभग 40 हजार वर्ग फीट में बनी है। इस हाई-टेक इमारत में, पुलिस की सभी 18 इकाइयों के कार्यालयों को स्थानांतरित कर दिया गया है।

हस्ताक्षर भवन को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस इमारत में चार मीनारें हैं। फिटनेस सेंटर, हेलीपैड के अलावा, इसमें कई आधुनिक सुविधाएं भी हैं। इस इमारत में नौवीं मंजिल पर DGP का कार्यालय बना है। डीजीपी अब इस कार्यालय में भी बैठते हैं।

इस इमारत के तीन अन्य टावरों में से एक के शीर्ष तल पर, एक सम्मेलन कक्ष, दूसरे में लाउंज और तीसरे में डीजीपी सहायकों के लिए बैठने की जगह तय की गई है। आठवें तल पर अधिकारी और उनके कक्ष डीजीपी मुख्यालय से जुड़े हैं। भूतल पर, पुलिस संग्रहालय, सभी नियंत्रण कक्ष, पीआरओ कार्यालय, पेंशनर्स कार्यालय, पुस्तकालय और आगंतुक कमरे बनाए गए हैं।

लखनऊ में एक बहु-मंजिला पुलिस भवन बनाने की मंजूरी दी गई थी ताकि पुलिस की विभिन्न शाखाएँ आपस में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बना सकें।

महिला हेल्पलाइन 1090

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य भर में महिलाओं के लिए महिला हेल्पलाइन '1090' शुरू की। लखनऊ में लॉन्च इवेंट के दौरान अपने संबोधन में, सीएम ने कहा कि यह पहल अन्य राज्य सरकारों के लिए एक मिसाल कायम करेगी।

बहुचर्चित महिला पावर फोन हेल्पलाइन '1090' मूल रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस का एक पायलट प्रोजेक्ट है क्योंकि यह नवनीत सिकेरा, लखनऊ के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) द्वारा की गई थी। हेल्पलाइन का उद्देश्य बड़े पैमाने पर पहली बार अपराध करने वालों को परामर्श देना है और यदि अपराध जारी रहे तो पुलिस बार-बार अपराधियों के खिलाफ कानूनी उपाय शुरू करेगी।

मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि हेल्पलाइन के पीछे का मकसद पूरा किया जाए, और किसी भी तकनीकी कठिनाई से उनके कामकाज प्रभावित नहीं होने चाहिए । हेल्पलाइन पहले चरण में प्रैंक कॉल, अश्लील कॉल, एसएमएस और एमएमएस से निपटेगी, जबकि इंटरनेट से संबंधित सभी तरह के उत्पीड़न, जिसमें सोशल नेटवर्क पर फर्जी प्रोफाइल पोस्ट करना शामिल है, से दूसरे चरण में निपटा जाएगा और तीसरे चरण में सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न के मामलों को शामिल किया जाएगा।

हेल्पलाइन की दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि इसे Google मानचित्रों से जोड़ा जाना है ताकि पुलिस उन क्षेत्रों को चिह्नित कर सके जहां से पूर्व संध्या के मामलों की सूचना दी जाती है। नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति के साथ संपर्क में रखते हुए अपराधियों के लिए एक डिजिटल पिंजरा भी बनाया गया है; एक बार हेल्पलाइन के अधिकारियों ने पुष्टि की कि अपराधी परामर्श पर ध्यान नहीं दे रहा है, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है कि व्यक्ति चरित्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाए ।

अखिलेश यादव ने महिला हेल्पलाइन पर समीक्षा बैठक की, लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था भी की

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं के बाद, राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में "महिला शक्ति लाइन 1090" की समीक्षा बैठक बुलाई और लड़कियों के लिए सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में "मार्शल आर्ट प्रशिक्षण" शुरू करने का आदेश दिया।

जीआर नोएडा में 5 हज़ार करोड़ का सेल फोन यूनिट

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा राज्य में निवेशकों के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना करते हुए माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी के चेयरमैन राजेश अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश ने मल्टी फेज्ड प्लान में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश कर के और 20,000 से अधिक कुशल और अकुशल व्यक्तियों को नौकरी की गारंटी देकर अपनी कंपनी की चौथी इकाई स्थापित करने के लिए सभी सरकारी समर्थन का वादा किया।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण समूहों को बढ़ावा देने के लिए , प्रमुख मोबाइल और स्मार्टफोन निर्माण कंपनियों, माइक्रोमैक्स और ओप्पो ने ग्रेटर नोएडा में मोबाइल फोन निर्माण इकाइयों को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था |

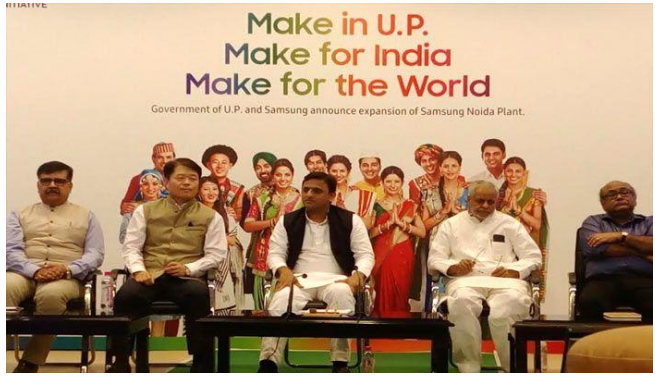

मोबाइल कंपनी ओप्पो के वैश्विक उपाध्यक्ष एरिक और माइक्रोमैक्स समूह के सीईओ राजेश अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात कर ओप्पो मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों ने ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर में एक मोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने सीएम को बताया कि कंपनी नोएडा में अपनी मौजूदा इकाई से प्रति माह 16 लाख मोबाइल फोन का उत्पादन कर रही है।

उत्तर प्रदेश में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और मोबाइल फोन प्रमुख सैमसंग के बीच 17 अक्टूबर 2016 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सैमसंग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत, सैमसंग राज्य में 1,970 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। नोएडा में एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा और कंपनी इसके लिए स्मार्टफोन भी बनाएगी महत्वाकांक्षी मुफ्त समाजवादी स्मार्टफोन योजना का मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई ।

“20 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ, यूपी न केवल उपभोक्ता लेखों के निर्माताओं को आकर्षित करता है, बल्कि इसमें उद्योग के अनुकूल माहौल भी है। अग्रवाल ने कहा, "अखिलेश यादव आक्रामक तरीके से राज्य का विपणन कर रहे हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ राज्य के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए और यूपी के गांवों में कन्नौज में इत्र पार्क और संग्रहालय और राज्य में सोलर पावर के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।" आगरा से लखनऊ तक देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने पर, बुनियादी ढांचे और उद्योग को राज्य में एक बड़ी मजबूती मिलेगी ।

सीएम की महत्वाकांक्षी समाजवादी अभिनव विद्यालय परियोजना

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 23 अप्रैल 2016 को उ०प्र इलाहाबाद में समाजवादी अभिनव विद्यालय का उद्घाटन किया।

यूपी सीएम अखिलेश यादव ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए इसे एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला किया। राज्य सरकार राज्य के 18 मंडलों में समाजवादी आदिवासी स्कूल स्थापित करेगी। कक्षा 6 से 12 तक में उन्हें पढ़ाया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध होंगे, जिसमें छात्रों का प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी भागीदारी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 191 मॉडल स्कूल विकसित किए गए। इनमें समाजवादी अभिनव विद्यालय को 18 मंडलों के जिला मुख्यालयों में एक-एक मॉडल स्कूल के रूप में स्थापित किया। फैजाबाद और कानपुर डिवीजनों के मुख्यालय में एक भी मॉडल स्कूल की स्वीकृति न होने के कारण, एक सोशलिस्ट एबिलिटी स्कूल प्रत्येक को फैजाबाद मंडल के सुल्तानपुर और कानपुर मंडल में कन्नौज में खोला गया। इन स्कूलों का संचालन माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। हिंदी के साथ-साथ स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा।

स्कूल की कक्षाएं दो वर्गों में संचालित की जाएंगी, कक्षाएं 6 से 12 तक संचालित की जाएंगी, जिसमें दो खंड होंगे। नि: शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

2009 के तहत, अधिकतम 35 छात्रों को कक्षा 6 से 8 तक प्रति सेक्शन रखा जाएगा। आगे की कक्षाओं में प्रति खंड अधिकतम 40 छात्र होंगे।

प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के लिए होगी,

इन स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। जबकि कक्षा 9 और 11 में छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। 2016-17 में शुरू, इन स्कूलों का पहला सत्र गैर-आवासीय स्कूलों के रूप में था। जबकि सत्र 2017-18 में, यह एक आवासीय विद्यालय के रूप में संचालित है।

इलाहाबाद मंडल के चाका विकासखंड के दांदूपुर में उत्तर प्रदेश के पहले समाजवादी विद्यालय का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह आवासीय विद्यालय सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने छात्रों को जीवन में समान रूप से अपने माता-पिता और शिक्षकों (गुरुओं) का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि माता-पिता और गुरु के आशीर्वाद से सबसे कठिन रास्ता आसान हो जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गांव, देश या समाज का विकास उसके शैक्षिक विकास पर निर्भर करता है और दांदूपुर इसका एक अच्छा उदाहरण है। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री एस हसनैन के व्यक्तित्व की सराहना करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति महोदय ने अब तक गांव के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं |

मुख्यमंत्री ने इलाहाबाद जिले के दांदूपुर को एक एलईडी गांव के रूप में और दांदूपुर को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) एक गांव के रूप में घोषित किया है। इस अवसर पर, श्री यादव ने सांस्कृतिक शहर इलाहाबाद की सांस्कृतिक विरासत पर आधारित कुंभ मेला कवर डाक टिकट और डेस्क कैलेंडर जारी किया। सूचना और जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से, मुख्यमंत्री ने स्कूल परिसर में एक पीपल का पौधा भी लगाया। राज्य के 18 संभागीय मुख्यालयों पर राज्य सरकार द्वारा समाजवादी विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 3 करोड़ 2 लाख रुपये है। दांदूपुर का सोशलिस्ट इनोवेशन स्कूल राज्य का पहला अभिनव स्कूल बन गया है।

बेनेट विश्वविद्यालय की स्थापना

16 महीने के रिकॉर्ड समय में बेनेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए टाइम्स ग्रुप को बधाई देते हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वह बहुत खुश और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि यूपी सरकार ने इस दावे को गलत साबित किया कि सरकारें धीरे-धीरे काम करती हैं।

लखनऊ में अपने आधिकारिक निवास से बेनेट विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए, अखिलेश ने कहा, "जब मैं टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन से मिला और उन्होंने मुझे बताया कि वह यूपी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, मुझे यकीन नहीं था कि यह समय पर पूरा हो जाएगा। आज, इसने शायद एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कई लोग शिकायत करते हैं कि सरकारें धीरे-धीरे काम करती हैं। बेनेट विश्वविद्यालय के मामले में, तेजी से काम किया गया । इसके लिए, मुझे नौकरशाही, सरकारी तंत्र और राज्यपाल को भी बधाई देना चाहिए। जिनकी मंजूरी के बिना यह संभव नहीं होता। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका विश्वविद्यालय इस प्रकार समय पर जल्द आ सकता है, तो समाजवादी आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, और लखनऊ और नोएडा मेट्रो को भी रिकॉर्ड समय में बनाया जा सकता है। "छात्रों, फैकल्टी, नौकरशाही और मीडिया के जमावड़े को संबोधित करते हुए, विनीत जैन, जो विश्वविद्यालय के पहले चांसलर भी हैं, ने कहा, "छात्रों को बौद्धिक और आर्थिक रूप से उनके मूल्य और मूल्य को बढ़ाने वाली शिक्षा प्रदान करना बेनेट विश्वविद्यालय में हमारा दृष्टिकोण है। ; एक ऐसी शिक्षा जो आपको कैरियर के लिए तैयार और भविष्य के लिए तैयार रहने का अधिकार देती है। शुरुआत से हमारा उद्देश्य बेनेट विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ होने के साथ एक अकादमिक अनुभव के लिए पसंद का गंतव्य बनाना है।

यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने भी बेनेट विश्वविद्यालय के छात्रों को सलाह दी। ग्रामीण भारत और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उनमें से कुछ से पूछते हुए, सिंघल ने कहा कि ग्रामीण भागों में उनके योगदान से उन्हें किसी भी उच्च-भुगतान वाली नौकरी की तुलना में अधिक संतुष्टि मिलेगी।

औपचारिक रूप से बेनेट विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र 8 अगस्त, 2016 को चल रहा था। देश भर से लगभग 240 छात्रों को पहले बैच में दाखिला दिया गया । उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए बेनेट विश्वविद्यालय के तीस छात्र भी लखनऊ में थे। इस अवसर पर, एक बीटेक छात्र सुरभि ने कहा: आप अपने अन्दर के बच्चे को मरने न दें, हमारे डीन ने हमें विश्वविद्यालय के पहले दिन बताया था। “विश्वविद्यालय हर विचार का पोषण करता है और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। उन्हें कैरियर के लिए तैयार करें, उन्होंने कहा, "हमें लगता है कि हम कुछ बड़े का हिस्सा हैं और जीवन में अधिक से अधिक चीजों के लिए हैं। सभा को संबोधित करने वाली दूसरी छात्रा विधी ने कहा," बेनेट विश्वविद्यालय दीवारों के बिना एक परिसर की तरह है। नई समस्याओं से निपटने के लिए हमारे कौशल यहां कॉन्फ़िगर किए गए हैं। यह आजीवन संजोने वाला एक अनुभव है। ”

लखनऊ में कैंसर संस्थान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैंसर के मामलों में वृद्धि पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उनकी सरकार राज्य में सर्वोत्तम उपचार प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ में एक कैंसर संस्थान स्थापित करना चाहती थी और इसका उल्लेख सत्ताधारी पार्टी के घोषणापत्र में भी किया गया था।" अखिलेश ने कहा, "बीमारी के उपचार में बीमारी का पता लगाना, उसका इलाज (ऑपरेशन) और मरीज का पुनर्वास और सरकार उस दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए जगह की पहचान की गई है।"

सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य का एक आगामी केंद्र है जिसकी परिकल्पना भारत के प्रमुख कैंसर विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, ताकि कैंसर प्रबंधन और कैंसर से संबंधित अनुसंधान के लिए एक छत के नीचे व्यापक शिक्षा और शोध कार्य की सुविधा प्रदान की जा सके।

यह संस्थान एक उन्नत राष्ट्रीय स्तर के रेफरल और उपचार सुविधा, अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों / संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के लिए उत्कृष्टता का केंद्र और बुनियादी और अनुप्रयुक्त ऑन्कोलॉजी में अनुसंधान के लिए एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए प्रगति पर है, तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए यहाँ एक विशेष स्थान है । सौ एकड़ का परिसर पहले चरण में 750 बेड के साथ उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है और इसके दूसरे चरण में कुल 1250 बेड हैं। सीमित ओपीडी सेवाएं पहले से ही प्रदान की जा रही हैं, जबकि सेवाओं की पूरी श्रृंखला जल्द ही शुरू होने की उम्मीद थी ।

भारतीय सांकेतिक भाषा और बधिर अध्ययन केंद्र

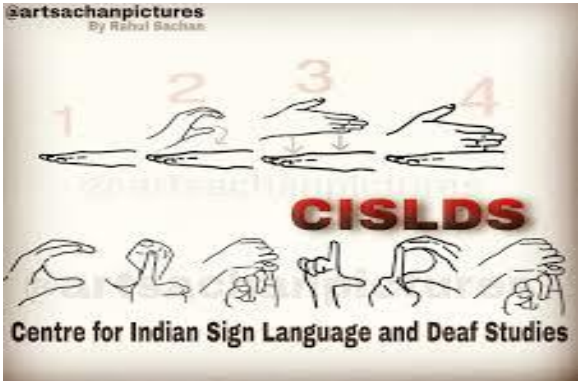

भारतीय सांकेतिक भाषा और बधिर अध्ययन केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और डॉ० शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा की गई ।

यह केंद्र एशिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। केंद्र अध्ययन और व्यक्तिगत विकास के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करके सुनने वालों और बधिरों के बीच की खाई को पाटने का एक दृढ़ प्रयास है। अपने विशेषज्ञ संकाय और सहायक कर्मचारियों के साथ केंद्र सांकेतिक भाषा में शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और बधिर सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और परियोजना की सुविधा प्रदान करते हैं। राष्ट्र के विकास में तेजी लाने के लिए बधिर

समुदाय को मुख्यधारा के समाज में शामिल करने की आवश्यकता पर विश्वास करता हैं।

लखनऊ में शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में भारतीय सांकेतिक भाषा और बधिर अध्ययन केंद्र यूपी में पिछले चार वर्षों के दौरान आने वाले अनूठे संस्थानों में से एक है। इसी तरह, कन्नौज में इत्र अनुसंधान केंद्र, एक फिल्म और प्रशिक्षण संस्थान और लखनऊ में एक डिजाइन विश्वविद्यालय जैसे संस्थान हैं, जो कुशल जनशक्ति विकास को बढ़ावा देंगे और राज्य में उद्योग को बढ़ावा देंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा : "आप देख सकते हैं कि कैसे IIT, IIM, FTI और NIFT भारत के विकास के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए, यूपी सरकार ने भी देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में स्थान बनाने का फैसला किया है। ताकि हमारे युवा लड़के और लड़कियों को उत्कृष्टता के संस्थानों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके।

चक गंजरिया परियोजना

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ में चक गंजरिया फार्म में लगभग 850 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है।

यह आईटी सिटी, कैंसर अस्पताल, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी, डेयरी फार्म, आवासीय और वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

सुल्तानपुर रोड पर 850 एकड़ का खेत पशुपालन विभाग का है; इसके अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपनी सभी गतिविधियों को स्थल से हटाकर वैकल्पिक रूप से 25 एकड़ भूमि प्रदान करें, जो कि उन्हें जल्द से जल्द रहमान खेड़ा में उपलब्ध कराई जाए।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता को देखते हुए प्रस्तावित योजना में एक विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान, एक आधुनिक डेयरी प्लांट, यूपी प्रशासनिक अकादमी कार्यालय और कई अन्य तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के साथ एक आईटी और एक 'मेडी-सिटी' विकसित करना शामिल था ।

प्राधिकरण द्वारा प्राप्त भूमि में से, शेष भूमि को सड़क, सीवर, जल निकासी, विद्युतीकरण आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास और ईडब्ल्यूएस / एलआईवी भवनों के निर्माण के बाद नीलामी द्वारा निपटाया जाएगा। संस्कृति स्कूल का निर्माण प्राधिकरण द्वारा 10 एकड़ भूमि पर, 5 एकड़ भूमि पर सीएसआई टॉवर और 10 एकड़ भूमि पर ईडब्ल्यूएस / एलआईवी भवन में किया जा रहा था ।

मथुरा में चंद्रोदय मंदिर

वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण की परियोजना का उद्घाटन अखिलेश यादव ने किया

70 मंजिला मंदिर बनाने का एक प्रोजेक्ट, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, होली के त्योहार के साथ यहां पर अगाध था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गगनचुंबी मंदिर 'वृंदावन चंद्रोदय मंदिर' के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया।

परियोजना की लागत300 करोड़ रु से अधिक होगी और इस्कॉन अगले पांच वर्षों के भीतर मंदिर निर्माण के समापन की उम्मीद कर रहे हैं। मथुरा-वृंदावन के लिए इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए, यादव ने कहा कि इस परियोजना ने धर्म की अच्छाई को समझा।

'यह होली के साथ एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमें प्यार और खुशी फैलाने के लिए प्रेरित करता है। भारत अपनी संस्कृति, बहुलता के लिए जाना जाता है और कई धर्मों

का घर है। यादव ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, "इस तरह का एक पल हमारी समृद्ध विरासत को रेखांकित करता है और सभी को आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।"

नियोजित सुविधाएं

- हेलीपैड।
- वाहनों के लिए 12 एकड़ पार्किंग।
- भोजन और पेय के लिए कैंटीन।
- एक इनडोर राधा-कृष्ण मनोरंजक पार्क।
- कृष्ण विरासत संग्रहालय।
- ऊपर की मंजिल पर दूरबीन रखी जाएगी जहाँ से लोग पूरे वृंदावन को देख सकते हैं।
- वृंदावन चंद्रोदय मंदिर थीम पार्क।
- एक देखने वाला टॉवर भव्य मंदिर को कुछ झलकियाँ प्रदान करता है।
- मंदिर के कोर के माध्यम से एक कैप्सूल लिफ्ट उठेगी।
- वैदिक साहित्य में ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह प्रणालियों, एक ध्वनि, प्रकाश और चित्रावली शो के माध्यम से।
- आगंतुकों के कुछ दिनों के रहने के लिए विभिन्न प्रकार के आवास की सुविधा इस परियोजना का हिस्सा हैं
- एक सौम्य गुरुलिंग यमुना क्रीक को भी जंगलों में फिर से बनाया जाएगा जो आगंतुकों के लिए नौका विहार का अवसर प्रदान करेगा। जो लोग चलना चाहते हैं, उनके लिए एक स्काईवॉक के लिए एक पथ का निर्माण होगा।
- मंदिर लगभग 30 एकड़ जंगल से घिरा होगा जो ब्रज के पुनर्निर्मित जंगलों का गठन करेगा।
- इस मंदिर के शीर्ष पर एक देखने का टॉवर होगा और मथुरा, आगरा जिससे वहाँ से यमुना नदी के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं।
- मंदिर द्वारा रात्रि सफारी का भी आयोजन किया जाएगा

भारत में कुछ वर्षों में दुनिया का सबसे ऊंचा धार्मिक स्मारक हो सकता है। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर, जो कि वृंदावन, मथुरा में निर्माणाधीन है, की शानदार ऊंचाई 213 मीटर या 700 फीट है। मंदिर की योजना इस्कॉन बैंगलोर द्वारा की गई थी और इसका शिलान्यास 16 नवंबर 2014 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया था।

मुख्यमंत्री अखिलेश ने संतों को दिया उपहार, अयोध्या में बना 5000 सीटों का भजन संध्या स्थल

मुख्यमंत्री ने कालिदास मार्ग पर अपने निवास पर अयोध्या में 5000 सीटों वाले भजन संध्या स्थल का शिलान्यास किया। कहा, इससे धर्म को समझने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर अयोध्या के कई प्रमुख संत उपस्थित थे।

उन्होंने अपने भाषण में रामायण की चौपाइयों और भजनों का उल्लेख किया। संतों ने मुख्यमंत्री को अंगवस्त्र, पगड़ी और प्रसाद देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बलिया में एक स्पोर्ट्स कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक पावर स्टेशन की नींव रखी

जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय (JNCU), एक राज्य विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया में 122 संबद्ध महाविद्यालयों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। बलिया जिले के ये 122 कॉलेज पूर्व में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से संबद्ध थे। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन छात्रों को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की उपाधि प्रदान की गई।

जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा, ज्ञान का सृजन, सामाजिक परिवर्तन और सद्भाव, एकीकृत आवाज और एकजुटता की भावना के साथ देश की सेवा के लिए एक प्रमुख केंद्र बनना है। गंगा घाटी के केंद्र में स्थित, यह नदी-

आधारित कृषि, अर्थव्यवस्था और समाज पर अध्ययन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसमें भारतीय प्रवासी और प्रवासन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

मिशन

उपरोक्त दृष्टि के साथ, विश्वविद्यालय के मिशन निम्नानुसार हैं:

1. छात्रों को सर्वश्रेष्ठ कक्षा शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनाना ।
2. उन छात्रों का पोषण करना जो समाज को बदलने में सक्षम हैं।
3. देश के एक बड़े हिस्से को कवर करने वाले क्रॉस-कल्चरल, मल्टी-कल्चरल और मल्टी-रीजनल कॉन्टिनम पर अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना।
4. शिक्षण, अनुसंधान, और मूल्य निर्माण में उत्कृष्टता की भावना को मूर्त रूप देकर व्यक्तियों की उन्नति के लिए सहायक एक शैक्षिक वातावरण का समर्थन और रख रखाव करना।
5. तेजी से प्रतिस्पर्धी, वैश्विक और बहुसांस्कृतिक दुनिया में चुनौतियों को पूरा करने के लिए

बसंतपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित चंद्रशेखर विश्वविद्यालय और स्पोर्ट्स कॉलेज की आधारशिला रखने आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भृगु की धरती पर जोरदार स्वागत किया गया। दिग्गज नेताओं ने अखिलेश का फूल और माला और स्मृति चिन्ह देकर जोरदार स्वागत किया।

विद्युत उत्पादन में उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने 2012 से 2017 के बीच 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 21,670 मेगावॉट की बिजली उपलब्धता बढ़ाने के लिए छह नई बिजली परियोजनाएँ स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

नई प्रस्तावित बिजली परियोजनाएं परछा थर्मल पावर प्लांट का 500 मेगावाट, हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट और पनकी थर्मल पावर प्लांट का 250 मेगावाट की वृद्धि। जिन अन्य इकाइयों को अपग्रेड किया गया उनमें 1,000 मेगावाट का अनपरा-डी थर्मल पावर प्लांट, 660 मेगावाट का हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट और 1320 मेगावाट का ओबरा सी थर्मल पावर प्लांट शामिल है। सरकार ने एनटीपीसी के साथ 1,320 मेगावाट बिजली परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया था; नेयवेली लिग्नाइट के साथ घाटमपुर में 1,980 मेगावाट; एनटीपीसी के साथ 1,320 मेगावाट (द्वितीय चरण) और संयुक्त क्षेत्र में बारा, करछना, जवाहरपुर और दोफा के 6,600 मेगावाट। इसके अलावा, 10,790 मेगावाट की 10 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, हालांकि निजी क्षेत्र में एमओयू मार्ग और खारा नदी पर 425 लाख रुपये की छोटी पनबिजली परियोजनाएं हैं।

सीएम अखिलेश यादव द्वारा चालू किए गए पावर प्लांट की सूची इस प्रकार है:

बारा थर्मल पावर प्लांट:

बारा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बारा तहसील में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। पावर प्लांट का मालिकाना हक प्रयागराज पावर जेनरेशन के पास है, जो जेपी ग्रुप की सहायक कंपनी है। 1980 MW

में पावर प्लांट की नियोजित क्षमता। 660MW की यूनिट को Dec 2015 में कमीशन किया गया था।

ललितपुर थर्मल पावर प्लांट:

ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में महारानी तहसील में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। पावर प्लांट का स्वामित्व बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड के पास है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स परियोजना को अंजाम दे रहा है। 1980 मेगावाट में पावर प्लांट की नियोजित क्षमता। प्रत्येक सितंबर, 2015 और जनवरी 2016 में 660 मेगावाट की दूसरी इकाइयाँ क्रमशः चालू की गई थीं, और पहले ही पूरी भार क्षमता हासिल कर ली गई थी। जून 2016 में इस इकाई को शुरू कर दिया गया था। एलपीजीएलएल और बीएचईएल के बीच सहमत हुए शेड्यूल से तीन से चार महीने पहले सभी इकाइयों को भेल द्वारा सिंक्रनाइज़ किया गया है।

मेजा थर्मल पावर प्लांट:

मेजा थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील में स्थित एक कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। पॉवर प्लांट का स्वामित्व मेजा उर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (MUNPL) के पास है, जो NTPC Limited और Uttar Pradesh Rajy Vidyut Utpadan Nigam के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। 1320 MW में पॉवर प्लांट की नियोजित क्षमता। राज्य सरकार ने जुलाई 2014 में दो को जोड़ने का फैसला किया परियोजना के दूसरे चरण के रूप में पावर प्लांट को 660 मेगावाट की अधिक इकाइयां दी गई हैं।

अनपरा पावर प्लांट:

यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, जहां बिजली संयंत्र एक परित्यक्त राख तालाब पर स्थापित किया गया है, जिससे दुर्लभ भूमि बचती है। राख तालाब पर बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए सिविल इंजीनियरिंग में विशेष तकनीकी नवाचारों की आवश्यकता होती है। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन ने भूमि की कमी का

सामना कर रहे भविष्य की परियोजनाओं के लिए एक वैकल्पिक विकल्प की पेशकश की।

अखिलेश सरकार द्वारा पहली यूनिट जून 2015 में और दूसरी मार्च 2016 को कमीशन की गई थी।

जवाहरपुर

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भारत के उत्तर प्रदेश में ग्राम मलावन जिला एटा में स्थित है। पावर प्लांट, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (JVUNL) के कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है, जो यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (UPRVIL) की 100% सहायक कंपनी है। पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट दुड्सन को दिया गया

ओबरा सी पावर प्लांट

ओबरा-सी पॉवर प्लांट जिसे यूपी कैबिनेट ने जुलाई 2012 में मंजूरी दी थी, 2009 में मायावती के कार्यकाल में इसे मंजूरी दी गई थी। 2009 में, इस परियोजना को मायावती सरकार ने मंजूरी दे दी थी, सरकारी सूत्रों का दावा है कि मायावती के मामले में परियोजना को "एक" करार दिया गया था। सिद्धांत "अनुमोदन, जबकि अखिलेश सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि परियोजना को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ अनुमोदित किया गया था। कुछ समय के लिए परियोजना की बारीकी से निगरानी करने वाले अधिकारियों का कहना है कि व्यवहार्यता प्राप्त करने में कोई प्रयास नहीं किया गया था। मायावती के शासनकाल में परियोजना की स्थिति का आकलन,करके अखिलेश सरकार ने इसे 'सुपर क्रिटिकल' करार दिया । परियोजना शुरू में 500x2 (1000 मेगावॉट) क्षमता की थी। इसे अखिलेश सरकार द्वारा बढ़ाकर 660x2 (1320 मेगावॉट) कर दिया गया । सरकार के पास बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक 200 हेक्टेयर भूमि थी, इसके अलावा रिहंद से 37 क्यूसेक पानी उपलब्ध हुआ । थर्मल प्लांट के लिए कोल लिंकेज को भी चेंडीपारा कोल ब्लॉक से मंजूरी दी गई थी।

परीछा थर्मल पावर प्लांट:

परिछा थर्मल पावर स्टेशन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में झांसी जिले के परीछा में, बेतवा नदी के तट पर झाँसी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। पावर प्लांट का स्वामित्व और संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा किया जाता है। परीछा थर्मल पावर स्टेशन की क्षमता 1140 मेगावाट है; 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, 210 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। 250 मेगावाट की इसकी पांचवीं इकाई को मई 2012 में चालू किया गया था। अप्रैल 2013 में 250 मेगावाट की छठी इकाई को चालू किया गया, जो कुल स्थापित क्षमता को 1140 मेगावाट तक ले गई।

घाटमपुर

घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन एक आगामी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर में स्थित है। पावर प्लांट नेयवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के स्वामित्व में है, जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (51%) और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उद्योग निगम (49%) के बीच एक संयुक्त उद्यम है। भूमि अधिग्रहण का कार्य जनवरी 2015 को पूरा हो गया। जून में एमईईएफ ने पर्यावरण मंजूरी जारी की। 2015. केंद्र ने घाटमपुर थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए जुलाई 2016 को मंजूरी दी।

हरदुआगंज

हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन कासिमपुर पावर हाउस कॉलोनी में स्थित है, जो भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज में हरदुआगंज रेलवे स्टेशन से 1 किमी की दूरी पर है, जो अलीगढ़ से लगभग 18 किमी दूर है। यह अलीगढ़ जिले में स्थापित किया गया नया विद्युत स्टेशन है। इस बिजली संयंत्र के लिए कोयले को BCCL और ECL के स्वामित्व वाली खानों से प्राप्त किया जाता है और रेल लाइन के माध्यम से बिजली संयंत्र में पहुँचाया जाता है। पावर प्लांट उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के स्वामित्व और संचालन में है। स्थापित क्षमता 665 मेगावॉट है। राज्य सरकार ने जुलाई 2014 में बिजली संयंत्र में 660 मेगावाट की इकाई को जोड़ने का फैसला किया, 660 मेगावाट की इकाई का निर्माण तोशिबा द्वारा किया गया है।

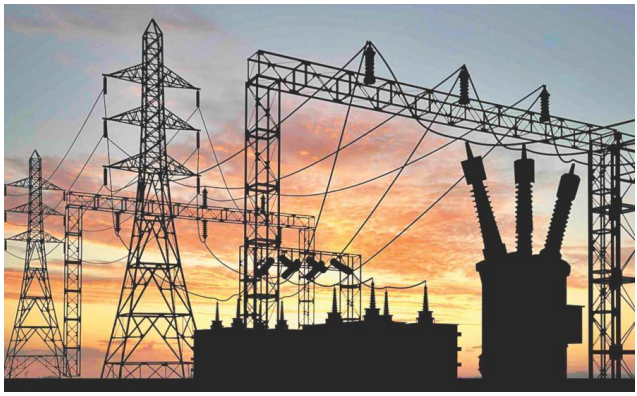

अन्य पावर प्लांट माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किए गए

1 एनटीपीसी लिमिटेड 500 उंचाहार, रायबरेली,
2 करछना पावर स्टेशन, इलाहाबाद
3 यूनिटेक मशीन लिमिटेड 250 औरैया
4 क्रिएटिव थर्मोलाइट पावर प्रा। लिमिटेड 600 बरगढ़, चित्रकूट जिला
5 आईएल एंड एफएस लिमिटेड 500 मुजफ्फरपुर जिला
6 पारेख अल्यूमिनेक्स लिमिटेड 250 बाराबंकी
7 जीएमआर समूह 1200 मथुरापुर
8 जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड 240 चुर्क, रॉबर्ट्सगंज
9 एनटीपीसी - सेल पावर कंपनी लिमिटेड 500 गोंडा
10 एनटीपीसी लिमिटेड 500 जगदीशपुर
11 कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड सीमेंट्स लिमिटेड 75 कानपुर
12 UPRVUNL 250 250 पनकी
13 बजाज पावर जनरेशन प्रा। लिमिटेड 2400 बरगढ़, चित्रकूट जिला
14 कांति बिजले उत्तपन निगम लिमिटेड 290 मुजफ्फरपुर जिला

15 टोरेंट पावर लिमिटेड 1320 संडीला, हरदोई जिला
16 पनकी पावर प्लांट
17 करछना
18 दोफा
19 खुर्जा पावर स्टेशन
20 बरगाह
21 बिल्हौर पावर प्लांट

स्थिति :

2012 में, उस समय कुल बिजली उत्पादन की क्षमता लगभग 10000MW थी और यूपी की वर्तमान स्थापित क्षमता 19000 मेगावॉट (राज्य और केंद्रीय हिस्से सहित) के आसपास है, यह Mar-2017 तक 20000 मेगावॉट की क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद थी । 10000 MW पांच साल की अवधि में क्षमता वृद्धि किसी भी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है। यूपी अब बिजली उत्पादन करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है।

लखनऊ में फिल्म टीवी संस्थान

सीएम अखिलेश यादव ने 2013 में यूपी-फिल्म इंस्टीट्यूट की घोषणा की । लोकभवन में 14 एकड़ के फिल्म संस्थान की आधारशिला रखी गई। इस दौरान सीएम ऑफिस में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा रहा। यह फिल्म संस्थान अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा ...

इस दौरान सीएम ऑफिस में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा था, जिसमें अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के अलावा उनका पूरा परिवार भी नजर आया था।

- गायक स्व० मुकेश के बेटे नील नितिन मुकेश भी भोजपुरी स्टार रवि किशन और निर्देशक अनुराग कश्यप के साथ मौजूद थे। सीएम ने कहा कि इस संस्थान से यूपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहां की प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

इसके लिए युवाओं को यूपी से बाहर कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। इसकी संरचना फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से मिलती-जुलती होगी।

- "हमने जो वादा किया है और इसे पूरा करने का इरादा रखते हैं"।

एक्टिंग से लेकर कैमरामैन, स्क्रिप्ट राइटिंग तक के कोर्स

- यूपी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर बन्धु को प्रमोट करने वाले दिनेश सहगल ने कहा कि सीएम अखिलेश यादव ने बहुत काम किया है।

राज्य में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सीएम इसकी घोषणा कर रहा है और इसे अपनी सरकार में पूरा करने के साथ-साथ इसे सार्वजनिक भी कर रहा है ।- सीएम में बहुत इच्छा शक्ति है। वह पहले सीएम हैं जो समय पर काम पूरा करने का साहस रखते हैं और अपनी टीम के साथ काम करना जानते हैं।

शुरुआत में, हमने सोचा था कि हम एक या दो पाठ्यक्रमों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन सीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी पाठ्यक्रमों को एक साथ शुरू करना होगा और इसे प्राथमिकता के रूप में पूरा करना होगा। - उनके निर्देश पर, हमने लोगों के साथ काम किया है, अभिनय, नृत्य, कैमरा हैंडलिंग, मॉडलिंग, पटकथा लेखन और सभी पाठ्यक्रम जो फिल्मों से जुड़े हैं वे सभी चलेंगे ।- हम एक विश्व स्तरीय संस्थान तैयार कर रहे हैं, जो इसे FTI। से आगे ले जाना चाहता है। इसके साथ, बॉलीवुड यहां आएगा और काम करेगा और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। - इसे अभी 14 एकड़ में बनाने की योजना है। अगर सीएम के निर्देश पर जरूरत पड़ी तो हम जमीन को और भी आगे बढ़ाएंगे।

फिल्म प्रचार नीति

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में दो फिल्म शहरों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, अक्टूबर 2014 को राज्य सरकार ने एक नई फिल्म नीति की घोषणा की। नए मानदंडों के तहत, राज्य में 50 प्रतिशत से अधिक फिल्म की शूटिंग होने पर, फिल्म निर्माता को सरकार 2 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। मौजूदा नीति में, एक निर्माता को 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाता था यदि फिल्म का 75 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में शूट किया जाता है। इसके अलावा, अगर कोई निर्माता राज्य में अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग करता है, तो उसे 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जबकि यह राशि क्रमशः 2.5 करोड़ रुपये और तीसरी और चौथी फिल्मों के लिए 2.75 करोड़ रुपये बढ़ाई गई , अनुदान बाद की फिल्मों पर 3 करोड़ रुपये हो जाएगा। फिल्म संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए, अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा को छोड़कर उत्तर प्रदेश में ऐसे केंद्र खोले जाते हैं, तो सरकार 50 लाख रुपये का अनुदान देगी। यूपी सरकार ने एकल खिड़की नीति लागू की है, उत्पादन / पोस्ट-प्रोडक्शन, सब्सिडी, फिल्म निर्माण के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए समर्पित पोर्टल, क्रू / फिल्म निर्माता / फिल्म प्रतिभा और फिल्म शूटिंग उपकरण के प्रदाताओं के लिए डेटाबेस बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान करना। युवा कलाकारों के लिए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता में एक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई । सभी जिलों में संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में एक 'फिल्म प्रचार और सुविधा समिति' का गठन किया गया। समिति, शूटिंग के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद, फिल्म यूनिट की सुरक्षा की समीक्षा करती है, शूटिंग के लिए अनुमति देती

है, सरकारी गेस्ट हाउस / पर्यटक बंगलों में आवास प्रदान करती है और परेशानी मुक्त शूटिंग अनुभव के लिए बाधाओं को दूर करती है। साथ ही, फिल्म की शूटिंग के लिए मुफ्त पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा जाएगी ।

यूपी फिल्म बंधु को अब तक फिल्म की शूटिंग और सब्सिडी के 150 प्रस्ताव मिले थे। जब से फिल्म बंधु का गठन किया गया है, 25 फिल्मों को पहले ही सब्सिडी की अनुमति दी जा चुकी है। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा स्टारर इश्कजादे, अर्जुन कपूर स्टारर तेवर, सैफ अली खान स्टारर बुलेट राजा और इश्किया सहित कई स्क्रीन कैपर्स को यूपी में शूट किया गया है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म सुल्तान को पश्चिमी यूपी में शूट किया गया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 63 वें राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड' के तहत 'स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट' प्राप्त किया। मई 2016. मई 2015 में, यूपी ने लगभग 700 करोड़ रुपये के निवेश पर दो फिल्म सिटी परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को शामिल किया था।

लखनऊ में दो फिल्म शहर प्रस्तावित हैं और उन्नाव जिले में प्रस्तावित ट्रांस गंगा सिटी परियोजना है। लखनऊ परियोजना को निर्माणाधीन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के आसपास के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। लगभग 300 एकड़ में फैली परियोजनाओं को पूरा होने में 36 महीने लगने का अनुमान था। कान फिल्म फेस्टिवल में आधा दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और आयोगों ने उत्तर प्रदेश में शूटिंग में रुचि दिखाई। कई फिल्म आयोगों ने यूपीएफडीसी के साथ गठजोड़ करने की पेशकश की है ताकि यूपी और अन्य देशों के बीच अभिनेताओं, तकनीशियनों और शूटिंग के अधिक आदान-प्रदान की सुविधा हो सके।

गोमती नदी सौंदर्यीकरण

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा जनता को समर्पित किए जाने के बाद, गोमती रिवर फ्रंट आगंतुको के लिए समय बिताने के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना |

16 नवंबर, 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गोमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। परियोजना के तहत, गोमती नदी के दोनों किनारों को सार्वजनिक उपयोग के लिए सुशोभित और विकसित किया गया ।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने संतुलित विकास और अन्य राज्यों के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक मिसाल कायम की है।

"गोमती रिवरफ्रंट सबसे बड़ी इको-फ्रेंडली परियोजनाओं में से एक है और देश में कहीं और समानांतर नहीं है। यह न केवल एक पर्यटक आकर्षण होगा, बल्कि व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा |

सीएम ने इस अवसर पर नए बने गौस मोहम्मद स्टेडियम का भी उद्घाटन किया। स्टेडियम का नाम लॉन टेनिस खिलाड़ी गौस मोहम्मद के नाम पर रखा गया है, जो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने वाले पहले भारतीय थे। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्टेडियम में खेले जा सकते हैं। अखिलेश यादव ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए बधाई दी और कहा कि नदी में जल परिवहन की सुविधा भी होगी जो ओल्ड सिटी को नए लखनऊ से जोड़ेगी।

- इस परियोजना के तहत, गोमती नदी के दोनों किनारों पर एक डायाफ्राम दीवार बनाई गई है, जो इसके जल प्रवाह को एक निश्चित दिशा (जल-मार्ग) देती है।
- सार्वजनिक उपयोग के लिए जल-मार्ग और तटबंध के बीच की भूमि विकसित की गई है। इसमें एक साइकिल ट्रैक, एक जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, किड्स प्ले एरिया और हर 500 मीटर पर शौचालय, पीने योग्य पानी और पार्किंग की सुविधा है।
- जल-मार्ग में संचार करने के लिए एक जल बस की भी व्यवस्था की गई ।
- परियोजना के तहत, झील विकसित की गई है जिसमें एक संगीत फव्वारा, योग स्थान, शादी का मैदान, 2000 व्यक्ति क्षमता वाला एम्फी-थिएटर और फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए एक स्टेडियम होगा।
- बैठने के प्रयोजनों के लिए, कंक्रीट और कठोर सामग्री के बजाय, घास और पौधों का उपयोग किया गया है, जिससे यह अपनी तरह का पहला स्टेडियम बना।
- इस परियोजना के तहत, लोगों के मनोरंजन और शहरी सौंदर्यीकरण के लिए, हार्डिंग ब्रिज, गोमती बैराज और लोहिया पुल को आरजीबी लाइटों से रोशन किया गया है और गांधी सेतु पर रंगीन रोशनी डाली गई है, जो तेजी से लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट का आकार ले रही है। ।

हेरिटेज जोन

अखिलेश यादव ने 4 दिसंबर 2016 को हेरिटेज जोन सौंदर्यीकरण परियोजना को जनता को समर्पित किया

हुसैनाबाद विरासत को पुनर्जीवित करने की परियोजना पूरी हो गई है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसे जनता को समर्पित किया - साथ ही वहां एक संग्रहालय की नींव रखने के साथ - साथ यह पर्यटकों और आगंतुकों के लिए एक उपहार है । टीले वाली मस्जिद और छोटा इमामबाड़ा के बीच का खंड एक प्रीमियम पर्यटन स्थल है, लेकिन आगंतुकों को पीने के पानी, खाने के जैसी बुनियादी सुविधाएं याद आती थीं, इसलिए अखिलेश यादव ने ऐसी सुविधाएं प्रदान की हैं जो इसे उनके लिए एक यादगार अनुभव में बदल देंगी, अखिलेश ने एलडीए को एक योजना बनाने और पर्यटकों की सुविधा के तत्वों सहित एक प्रभावशाली परिसर विकसित करने का आदेश दिया था। तदनुसार, एक विशेषज्ञ एजेंसी लगी हुई थी और एक साल पहले काम शुरू हुआ था।

"एक पर्यटक या आगंतुक शाम को स्मारकों के वैभव का आनंद ले सकता है, रोशनी के लिए भी योजना के अनुसार एक लाइट और साउंड शो भी होता है

प्रकाश के लिए, शाम -ए-अवध धन्यवाद् देता है कि अब अंधेरे में गायब नहीं होगा, क्योंकि हुसैनाबाद क्लॉक टॉवर और सतखंडा टॉवर को रोशन करने की विशेष व्यवस्था है जो पहले बंद हो गया था और नशेड़ियों का अड्डा बन गया था।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ

2012 में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अखिलेश यादव ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी।उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले इसका उद्घाटन करने की योजना बनाई और उस साल जनवरी तक इसका ढांचा तैयार कर लिया।

एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम - एकाना स्पोर्ट्ज़ सिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर, सरकार के निजी साझेदार ने इसे डिज़ाइन किया - चुनाव से पहले इसका उद्घाटन नहीं किया जा सका।

आदित्यनाथ सरकार ने कुछ बाड़ लगाने और पेंटिंग के काम के बाद, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के नाम पर स्टेडियम का नाम बदल दिया, जिनकी इस साल अगस्त २०१७ में मृत्यु हो गई, सरकार ने आधिकारिक तौर पर आईपीएल मैच से पहले 24 घंटे में बदलाव को मंजूरी दे दी।

एकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे आमतौर पर एकाना क्रिकेट स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। यह एक पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप स्टेडियम है। यह 50,000 की बैठने की क्षमता के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया

खिलाड़ियों, अधिकारियों, वीआईपी, दर्शकों और मीडिया के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ, 50,000 सीटों वाला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम अपनी तरह का सबसे उन्नत हैं । बाउल डिजाइन दर्शकों को एक्शन की तुलना में करीब लाएगा। इस तरह के इस स्टेडियम का डिज़ाइन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की मेजबानी के लिए ICC और BCC। द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और विशिष्टताओं का अनुसरण करता है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सैफई

1 जून 2018 को इटावा शहर के एक समारोह में इटावा सफारी पार्क और अभिनव विद्यालय, सैफई के साथ इसका उद्घाटन किया गया। ग्रीन पार्क स्टेडियम एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई मास्टर चंदगीराम स्पोर्ट्स स्टेडियम। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए काम, सैफई 2006 में शुरू हुआ था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। लेकिन परियोजना पूरी नहीं हो सकी और बाद में निर्माण कार्य में कथित विसंगतियों के कारण फंस गया। 2015 में, सरकार ने सैफई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की परियोजना में नई जान फूंकने का फैसला किया ।

सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत के उत्तर प्रदेश के सैफई में अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक क्रिकेट स्टेडियम है। यह मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज के परिसर के अंदर स्थित है। 43,000 लोगों की बैठने की क्षमता के साथ, यह भारत का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस क्रिकेट स्टेडियम के साथ-साथ स्पोर्ट्स कॉलेज के परिसर में एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल, एथलेटिक्स स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम भी है। पहला टूर्नामेंट जिसकी मेजबानी 2017 में इंडियन ग्रामीण क्रिकेट लीग ने की थी।

इसमें लगा हुआ स्कोर बोर्ड देश के अन्य स्टेडियमों की तुलना में बहुत बड़ा है। मैदान भी ऐसा तैयार किया गया है कि एक या दो घंटे के बाद मैदान में कितनी भी बारिश हो, पानी नहीं दिखेगा। यहां रखा गया स्कोर बोर्ड 3 डी है। इसे पूरे स्टेडियम में किसी भी जगह से साफ देखा जा सकता है। यह 17 मीटर लंबा और नौ मीटर चौड़ा है। यह पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। अब तक, कोलकाता, धर्मशाला, रायपुर, मोहाली, हैदराबाद, पुणे, नागपुर और ग्वालियर के स्टेडियमों में बड़े स्कोर बोर्ड थे ।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव सैफई में 43,000 दर्शक क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। खेत में एक विशेष प्रकार की घास लगाई गई है। यहां नौ पिचें बनाई गई हैं। डे-नाइट मैच के लिए फ्लड लाइट भी तैयार की गई है।

स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए एक अलग पवेलियन, अंपायर रूम, ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर, कमेंट्री बॉक्स आदि का निर्माण किया गया है।

लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की कि लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

फ्लड लाइट्स के साथ एक फुटबॉल स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय मानक के सिंथेटिक मैदान को लखनऊ में फुटबॉल प्रशंसकों के लिए एक वास्तविकता होगी। यह यूपी का पहला फुटबॉल स्टेडियम होगा जहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों की सफलतापूर्वक मेजबानी की जा सकती है। 250 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस स्टेडियम में गोथेनबर्ग, रियल मैड्रिड, मैड्रिड, लॉर्ड्स और लंदन फुटबॉल स्टेडियम जैसे आर्सेनल फुटबॉल स्टेडियम जैसे प्रसिद्ध फुटबॉल स्टेडियम कि तरह् होगा । 20,000 से अधिक की क्षमता के साथ, सुल्तानपुर रोड पर चक गंजरिया लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बगल में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की एक टीम ने वाइस चेयरमैन सत्येंद्र यादव की अगुवाई में और मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंताओं और अन्य अधिकारियों ने स्पेन के प्रसिद्ध फुटबॉल स्टेडियमों का दौरा किया, स्वीडन और इंग्लैंड और शहर में विश्व स्तर के फुटबॉल स्टेडियम के लिए सिफारिशों के साथ सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी। यह सिफारिश की गई थी कि स्टेडियम में आर्सेनल और टेली 2 क्षेत्र की तुलना में फुटबॉल की बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खेल स्थलों में से एक हैं। दर्शकों के लिए 3-स्तरीय अखाड़ा, फ्लड लाइट, कॉर्पोरेट बॉक्स और वीआईपी गैली जैसी सुविधाएं बनाई जानी हैं। लेकिन समय कम होने के कारण और अखिलेश जी का कार्यकाल समाप्त होने के कारण वो इस कार्य को समाप्त नहीं कर पाए.

अंतर्राष्ट्रीय इत्र पार्क कन्नौज

कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय इत्र पार्क परियोजना, जो उनकी पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में से है, का उद्घाटन किया गया, इस परियोजना को कन्नौज के प्रसिद्ध 'अत्तर' उद्योग को आगे बढ़ने के लिए शुरू किया गया था। इत्र निर्माताओं को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक वैश्विक मंच देना इसका प्रमुख उद्देश्य था ।

कन्नौज पारंपरिक रूप से प्राकृतिक इत्र और सार के लिए एक विनिर्माण केंद्र रहा है जो फूलों और प्राकृतिक अर्क तेल से तैयार किया जाता है।

विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे मेहंदी का पेस्ट, शरीर का तेल, आयुर्वेदिक दवाएं, गुलकंद, सुगंध और गुलाब के फूल और चमेली जैसे फूलों से बनाया जाता है।

परियोजना की देखरेख करने वाले प्राधिकरण, राजकीय निर्माण निगम के सूत्रों ने कहा कि वित्त की कमी के कारण काम में बाधा आ गई। एक सूत्र ने कहा, "जबकि पूर्व मुख्यमंत्री 'अतर' शहर कन्नौज को ऑन-वर्ल्ड मैप लाना चाहते थे-, पर उनके बाद योगी आदित्य नाथ इस कार्य को बढ़ने में बहुत दिलचस्पी नहीं लेते हैं।" इत्र पार्क के अलावा, एक इत्र संग्रहालय भी जिले में प्रस्तावित किया गया था।

सहायक अभियंता, प्रभात गुप्ता, जो परियोजना की देखरेख करने वाली टीम का हिस्सा थे, ने कहा, "परियोजना को राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया था। एजेंसी ने बकाया भुगतान न करने पर निर्माण रोक दिया।"

अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल सैफई

अखिलेश यादव ने सैफई में तीन हजार दर्शकों की क्षमता वाला एक एयर कंडीशन स्विमिंग पूल बनाया

अंतरराष्ट्रीय मानक के तीन स्विमिंग पूल विश्व कप टूर्नामेंट के लिए सक्षम है

इटावा जिले के सैफई में अंतरराष्ट्रीय स्विमिंग पूल तैराकों के स्वागत के लिए तैयार है|

अंतरराष्ट्रीय मानक का स्विमिंग पूल: - सपा सरकार में, तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने गांव सैफई में लगभग तीन हजार दर्शकों की क्षमता वाला एक एयर कंडीशन स्विमिंग पूल का निर्माण किया। यहां तीन स्विमिंग पूल बनाए गए हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं, जो विश्व कप के अनुसार भी फिट हैं

तीन प्रकार के स्विमिंग पूल हैं, 10 मीटर, 7.5 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर डाइविंग टॉवर।

आईटी सिटी लखनऊ

"देश की कोई भी राज्य सरकार एक जगह पर सभी आईटी बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने की ऐसी अनूठी अवधारणा के साथ नहीं आई है," (एचसीएल के संस्थापक, श्री शिव नादर)

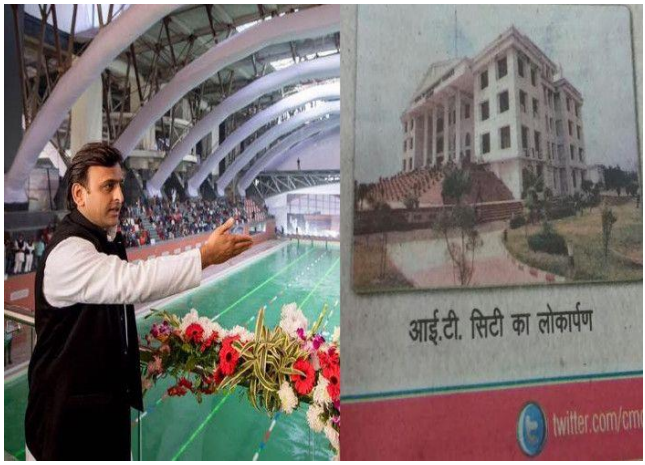

लखनऊ में प्रस्तावित आईटी सिटी 100 एकड़ में फैली है जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एचसीएल के संस्थापक शिव नादर ने आभार प्रकट करते हुए कहा ,

"देश की कोई भी राज्य सरकार एक ही स्थान पर सभी आईटी बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराने की ऐसी अनूठी अवधारणा के साथ नहीं आई है।"

लखनऊ आईटी सिटी को विकसित करने के लिए राज्य द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत एचसीएल आर्म वामसुंदरी इन्वेस्टमेंट का चयन किया गया ।

कंपनी अगले 10 वर्षों में आईटी, आईटी सक्षम सेवा (आईटीईएस), आईटी प्रशिक्षण और अन्य गैर-प्रमुख सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।

इससे पहले, लखनऊ जिले में लखनऊ-सुल्तानपुर राजमार्ग पर चक गजरिया में 100 एकड़ भूमि राज्य आईटी विभाग को हस्तांतरित की गई थी।

कंपनी विकास और कौशल विकास केंद्रों के निर्माण के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) का निर्माण करेगी। कौशल विकास केंद्र आईटी क्षेत्र में युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा।

आईटी सिटी में अगले 10 वर्षों में आईटी और संबद्ध क्षेत्रों में 25,000 नए रोजगार सृजित होने का अनुमान था ।

यूपी से संबंधित छात्रों के लिए राज्य 5,000 रुपये की सीमा के साथ आईटी सिटी में आईटी प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण शुल्क का 50% अनुदान देगा।

यादव ने कहा कि आईटी सिटी लखनऊ को भारत के शीर्ष आईटी गंतव्यों में गिना जाएगा। "हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अलावा अन्य क्षेत्रों में निवेश करना है। आईटी युवाओं के लिए बहुत अधिक रोजगार की संभावना वाला एक बड़ा क्षेत्र है, |

जनेश्वर मिश्र पार्क

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 5 अगस्त 2014 को एक भव्य समारोह में औपचारिक रूप से पार्क का उद्घाटन किया।

"मुलायम सिंह यादव ने कहा।

"एक राजधानी शहर होने के अलावा, लखनऊ एक बड़ा नाम है। ऐसी भव्य स्थिति का एक पार्क इस शहर की शान बढ़ाएगा। पार्क लोगों के लिए विकसित किया गया है और मैं इसके लिए अखिलेश यादव को बधाई देता हूं और वह अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हैं,

लोहिया पार्क 'को शहर का पहला ऐसा पार्क बताया गया, जिसे लोगों ने उपयोगी पाया, उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र पार्क जनता के हित के लिए एक और ऐसा प्रयास है।

उन्होंने कहा कि जब कुछ लोगों ने लोहिया पार्क की आलोचना की थी, जब यह विकास के अधीन था, आज यह सभी को प्यारा है, और इसी तरह जनेश्वर मिश्र पार्क शहर का स्वर्ग बन जाएगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में, जनेश्वर मिश्र पार्क राष्ट्र के सबसे अच्छे पार्क के रूप में उभरेगा, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के कद का कोई अन्य पार्क घनी आबादी के बीच नहीं पाया जा सकता है।

अपने कार्यकाल के दौरान, नेताजी ने लोहिया पार्क का निर्माण किया, जो सुबह से शाम तक शहर भर के लोगों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोहिया पार्क में वे गुण हैं जिनकी प्रशंसा की जाती है

"मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए कि जनेश्वर मिश्र पार्क समाजवादी प्रयासों और समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की श्रद्धांजलि का परिणाम है, मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि समाजवादी पार्टी प्रकृति से प्यार करती है

और पर्यावरण को गंभीरता से लेती है इसलिए पार्क पत्थरों के ढेर के बजाय हरियाली से भरा है।

पार्क को डिजाइन करते समय, दुनिया भर के सभी बेहतरीन पार्कों का अध्ययन किया गया था और इस तरह से पार्क के डिजाइन को प्रेरित किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से चयनित 150 से अधिक किस्मों के पेड़ों को पार्क में नियोजित किया गया

प्रकृति प्रेमियों और फिटनेस प्रेमी लोगों के लिए एक स्वर्ग के रूप में है लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा विकसित किया गया है, जनेश्वर मिश्र पार्क को दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के संकायों द्वारा डिजाइन किया गया है, इस तरह से इसे पेश करने के लिए बहुत कुछ है।

दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत पार्कों से प्रेरित, जनेश्वर मिश्र पार्क में छह अलग-अलग गार्डन है , जिनमें रोज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, बोगेनवेलिया गार्डन, मुगल गार्डन, टोपरी गार्डन, फ्रेंच गार्डन, बैंबू गार्डन और लिली पूल शामिल हैं।

जबकि पार्क की स्पोर्ट्स फैसिलिटी में क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बास्केट बॉल, स्केटिंग रिंग, 8kms का जॉगिंग ट्रैक, 5kms का साइकिलिंग और घुड़सवारी ट्रैक, 10kms का पैदल ट्रैक भी विकसित किया गया है। यहां कृत्रिम झील के रूप में एक विशाल जल निकाय और विशालकाय व्हील 'लंदन आई' की प्रतिकृति 'लकवाइन आई' पार्क के प्रमुख आकर्षण होने की उम्मीद है। अन्य विशेषताओं में चिल्ड्रन प्ले एरिया, वर्कआउट स्टेशन, बोटिंग, एम्फीथिएटर और एक बड़ा फव्वारा शामिल हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए, रामेश्वर वाटिका, गीता वाटिका, बौद्ध वाटिका और कुरान वाटिका को भी जनेश्वर मिश्र पार्क में विकसित किया जाएगा।

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में गोंडोला की सवारी करें

विश्व प्रसिद्ध गोंडोला सवारी का अनुभव करने के लिए लखनऊ वासियों को वेनिस के लिए उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी। गोंडोला की सवारी आखिरकार स्थानीय लोगों के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क में शुरू हुई ।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उद्घाटन के बाद गोंडोला में अपनी पत्नी डिंपल यादव और बच्चों के साथ पहली सवारी की।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ बैलून पर्व के साथ जनेश्वर मिश्र पार्क में पहला उत्तर प्रदेश पर्यटन दिवस मनाया

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने पहले पर्यटन दिवस पर लखनऊ में आसमान में गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाए।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर बनाना है क्योंकि इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे और राज्य को आर्थिक रूप से लाभ होगा।

यूपी सरकार ने 14 फरवरी (2016) को 'पर्यटन दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।

प्रतिभागियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और प्रतियोगिता के विजेताओं को मुफ्त हॉट एयर बैलून की सवारी से सम्मानित किया गया।

जेपी इंटरनेशनल सेंटर लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समाजवादी राजनीतिक नेता जयप्रकाश नारायण को समर्पित एक नए संग्रहालय का उद्घाटन किया |

अखिलेश यादव ने जेएन इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसे समाजवाद के संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है, जय प्रकाश नारायण के 114 वे जन्म दिन के अवसर पर इसका उद्घाटन किया , जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के लिए संघर्ष किया था ।

आर्किटेक्चर स्टूडियो आर्क होम और डिज़ाइन फैक्ट्री इंडिया द्वारा डिज़ाइन किया गया है, और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित, भवन और इसके बगीचे छह एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए हैं।

अखंड संरचना एक विशाल त्रिकोण बनाती है, जो समाजवाद के तीन मुख्य सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि नारायण ने कल्पना की थी - स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा।

इमारत को सशक्त बनाने और शहर के लिए एक नया स्थान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टेराकोटा क्लैडिंग ऐतिहासिक वास्तुकला के प्रति प्रतिक्रिया करता है, अंदर, बड़े रिक्त स्थान अलग-अलग प्रदर्शनियों और अनुभवों के लिए पृष्ठभूमि बनाने की अनुमति देते हैं आगंतुकों को संग्रहालय में प्रवेश करने पर एक रिमोट कंट्रोल और हेडफ़ोन दिया जाएगा, और बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन द्वारा आवाज दी गई एक ऑडियो गाइड संग्रहालय के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेगी। प्रदर्शनों में एक थिएटर शामिल होगा जिसमें नारायण की कहानी एक 3D होलोग्राम के माध्यम से होगी।

आर्किटेक्ट सौरभ गुप्ता की अध्यक्षता में नोएडा स्थित आर्किटेक्चर फर्म आर्कहोम कन्सल्ट्स द्वारा डिज़ाइन की गई, अखंड संरचना को 27 मी-ऊंचे पच्चर के रूप में आकार दिया गया है, जो 20 मी फैले एक आर्च का समर्थन करता है। यह, 9 मीटर की ऊंचाई के साथ, केंद्र में एक तराशे हुए प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। 18.6 एकड़ के एक साइट क्षेत्र में फैले, इस कार्यक्रम को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो उनके नाम के मतलब को दर्शाता है - 'अवशोषण' निचली मंजिल की प्लेटों में बैठता है, 'प्रतिबिंब' को ऊर्ध्वाधर प्रवेश के माध्यम से आधे रास्ते में रखा जाता है, 'आत्मनिरीक्षण' जीवन ऊपरी मंजिलों में और 'कन्टेम्पशन' संरचना के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है।

कुशी नगर हवाई अड्डा
(अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा)

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि कुशीनगर हवाई अड्डे पर काम, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, राज्य में उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था।

कुशीनगर हवाई अड्डा कई बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के आसपास के क्षेत्र में स्थित है जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी (कुशीनगर अपने आप में एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है) और "अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा" के रूप में घोषणा करने से बेहतर कनेक्टिविटी की पेशकश होगी, जो हवा की प्रतिस्पर्धी लागत का एक व्यापक विकल्प है |

इस निर्णय के परिणामस्वरूप घरेलू / अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्रों का आर्थिक विकास होगा।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान होगा। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर-पूर्वी भाग में गोरखपुर से लगभग 50 किमी पूर्व में स्थित है और यह महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है।

Cm अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का प्रस्ताव रखा, जो नेपाल और बिहार की सीमा क्षेत्र का पहला 'गंतव्य हवाई अड्डा' होगा।

ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में 'निर्वाण' प्राप्त किया था और इस तरह यह एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल है। हालांकि, कोई सीधा हवाई संपर्क नहीं है, जो पर्यटन को प्रभावित करता ।

लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन सर्किट में पूर्वी यूपी और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में कई जिले शामिल हैं, जिनमें कुशीनगर, सारनाथ (वाराणसी), कौशाम्बी, श्रावस्ती और कपिलवस्तु शामिल हैं।

प्रस्तावित हवाई अड्डा अधिकतम पर्यटक आगमन के लिए लेखांकन करने वाले देशों के साथ सीधे सर्किट को जोड़ने का लक्ष्य है। घरेलू पर्यटकों के अलावा जापान, म्यांमार, कोरिया, चीन, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका। कुशीनगर में छोटे विमानों को संभालने के लिए 97 एकड़ में एक मौजूदा हवाई पट्टी है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कुशिंगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की लागत लगभग 354 करोड़ रुपये थी। जनवरी 2014 में, अखिलेश यादव कैबिनेट ने डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर (डीबीएफओटी) आधार के तहत परियोजना को मंजूरी दे दी थी

लैपटॉप वितरण योजना

मुफ्त लैपटॉप वितरण योजना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कि एक क्रन्तिकारी योजना साबित हुई |

यूपी सरकार के अनुसार, यूपी सीएम द्वारा नि: शुल्क लैपटॉप योजना का उद्देश्य छात्रों को समान अवसर प्रदान करना था, जो संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ रहे थे। कंप्यूटर एक आवश्यकता के रूप में उभरा है। सरकार ने छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए मुफ्त लैपटॉप वितरित किया । जनवरी 2012 में लखनऊ में पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा सपा घोषणापत्र में घोषणा किए जाने के समय लैपटॉप योजना को मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए पेश किया गया था।

उनकी योजना पहली बार शुरू की गई थी |समाजवादी पार्टी 2012 के इंटरमीडिएट और हाई-स्कूल पास आउट के लिए मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट कंप्यूटर देने के लिए

चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था जिसे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, अपने प्रशासन के पहले तीन वर्षों में इस योजना के तहत 18 लाख लैपटॉप वितरित किए। वर्ष 2015 में सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के टॉपर्स को मुफ्त लैपटॉप देने की घोषणा की। सत्र 2014-2015 के 625 हाई स्कूल कक्षा और 425 इंटरमीडिएट के टॉपर्स लाभान्वित हुए । 2012-16 के बीच लगभग 1607000+ लैपटॉप वितरित किए गए जबकि 2013 में एक वर्ष में 980000+ लैपटॉप उत्तर प्रदेश में छात्र के बीच वितरित किए गए जो एक रिकॉर्ड भी है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त लैपटॉप योजना का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना और राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना था। जो छात्र संसाधनों की कमी के कारण पिछड़ रहे थे, उन्हें इस योजना के तहत लाभ हुआ।

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार लाभार्थी ऐसे छात्र थे जिन्होंने निम्नलिखित निकायों द्वारा आयोजित 10 वीं और 12 वीं की परीक्षा दी थी।

- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- सीबीएसई,आईसीएसई तथाआईएससी
- संस्कृत शिक्षा बोर्ड
- मदरसा बोर्ड के मुंशी / मौलवी और आलिम
- मान्यता प्राप्त आईटीआई और पॉलिटेक्निक

अल्पसंख्यकों के लिए 20% कोटा और SC / ST छात्रों के लिए 21% अंतिम फ़ाइनल लैपटॉप वितरण योजना प्राप्तकर्ताओं की सूची में भी बनाया गया था। इस योजना को एक समान अवसर प्रदान करने और भेदभाव को दूर करने के लिए समाजवादी सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण के रूप में माना जाता था। यह माना जाता है कि इन लैपटॉप वितरण के माध्यम से, छात्रों को उच्च शिक्षा और सॉफ्ट कॉपी में संसाधन सामग्री की सुगमता के साथ अध्ययन में रुचि प्राप्त होगी और उनके नोट्स का संपादन उस समय होगा जब भारत में, उच्च शिक्षा में नामांकन (लगभग 25%) था कई देशों की तुलना में बहुत कम (चीन 43%, था |

लेदर पार्क कानपुर

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हरदोई जिले के संडीला क्षेत्र और कानपुर जिले के रमईपुर क्षेत्र में दो मेगा लेदर क्लस्टर परियोजनाओं के लिए प्रमुख स्वीकृति दी। दोनों क्लस्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित किए गए और केंद्र द्वारा देश भर में मेगा लेदर क्लस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया।

कानपुर के रमईपुर क्षेत्र में लगभग 625 एकड़ भूमि में लेदर पार्क विकसित किया जाना था । पार्क गुणवत्ता मानकों और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार से मांगों को पूरा करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगा। पार्क में छोटे और मध्यम स्तर के क्षेत्र से 50% इकाइयों के लिए बुनियादी ढांचा होगा। ।IDC ने कहा कि प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पार्क में उत्पन्न होने वाले अपशिष्टों के उपचार की सुविधा होगी। घरेलू बाजारों की मांग और निर्यात के लिए मानकों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित एकीकृत चमड़े के पार्क अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और उत्पादन श्रृंखला से लैस होंगे। लघु और मध्यम स्तर की चमड़ा प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह भी कहा है कि इस श्रेणी में इकाइयों के लिए 50 प्रतिशत स्थान अलग रखा जाएगा, चमड़े के समूहों में अपनी उत्पादन गतिविधियों को अंजाम देना। समूहों में वर्षा जल संचयन, भण्डारण, कच्चे माल के बैंक, प्रदर्शनी केंद्र, डिजाइन केंद्र और मानव संसाधन विकास के प्रावधान भी प्रस्तावित थे । मेगा लेदर क्लस्टर्स के विकास के लिए भारत सरकार की योजना के

तहत विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से लेदर पार्क को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, 70 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष सुविधा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 233 एकड़ में से, 69 एकड़ भूमि का उपयोग टेनरियों की स्थापना के लिए किया जाता है, 47 एकड़ में चमड़े के सामान के लिए विनिर्माण इकाइयां, 22 एकड़ में ग्रीन बेल्ट और 30 एकड़ में सीईटीपी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समूहों में कच्चे माल बैंक, प्रदर्शनी केंद्र, डिजाइन केंद्र और मानव संसाधन विकास भी प्रस्तावित हैं। मेगा लेदर क्लस्टर्स के विकास के लिए भारत सरकार की योजना के तहत विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से लेदर पार्क को लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत, 70 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष सुविधा राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

लायन सफारी इटावा

समाजवादी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा लायन सफारी

इटावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क या लायन सफारी इटावा एक ड्राइव-थ्रू वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। इटावा में सफारी चल रही है। इस परियोजना के लिए सौंपे गए वन्यजीव अधिकारियों ने प्रेरणा के लिए इंग्लैंड के लॉन्गलेट सफारी पार्क का दौरा किया। इटावा के शेर सफारी के पास एक थीम पार्क और एक पर्यटक स्थल विकसित किया गया ।

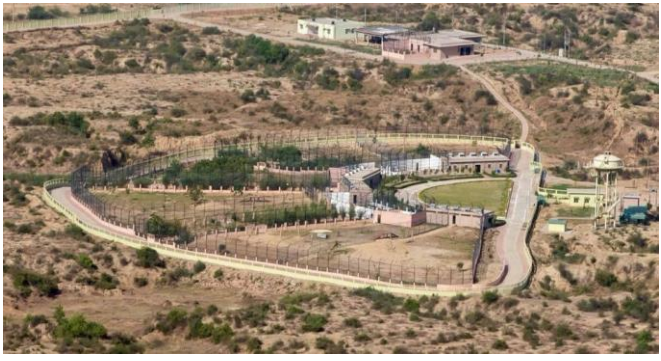

मुलायम सिंह यादव के "ड्रीम प्रोजेक्ट" की परिकल्पना 2005 में की गई थी ।

इसमें एक लॉयन सफारी, एक हिरण सफारी, एक हाथी सफारी, भालू सफारी और एक तेंदुआ सफारी है। इसमें पहले से ही भारतीय सेना के दो विजयंत टैंक हैं, जिनमें एक स्टीम लोकोमोटिव है। इसमें 4D थिएटर भी है, जो आपको वन्य जीवों के साथ वास्तविक नज़दीकियां प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो रामगोपाल यादव के साथ हिरण सफारी का उद्घाटन किया और फिर सफारी में चीतल को चारा भी खिलाया। मुख्यमंत्री वहां काफी देर तक रुके और चीतों के साथ खेलते रहे। उन्होंने सफारी के सुविधा केंद्र का भी दौरा किया।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खुली जीप में इटावा के सफारी पार्क में हिरन को निहारते हुए प्रो राम गोपाल यादव, सांसद धर्मेन्द्र यादव और मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव एक साथ सफारी पार्क में नजर आए।

मैत्रेय परियोजना-कुशीनगर

13 दिसंबर 2013 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए मैत्रेय परियोजना की आधार शिला रखी |

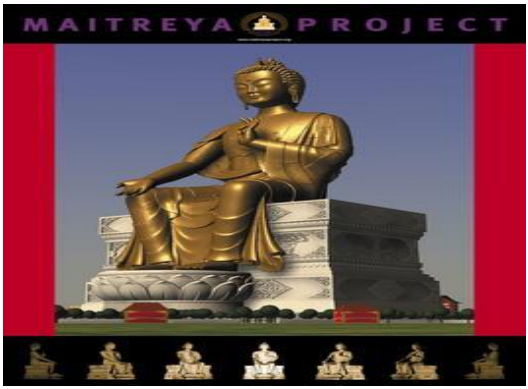

इस आयोजन में बौद्ध संत लामा जोप्पा रिनपोशे सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि शामिल थे।

मैत्रेय परियोजना इसमें 500 फीट (152.4 मीटर) ऊंची, बुद्ध मैत्रेय की 50 मंजिला प्रतिमा का निर्माण शामिल था , जिसके 1,000 साल तक खड़े रहने की उम्मीद है। । साइट, शुरुआत में बिहार (भारत) राज्य में, प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण स्थानांतरित कर दी गई थी । यह संभवतः उत्तर भारतीय राज्य में स्थित होगा उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा में भारत के चार में से चार बौद्ध तीर्थ स्थल हैं।

मूल तकनीकी टीम को यह तय करना था कि प्रतिमा का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा और इसका निर्माण बड़े पैमाने पर कैसे किया जाएगा। उन्होंने चीन में बुद्ध की दो बड़ी मूर्तियों (वूशी और पु तोल शान) और जापान (उशीकू) सहित मौजूदा बड़ी मूर्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की। इन दोनों प्रतिमाओं को कांस्य में रखा गया था। मूल रूप से, वैकल्पिक सामग्रियों पर विचार किया गया था, जिसमें आंतरिक समर्थन संरचना पर पत्थर, कंक्रीट और एक गठित धातु का खोल शामिल था। पत्थर को जटिल आकार के लिए अनुपयुक्त माना जाता था।

मैत्रेय परियोजना 268 एकड़ में फैली होगी और इसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक भव्य और आधुनिक शैक्षणिक संस्थान होगा। इसमें एक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा इकाई, ध्यान मंडप, फव्वारे, जल निकाय, पार्क, और एक गेस्ट हाउस भी शामिल होगा।

मुगल संग्रहालय

अखिलेश ने मुगल संग्रहालय की नींव रखी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 जनवरी 2016 को यहां एक मुगल संग्रहालय, एक स्ट्रीट कैफेटेरिया, एक आगरा हेरिटेज सेंटर और एक ताज ओरिएंटेशन सेंटर की आधार शिला रखी। सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को सही प्राथमिकता दी थी और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की थी।

संग्रहालय ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास आएगा और स्मारक से लगभग 1,300 मीटर की दूरी पर स्थित होगा।

एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग मुगल युग के पर्यटकों को उनके हथियार, कपड़े, संस्कृति और कई अन्य चीजों से अवगत कराने के लिए किया जाएगा।

ताज ओरिएंटेशन सेंटर मौजूदा शिल्पग्राम को धराशायी करके बनाया जाएगा और इसमें एक ओपन एयर थिएटर और एक भूमिगत पार्किंग होगी।

स्ट्रीट कैफेटेरिया आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा फतेहाबाद रोड पर पीएसी मैदान में बनाया जाएगा। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि यह दो मंजिला इमारत होगी जिसमें आठ फूड स्टॉल, एक मंडप, अन्य सुविधाओं के बीच दो रेस्तरां होंगे।

आगरा हेरिटेज सेंटर वैश्य हॉस्टल में 11,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आएगा और इसका उपयोग पर्यटन, कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा।

अखिलेश यादव ने वहां का दौरा किया और सोशल मीडिया पर घोषणा की कि 'आगरा में सपा के समय शुरू हुए मुगल संग्रहालय को राष्ट्रीय एकता और बहु-धार्मिक साझी विरासत के रूप में जाना जाएगा, जब सपा सरकार आती है। आने वाले समय में, एसपी महाराज अग्रसेन, राजमाता जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा का सम्मान करेंगे।

नये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था कि सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करेगी। जब तक 2009 में यूपी में केवल 5 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज थे, अब 12 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। त्वरित समय में नए कॉलेज स्थापित करने का श्रेय अखिलेश सरकार को जाता है।

अंबेडकरनगर, बिजनौर, बांदा, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी और सोनभद्र में 7 नए इंजीनियरिंग कॉलेज सामने आए ।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आजमगढ़

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया । कॉलेज ने बीटेक की शिक्षा शुरू कर दी है। तीन विषयों में कार्यक्रम - सूचना प्रौद्योगिकी , मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग (प्रत्येक में प्रवेश के लिए 60 सीटों का सत्र 2010-11 से मदन मोहन मालिया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के माध्यम से शुरू हुआ

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में कि गई थी प्रत्येक शाखा में साठ ६० सीटो का प्रावधान था तीन शाखाओं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी के साथ की गई थी। कॉलेज जुलाई 2015 अतर बांदा में स्थित अपने स्वयं के पूर्ण आवासीय

परिसर में चला गया है और सत्र 2015-16 से सभी शैक्षणिक गतिविधियों को अपने स्वयं के परिसर में किया जा रहा है। कॉलेज के पूरी तरह से आवासीय परिसर में शैक्षणिक भवन कार्यशाला, पांच छात्रावास (लड़के और लड़कियां आवासीय अपार्टमेंट, छात्र गतिविधि केंद्र कॉलेज कैंटीन किराने की दुकान और मनोरंजन के लिए अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

सत्र 2015-16 से इंजीनियरिंग की तीन शाखाओं IT, ME और EE में पढ़ाई शुरू करने के लिए कॉलेज में AICTE के मानदंडों के अनुसार सभी आवश्यक संरचनाएं विकसित की गई । कॉलेज में विभिन्न कार्यालयों के लिए कला बुनियादी ढांचे की स्थिति जैसे कि निदेशक रजिस्ट्रार लेखा परीक्षा डीन अकादमिक विभागाध्यक्ष संकाय सदस्य और अन्य शैक्षणिक कार्यालय कॉलेज में मौजूद हैं।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अम्बेडकर नगर

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2010 में विशेष घटक योजना के तहत स्थापित किया गया था कॉलेज ने बीटेक की शिक्षा शुरू कर दी है। सत्र 2010-11 से प्रत्येक शाखाओं में 60 सीटों के साथ तीन विषयों में कार्यक्रम - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईई और सिविल इंजीनियरिंग प्रारंभ हो चूका है |

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सोनभद्र

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इंजीनियरिंग कॉलेज पुलिस लाइंस की तरफ स्थित है जो चर्क रेलवे से लगभग 2 किमी दूर है। यह जिला मुख्यालय से लगभग 3.5 किमी दूर है। मुख्य रेलवे स्टेशन रॉबर्ट्सगंज इंजीनियरिंग कॉलेज से लगभग 8 किमी दूर है। सत्र 2015-16 के दौरान, छात्रों के पहले बैच को UPSEE के माध्यम से प्रवेश दिया गया था। यह वर्तमान में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बी में बीटेक की पेशकश कर रहा है। यह वर्तमान में KNIT सुल्तानपुर से चलाया जा रहा है।

राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी कन्नौज

दोनों कॉलेज अन्य HBTI कानपुर से संचालित हो रहे हैं। सत्र 2015-16 से शुरू हुए हैं।

न्यू हाईकोर्ट लखनऊ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यहां क़ैसरबाग में अपने 100 साल पुराने अदालत परिसर को अलविदा कह दिया और आखिरकार 19 मार्च 2016 को उद्घाटन किए गए गोमतीनगर में नए विशाल परिसर में स्थानांतरित कर दिया।

जिसमे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल रहे, राज्यपाल ने ध्वजारोहण किया और नए न्यायालय परिसर में बेंच के आधिकारिक स्थानांतरण को चिह्नित किया।

वकीलों ने एक विशेष 'पूजा' की और कई लोग नए भवन में सेल्फी क्लिक करते देखे गए।

भवन का निर्माण 2010 में शुरू हुआ था और 2014 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि, यह 2016 में पूरा हो गया था।

नए भवन में पहले के परिसर में 29 की तुलना में 57 कोर्ट रूम हैं। पूरा परिसर वाई-फाई सक्षम है और केंद्रीय रूप से वातानुकूलित है और इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। कैंपस में 6,900 वर्ग मीटर का रिकॉर्ड रूम है, जिसमें एक निश्चित समय में 18 लाख फाइलें रखी जा सकती हैं।

न्यायाधीशों की कारें पहली मंजिल तक जा सकती हैं और पुस्तकालय में 3 लाख पुस्तकों की क्षमता है।

न्यू लखनऊ सचिवालय

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नए कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें कुछ मंत्रियों और वरिष्ठ नौकरशाहों के कार्यालय भी होंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय के नए भवन में 'एडजस्टेबल केबिन' है, जो सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक है। कार्यालय के केबिनों का आकार आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा किया जा सकता है।

- भवन का मुख्य कार्यालय यूपी विधानसभा का प्रतिबिंब है।
- नए भवन के मुख्य गुंबद में उकेरी गई नवग्रह बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि विधान सभा में है।

- नई इमारत 125 साल पुरानी विधानसभा की तुलना में अधिक सुंदर और भव्य है।

- पूर्ण भवन को तीन भागों में विभाजित किया गया है
- इमारत के ब्लॉक ए में 'बेसमेंट पार्किंग', लॉन, सुरक्षा कक्ष और वॉच टॉवर हैं
- ट्रैफिक से बचने के लिए मैकेनाइज्ड रैंप पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है

- गुंबद के ठीक नीचे मुख्यमंत्री का कार्यालय पांचवीं मंजिल पर होगा
- भवन में पांच प्रवेश द्वार होंगे। मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी के लिए एक द्वार से प्रवेश वर्जित होगा
- इस विशेष गेट से प्रवेश सीएम को सीधे पहली मंजिल पर वीआईपी लॉबी में ले जाएगा
- लॉबी में दो लिफ्ट हैं जो सीएम को सीधे पांचवीं मंजिल तक ले जाती है|
- मुख्यमंत्री कार्यालय वाई-फाई सक्षम है और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बीएमएस तकनीक, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली जैसी सुविधाएं हैं|

उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज

अखिलेश यादव ने कई नए मेडिकल कॉलेज खोलकर और नए और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों के साथ मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करके यूपी की स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का प्रयास किया। ऑपरेशन थियेटरों की मशीनीकृत सफाई और अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की योजना बनाई गई । ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता है। जौनपुर, चंदौली, नजीबाबाद, और शाहजहाँपुर में आने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के लिए बस अड्डा स्वीकृत किया गया । उत्तर प्रदेश में चिकित्सा देखभाल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अखिलेश सरकार ने जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला | राज्य बस्ती, फैजाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और बहराइच के जिला अस्पतालों का उन्नयन किया । उत्तर प्रदेश में तीन सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हैं, यानी लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU); संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS), लखनऊ; और सैफई (इटावा जिले) में यूपी ग्रामीण आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान।

स्थिति :

1947 और 2012 के बीच केवल आठ मेडिकल कॉलेज आये | अगस्त 2016 के अंत तक 11 और मेडिकल कॉलेज जोड़े गए। यह अखिलेश सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धि है | यूपी ने भी मेडिकल सीटों की कुल संख्या में वृद्धि की । अंबेडकरनगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर में नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही क्रियाशील हैं। बदायूं मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन था जबकि ओपीडी पहले से ही शुरू है। सितंबर 2016 तक आपातकालीन सेवाएं शुरू हुईं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज के

2017 के शुरू होने तक 150 बेड की क्षमता के साथ पूरा होने और कार्यात्मक होने की उम्मीद थी। फिरोजाबाद जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में बदल गया । सरकारी और निजी दोनों मेडिकल कॉलेजों के लिए फोरेंसिक मेडिसिन प्रोग्राम में पोस्टमार्टम प्रणाली शुरू की गई । सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, शिक्षण सहायक उपकरण और आधुनिक आरएंडडी सुविधाएं। लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए छात्रावास और संकाय और अन्य कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में मेडिकल कॉलेज की एक बड़ी श्रृंखला है, इसके अलावा, राज्य सरकार राज्य स्तर पर अधिक मेडिकल कॉलेज रखने के लिए पूर्ण नियोजन मोड में थी। कुल मिलाकर यूपी में 18 मेडिकल कॉलेज होंगे और स्वास्थ्य सेवा के मामले में यह राज्य के लिए बड़ा बढ़ावा है। तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में 1000 से अधिक चिकित्सा सीटों में वृद्धि की गई जो कि चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए हर्ष का विषय है। यूपी की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए यूपी सरकार द्वारा कुल मिलाकर उत्कृष्ट कार्य किये गए ।

उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य और शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: अखिलेश यादव

अखिलेश सरकार के दौरान तीन पैरामेडिकल कॉलेज या तो पूरे हो गए या शुरू हो गए।

1.) रानी लक्ष्मी बाई पैरामेडिकल कॉलेज झाँसी कॉलेज 86 एकड़ के फैलाव में उच्च गुणवत्ता वाले आधुनिक परिसर के साथ कला महाविद्यालय है। यह सितंबर 2014 में शुरू हुआ था। इसमें 2000 छात्रों को दाखिला देने की क्षमता है। इसमें सभी आधुनिक उपकरण हैं और इसमें ऑडिटोरियम है, जिसमें एक बार में 1100 लोग रह सकते हैं।

2.) बदायूं में पैरामेडिकल कॉलेज और सैफई में पैरामेडिकल साइंस कॉलेज

यूपी रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सफई में 300 स्टूडेंट्स हॉस्टल के साथ एक पैरामेडिकल कॉलेज की योजना थी। बदायूं में एक और पैरामेडिकल कॉलेज प्रस्तावित था।

सैफई में पैरामेडिकल कॉलेज मूल रूप से फरवरी 2006 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2012 में इसकी पहली अकादमिक सत्र की शुरुआत हुई। एक प्रतिष्ठित और अपनी तरह का पहला उत्तर प्रदेश राज्य में ही नहीं, बल्कि भारत में भी, सरकारी क्षेत्र में एक बहुत प्रतीक्षित पैरामेडिकल कॉलेज आखिरकार वर्ष 2012 में "पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय" (कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज), सैफई (इटावा) के रूप में अस्तित्व में आया जो वास्तव में श्री मुलायम सिंह यादव जी की मजबूत दूरदर्शी दूरदर्शिता को साबित करता है। कॉलेज को यूपी RIMSR, सैफई के एक घटक कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया है। सैफई में एक पैरामेडिकल कॉलेज को जोड़ने के फैसले को इस तथ्य का समर्थन किया गया था कि राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ देश में भी पैरामेडिकल / संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है।

कॉलेज का पहला शैक्षणिक सत्र 2012-13 में पैरामेडिकल / एलायंस हेल्थ साइंसेज के विभिन्न विषयों में 13 पाठ्यक्रम शुरू करके शुरू किया गया था। फिजियोथेरेपी और मेडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में स्नातक स्तर (4 पाठ्यक्रम) जबकि भौतिक चिकित्सा, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, ऑप्टोमेट्री, एक्स-रे, सीटी स्कैन, एमआरआई, कार्डियो में डिप्लोमा स्तर (11 पाठ्यक्रम)। टेक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक।, डायलिसिस टेक।, ऑपरेशन थिएटर टेक। और इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर। शैक्षणिक सत्र 2013-14 में ऑप्टोमेट्री और रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक में दो और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम अनुशासन का परिचय दिया गया। सभी स्नातक पाठ्यक्रम CSJMU से संबद्ध हैं, कानपुर बैच 2015-16 तक और यूपीयूएमएस (मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी) में यूपीआईआरएमएस के बैच ग्रेड 2016-17 के बाद से सभी डिग्री कोर्स अब स्व-संबद्ध हैं, जबकि सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रम राज्य चिकित्सा संकाय, लखनऊ के तहत चल रहे हैं। विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में कुल सेवन लगभग 510 है।

कॉलेज ने पहले ही विभिन्न विषयों के लिए विभिन्न स्तरों पर 26 प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों की भर्ती की है।

कॉलेज परिसर UPUMS से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और एक शैक्षणिक सह प्रशासनिक ब्लॉक, व्याख्यान थिएटर परिसर, छात्रों के लिए छात्रावास, खेल का मैदान, ग्रीन बेल्ट और शिक्षण संकाय और आवासीय आवास के लिए 44 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है |

प्लास्टिक सिटी, औरैया परियोजना

मुख्य मंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्लास्टिक सिटी उद्यमियों और रोजगार सृजन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक होगी, जिसमें आम सक्षम संपत्ति, प्रोटो-टाइपिंग, गैर-विनाशकारी सामग्री परीक्षण, ऊष्मायन, प्रशिक्षण, भंडारण और प्लास्टिक जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्लास्टिक शहर में रीसाइक्लिंग प्रदान किया जाएगा।

राज्य सरकार ने इसे प्लास्टिक सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दिबियापुर में 314 एकड़ भूमि की पहचान की है। क्षेत्र में प्लास्टिक हब की स्थापना के लिए जोर गेल के मौजूदा पेट्रोकेमिकल प्लांट की वजह से है, जो उच्च-घनत्व के साथ-साथ कम घनत्व वाले पॉलीथीन का उत्पादन करता है। लोकप्रिय रूप से एचडीपीई और एलडीपीई कहा जाता है, ये प्लास्टिक, उत्पादों, पाइप, खिलौने, बाल्टियों, प्लास्टिक की बोरियों से लेकर औद्योगिक के साथ-साथ घरेलू उपयोग के लिए आवश्यक उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल हैं। विकास लगभग 314 एकड़ में फैलेगा, जिनमें से 225 एकड़ औद्योगिक उपयोग के लिए होगा। शेष में एक आवासीय टाउनशिप, बैंक, स्कूल और अस्पताल होंगे। लखनऊ से लगभग 125 किलोमीटर दूर दिबियापुर (औरैया) में प्रस्तावित प्लास्टिक सिटी का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना और उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए है। इस 200 एकड़ के AIPMA प्लास्टिक पार्क का स्थान उत्कृष्ट है और दिल्ली से लगभग 4.5 घंटे की ड्राइव और कानपुर से 1.5 घंटे की दूरी पर, पाटा में गेल संयंत्र के निकट एल में स्थित है। यूपीएसआईडीसी ने कंपनी के तहत प्लास्टिक पार्क की स्थापना की है, यूपी स्टेट प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एआईपीएमए के अध्यक्ष और

उपाध्यक्ष उत्तर के साथ, निदेशक के रूप में, यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ। निर्माण यूपीएसआईडीसी द्वारा, एआईपीएमए के परामर्श से किया जाएगा। निवेशकों को दी जाने वाली निम्नलिखित सुविधाओं को समझा जाता है।

परियोजना के यूएसपी

परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 274.4 एकड़ औद्योगिक इकाइयों के साथ विकसित किया जाएगा और 84.93 एकड़ आवासीय इकाइयों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है
- गेल ने औरैया में HDPE के 1,00,000 TPA और LDP के 1,60,000 TPA के अपेक्षित उत्पादन के साथ एक पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की है
- 7 एकड़ जमीन विशेष सुविधाओं के लिए आरक्षित है जिसमें 5 एकड़ में CIPET लगाया गया है, जो मुफ्त है
- प्लास्टिक उद्योग में कुशल कर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए गेल द्वारा कौशल विकास केंद्र के लिए 1.5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई
- पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) औरैया से होकर गुजरेगा, जो प्लास्टिक सिटी को बहुत जरूरी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।
- गोदाम और कंटेनर डिपो के लिए भूमि और बुनियादी ढांचा
- एनटीपीसी औरैया में एक पावर प्लांट है
- गेल का मौजूदा पेट्रोकेमिकल प्लांट

सुविधाएं और बुनियादी ढांचा

- NH-2 और राज्य राजमार्ग 21 के निकटता (लगभग 15 किलोमीटर)

- फफूंद रेलवे स्टेशन से 8 किमी
- गेल और एनटीपीसी से 10 किमी सीमित
- CUGL पाइपलाइन से निकटता जिसका उपयोग कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किया जा सकता है

अधिग्रहित और विकसित भूमि का विवरण

- आवंटित भूखंड (सं।): औद्योगिक -108, व्यक्तिगत आवास भूखंड- 109
- रिक्त भूखंड (Nos): औद्योगिक 224, व्यक्तिगत आवास भूखंड -513

निवेश के अवसर

- **औद्योगिक**
  175.02 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखी गई है। कुल 223 भूखंड 450 वर्गमीटर से भिन्न भूखंड के आकार के साथ उपलब्ध हैं। माउंट लगभग 36,000 वर्गमीटर। माउंट प्लास्टिक पार्क प्लास्टिक-मोल्डेड एक्सट्रूडेड सामान, पॉलिएस्टर फिल्मों और जैसे उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला के लिए विनिर्माण और निर्यात का अवसर प्रदान करता है।

- **आवासीय इकाइयाँ**
  प्लास्टिक सिटी में आवास योजना में आवासीय क्षेत्र के लिए 84.93 एकड़ जमीन है, जिसमें समूह आवास और व्यक्तिगत आवास भूखंड शामिल हैं। 112.5 वर्ग मीटर आकार के कुल 622 आवास भूखंड। माउंट से 300 Sq माउंट प्रस्तावित हैं जिनमें से 480 प्लॉट उपलब्ध हैं। ग्रुप हाउसिंग के लिए कुल 17.79 एकड़ जमीन के साथ चार प्लॉट उपलब्ध हैं। आवासीय क्षेत्रों में कई सहायक कारक होंगे जैसे कि खुदरा दुकानें और पर्याप्त मात्रा में हरे रंग के क्षेत्र।

- **व्यावसायिक**
  प्लास्टिक सिटी दुकानों, छात्रावास, पेट्रोल पंप, रेस्तरां, ऑटो शोरूम, होटल, वेयरहाउसिंग स्पेस और अन्य सुविधाओं जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ एक आत्मनिर्भर शहर है।

- **संस्थान**
  एक एकीकृत टाउनशिप के रूप में, विभिन्न संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह कामकाजी आबादी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा, साथ ही उद्योग को प्रशिक्षित मानव शक्ति की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

समाजवादी स्वास्थ्य सेवा (एम्बुलेंस)

मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की ये एक नि: शुल्क, 24/7 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा है इस सेवा के लिए निर्धारित टोल-फ्री नंबर 108 था; जिस पर कॉल करने पर, एम्बुलेंस 20 मिनट के भीतर मरीज तक पहुँच जाएगी और अस्पताल ले जाने से पहले उसे चिकित्सा सहायता दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की आपातकालीन चिकित्सा परिवहन प्रणाली, "108- समाजवादी सेवा" का शुभारंभ किया। जिसके द्वारा बेशुमार जिन्दगी बचाई और अभावग्रस्त व्यक्तियों की मदद की। उत्तर प्रदेश सरकार के कई स्वास्थ्य-क्षेत्र आधारित नव विचारो की सफलता की कहानियां असंख्य हैं, और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करने में बड़ी दूरी तय कर चुकी है।

दिल के दौरे, गर्भधारण, जलने, दुर्घटना या हमले से आघात और संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा राहत के लिए प्रावधान किए गए थे; जिनमें से सभी को तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

108 प्रणाली के तहत, चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान एम्बुलेंस और अन्य संबद्ध चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और इस तरह की आपातकालीन स्थिति के बीस मिनट के भीतर सूचित किया जाता है। गर्भवती महिलाओं, सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों, दिल के दौरे से बचे लोगों और संक्रामक रोगों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता वाले लोगों को आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदान की जा रही एम्बुलेंस चिकित्सा उपकरणों के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित हैं और वातानुकूलित भी हैं।

इन स्थितियों को दूर करने और तेजी से चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने एम्बुलेंस सेवाओं को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक कॉल-सेंटर भी शुरू किया । एम्बुलेंस सुविधा के शुभारंभ के शुरुआती चरणों में, लखनऊ, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, संभल, शामली, बागपत और अंबेडकर नगर सहित तेरह जिले 108 प्रणाली द्वारा कवर किए गए थे। इसके अलावा, 133 एम्बुलेंस विशेष रूप से चिकित्सा आपात स्थिति के लिए और उनमें से 240 समाजवादी स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, 18

जिलों में 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। 102 राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के संचालन में सुधार के लिए निवेश किया गया , जिसमें गर्भवती महिलाओं और बीमार बच्चों को चिकित्सा सहायता पहुंचाने के लिए 1000 अतिरिक्त एम्बुलेंस का प्रावधान शामिल है। और 2015 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 108 सेवा में 900+ एम्बुलेंस के बेड़े को बढ़ाने के लिए इसमें 500 और जोड़ दिए।

इसके अलावा, जीवन बचाने में मदद करने के अलावा, एम्बुलेंस सेवा भी हजारों लोगों के लिए बचत और आजीविका बनाने में मदद कर रही है, जिसमें 15,000 से अधिक व्यक्ति एम्बुलेंस सेवाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य (और संबद्ध) क्षेत्रों में जो कदम उठाए हैं, वे उल्लेखनीय हैं। इस क्षेत्र में निरंतर विस्तार और प्रगति के साथ, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य आंकड़ों में बड़े पैमाने पर व्यापक सुधार निश्चित रूप से सराहनीय हैं।

सरस्वती हाई-टेक सिटी इलाहाबाद

न्यू इलाहाबाद मास्टरप्लान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2 सितंबर, 2015 को इलाहाबाद में सरस्वती हाई-टेक स्मार्ट सिटी की आधार शिला रखी। उन्होंने कहा कि नए हाई-टेक स्मार्ट सिटी में शहर में सफाई की जाँच के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। हाई-टेक स्मार्ट सिटी में प्रयाग विश्वविधालय (राज्य विश्वविद्यालय) और एक पुस्तकालय (जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय) होने के अलावा औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, पार्क, संग्रहालय होंगे। कुल क्षेत्रफल लगभग 1200 एकड़ है।

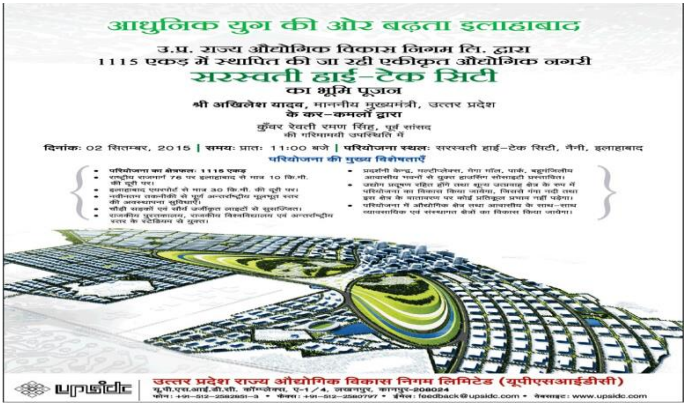

अखिलेश ने सपा सरकार की नीति को दोहराया जो गरीबों को देने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह बताया कि यह सिर्फ ऐसे शहर नहीं हैं, जिन्हें विकास और ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि गांवों के साथ-साथ बहुत से किसान जरूरत की चीजों की खेती करते हैं जिनकी आपूर्ति शहरों को की जाती है। किसानों के मुद्दों का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उपज के वितरण में आने वाली चुनौतियों का भी सपा सरकार द्वारा सामना किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने सपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नए हाई-टेक स्मार्ट सिटी में शहर में सफाई की जाँच के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

इस आयोजन में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि "हाई-टेक स्मार्ट सिटी में औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, पार्क, संग्रहालय होंगे, इसके अलावा प्रयाग विश्वविधालय (राज्य विश्वविद्यालय) और एक पुस्तकालय (जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय) भी होगा।"

हाई-टेक शहर के अलावा, सीएम ने आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित 18 कार्यों को समर्पित किया है।

शिक्षा मित्र नियुक्ति-1.75 लाख शिक्षक नियुक्ति

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास आउट और शिक्षा मित्र (तदर्थ प्राथमिक शिक्षक) की नियुक्ति करने का निर्णय लिया।

शिक्षा मित्र, जिन्हें इंटरमीडिएट की न्यूनतम योग्यता प्राप्त होनी चाहिए थी, उन्हें 1999 में एक सरकारी आदेश (GO) के माध्यम से पिछले BSP नियम के दौरान नियुक्त किया गया था। वे ग्रामीणों को अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए थे। शिक्षा की आवश्यकता 2010 में, नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) ने फैसला किया कि प्राथमिक स्तर से ऊपर के शिक्षकों को ही पात्रता परीक्षा (टीईटी) में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, इसने उन लोगों को पांच साल की छूट दी थी जो पहले से ही शिक्षक थे। 2011 में, सरकार को दो वर्षीय बीटीसी में शिक्षा मित्र प्रदान करने के लिए NCTE से अनुमति मिली। 2011 से कई बैचों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और कुछ को अभी भी प्रशिक्षित किया जा रहा था ; इस प्रकार कुल संख्या लगभग 1.72 लाख तक पहुंच गई।

2012 में, अखिलेश सरकार ने शिक्षा मित्र को नियमित करने का उपाय शुरू किया। मई 2014 में, सरकार ने शिक्षण नियमों में संशोधन किया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद लागू किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि शिक्षा मित्र को टीईटी उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसने सहायक अध्यापक के रूप में उनको आत्मसात करने की घोषणा की। जून, 2014 में पहले चरण में लगभग 59,000 शिक्षा मित्रा को नियमित किया गया था, इसके बाद जून 2015 में दूसरे चरण में 73,000 और लगभग सभी शिक्षा मित्रा को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वे लगभग 30000 रुपये का सुंदर वेतन प्राप्त कर रहे थे । सितंबर 2015 में, इलाहाबाद HC ने अपने आदेश में राज्य शिक्षा विभाग के नियमों में लाए गए संशोधनों को रद्द कर दिया, जिसके माध्यम से शिक्षा मित्र को नियमित किया जा रहा था।

सिद्धार्थ विश्वविद्यालय

विश्विद्यालय के संस्थापक कुलपति, रजनीकांत पांडे ने टीओआई को बताया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेपाली छात्रों के लिए विश्विद्यालय में आवासीय सुविधाओं को विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जो निश्चित रूप से भारत-नेपाल संबंधों को मजबूत करेगा।

उत्तर प्रदेश का 25 वां राज्य विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, भारत-नेपाल सीमा पर राज्यपाल के अनुमोदन और यूपी सरकार के औपचारिक आदेश के बाद 17 जून 2013 से अस्तित्व में आया।

गोरखपुर जोन के महाराजगंज, बस्ती जोन के सिद्धार्थनगर, देवीपाटन जोन के संतकबीर नगर, बलरामपुर और श्रावस्ती जिले सहित विभिन्न जिलों के लगभग 185 कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 30 अक्टूबर, 2013 को वर्सिटी की आधारशिला रखी गई थी और उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि विश्वविद्यालय दो साल में सक्रिय हो जाएगा और विश्वविद्यालय दो साल के भीतर शुरू हो गया जो उल्लेखनीय है। विविधता निश्चित रूप से डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय और आरएमएल अवध विश्वविद्यालय

के बोझ को हल्का करती है क्योंकि दो जिलों के 21 कॉलेज जो अवध विश्वविद्यालय के अधीन थे और चार जिले के 164 कॉलेज जो डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय के अधीन थे, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के तहत आएंगे। सत्र में प्रवेश के लिए छात्र। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के तहत सभी संबद्ध कॉलेजों में 2015-16 सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के पहले सत्र के छात्र होंगे। ”

महान समाजवादी श्री मुलायम सिंह यादव ने 1989 से क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया शुरू की। यह वास्तव में इस विश्वविद्यालय की स्थापना के महान सपने की परिणति के लिए यात्रा की शुरुआत थी। इसके बाद, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 30 अक्टूबर, 2013 को विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 अक्टूबर, 2015 को इस केंद्र को उच्च शिक्षा के लिए खोलने के संबंध में औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी की।

नव स्थापित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, वास्तव में, महात्मा बुद्ध के दर्शन और उपदेश की ऐतिहासिक परंपरा और विरासत की एक पवित्र धारा है और इसका उद्देश्य ज्ञानवर्धन है।

कौशल विकास मिशन
(कौशल विकास योजना)

कौशल विकास कार्यक्रम सकारात्मक रूप से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, **अखिलेश यादव** 29 दिसंबर 2015 प्रशिक्षुओं को 1,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके अलावा, उन्होंने प्रत्येक को 30,000 रुपये के चेक भी दिए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने 100 लड़कियों को एलईडी बल्ब भी दिए।

(इंडिया टुडे, 30/12/2015)

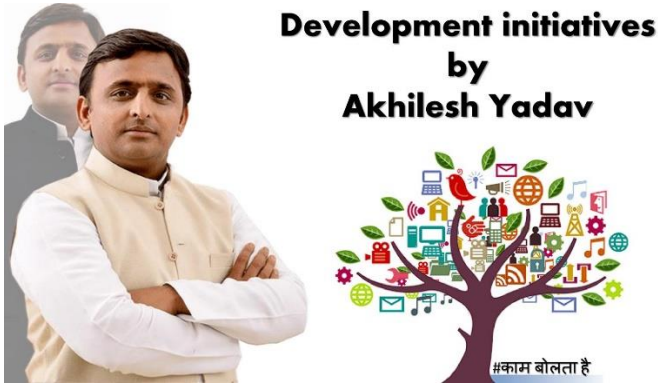

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) राज्य में कौशल विकास की पहल को समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2013 में स्थापित किया गया । UPSDM उत्तर प्रदेश कौशल विकास कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को अल्पकालिक मॉड्यूलर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बड़े निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को संलग्न करने के लिए तैयार है। एक प्रभारी मंत्री और एक सचिव के साथ एक अलग मंत्रालय बनाया गया । पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पांच जिलों में एक कार्यक्रम केंद्र स्थापित किया गया था। एक एमओयू मॉडल बनाया गया था, और मापदंड और दिशा निर्देश तैयार किए गए थे, जिन पर कंपनियां यूपी सरकार के साथ साझेदारी में युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार दे सकती थीं। ऐसी कंपनियों को कम से कम 100 करोड़ रुपये का कारोबार करना पड़ता था।

यूपी उन कुछ भारतीय राज्यों में शामिल है, जिन्होंने विशेष रूप से खाड़ी देशों में निवासियों को नौकरी पाने की सुविधा के लिए एक प्रवासी जनशक्ति भर्ती लाइसेंस प्राप्त किया है। इस राज्य ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में 70,000

अधिक सीटें जोड़ी हैं और एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना थी । प्रशिक्षण के लिए राज्य भर के पारंपरिक समूहों का उपयोग किया गे , जैसे भदोही में कालीन बुनाई, कानपुर और आगरा में चमड़ा उद्योग, मुरादाबाद में पीतल के बर्तन, वाराणसी में रेशम बुनाई, लखनऊ में चिकनकारी, फिरोजाबाद में कांच का काम, अलीगढ़ में ताला बनाना, खेल का सामान मेरठ आदि में।

स्थिति:

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है, इस क्षेत्र में भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य हैं। राज्य का कौशल विकास कार्यक्रम न केवल प्रमाण पत्र और वार्ड - दोनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुचाने के लिए सुर्खियां बना रहा है - यह दुनिया भर में शुरू किया गया सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम भी है। राज्य ने 1,769 केंद्रों पर लगभग दो लाख लड़कों और लड़कियों को प्रशिक्षित किया । 40,000 कार्यरत हैं। रेमंड, मारुति, जी 4 सिक्योरिटी, कैफ़े कॉफी डे, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो भर्ती के लिए आती हैं।

सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि

अखिलेश यादव ने यूपी के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया

इस लगातार बढ़ती आधुनिक दुनिया में, मनुष्यों ने महसूस किया है कि गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन अब बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगे और एक बार जब वे चले जाते हैं, तो उन्हें फिर से भरा नहीं जा सकता। ये जीवाश्म ईंधन भी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का एक प्रमुख कारण रहे हैं। हाल के दिनों में, सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन से होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं के संभावित समाधान के रूप में सामने आई है। अक्षय सौर ऊर्जा के महत्व को समझते हुए, उत्तर प्रदेश के दूरदर्शी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के सौर विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया ।

राज्य के अधिक पर्यावरण-अनुकूल समावेशी विकास की दिशा में कदम उठाते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर विकास की दिशा में कई उपाय किए हैं। उनमें से कुछ हैं:

- जुलाई 2015 तक लगभग 15722 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करना
- सौर पार्क और एक अल्ट्रा-मेगा सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 2 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
- सौर ऊर्जा और रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्र नीति भी लागू की गई है
- विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में 160 से अधिक सौर आरओ जल संयंत्र (1 किलोवाट की क्षमता) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं
- 105 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए डेवलपर्स को पत्र जारी किया गया
- 2013-14 में 900 सौर पीवी पंप स्थापित किए गए और राज्य में 5000 और स्थापित किए जा रहे थे
- औद्योगिक और घरेलू उद्देश्यों के लिए कुल क्षमता 2.5 मिलियन लीटर प्रति दिन की सौर जल तापन प्रणाली
- दयाल बाग संस्थान, आगरा और राम शैक्षिक समाज, हापुड़ में सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम स्थापित
- 3 एक्स 10 मेगावाट, 10 मेगावाट, और 5 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र ने क्रमशः ललितपुर, महोबा और नैनी (इलाहाबाद) में परिचालन शुरू किया।
- जिला बाराबंकी, झाँसी, और बरेली में 7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित
- न्यूनतम 1 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए बनाई गई सौर ऊर्जा नीति
- लोहिया समागम ग्राम विकास योजना के तहत, 1598 गांवों, उद्योगों, तहसीलों और खंड विकास कार्यालयों में 18,444 सौर स्ट्रीटलाइट्स लगाए गए ।
- वर्तमान सरकार द्वारा 96,151 गाँवों का विद्युतीकरण, 36,842 सौर ऊर्जा होम लाइटिंग और 66,585 बायोमास बिजली सौर स्ट्रीटलाइट्स लगाए गए ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 1,21,000 सौर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम के साथ 2 लाख से अधिक सौर होम लाइटिंग सिस्टम स्थापित किए गए
- 2098 गांवों में 2014-15 में 26,715 सौर स्ट्रीटलाइट भी लगाए गए थे

अधिक सौर ऊर्जा पैदा करने की दिशा में झुकाव, गरीब गाँवों और पड़ोस में अक्षय ऊर्जा वितरित करके ऐतिहासिक बाधाओं को तोड़ने में राज्य की मदद की । इन कदमों ने सीएम अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बिजली-अधिशेष राज्य बनने की यात्रा शुरू करने में मदद की है, क्योंकि लगभग 13000 मेगावाट अतिरिक्त क्षमताएँ उपलब्ध कराई जानी थी । , लगभग 10000 मेगावाट की मौजूदा उपलब्धता के अलावा। सौर विकास राज्य और इसके गरीबों के लिए एक अभूतपूर्व गेम-चेंजर है। यह बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए आधारशिला रखेगा और अपने नागरिकों को बेहतर और समृद्ध जीवन जीने में मदद करेगा।

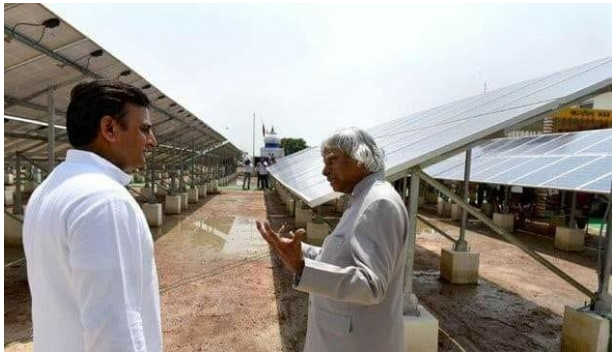

स्पोर्ट्स कॉलेज, सैफई

इसकी स्थापना 2014 में सीएम अखिलेश यादव द्वारा सैफई, इटावा जिले, उत्तर प्रदेश में सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में की गई थी

मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज, जिसे पहले सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में जाना जाता था, उत्तर प्रदेश के सैफई, इटावा जिले में एक कॉलेज और स्पोर्ट्स अकादमी है। यह 2014 में राज्य सरकार द्वारा सैफई, इटावा जिले, उत्तर प्रदेश में सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था, यह एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, तैराकी और जूडो में 6 वीं से 12 वीं कक्षा में यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान करता है, लखनऊ में गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और गोरखपुर में बीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के बाद उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई। कॉलेज निम्नलिखित खेलों का प्रशिक्षण प्रदान करता है: एथलेटिक्स, फुटबॉल, कुश्ती, कबड्डी और बैडमिंटन, बैडमिंटन और एथलेटिक्स यह एक आवासीय परिसर है और इसके कारण कुल मिलाकर वजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है; कॉलेज का लड़का वर्ग क्रिकेट, हॉकी में खेल प्रशिक्षण प्राप्त करता है,

इस स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षुओं की संख्या 560 के रूप में निर्धारित की जाती है। पहले वर्ष में 74 प्रशिक्षुओं ने यहाँ अध्ययन शुरू किया। सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सिंथेटिक रनिंग ट्रैक या एथलीट्स स्टेडियम इंडोर स्टेडियम स्विमिंग पूल हॉकी मैदान एस्ट्रोतुरफ तीन घास के मैदान बास्केटबॉल कोर्ट टेनिस कोर्ट एडमिन एंड एजुकेशन ब्लॉक हॉस्टल डिस्पेंसरी गेस्ट हाउस फैकल्टी आवास इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन

ताजगंज प्रोजेक्ट

ताजगंज परियोजना, ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को आंतरिक रिंग रोड के साथ, जो ताज के साथ यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ता है,

जिसका उद्घाटन 27 नवंबर 2016 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था।

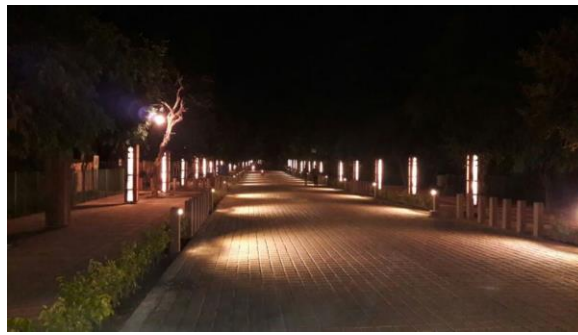

ताज गंज एक बाजार है जो 400 साल पुराना है और ताजमहल के परिधीय क्षितिज को साझा करता है। इसमें बस्तियों (पड़ोस) के समूह शामिल हैं जो मूल रूप से ताजमहल के दक्षिणी द्वार की ओर चार 'कत्रों' या चौपाइयों के साथ शुरू हुए थे। तब से यह धीरे-धीरे विस्तारित हो गया है और शहर भर में झुग्गी बस्तियों के समूह भी इस प्रक्रिया में बन गए हैं। अब तक, ताज गंज की अजीबोगरीब शहरी स्थिति शहरीकरण की दिशा में पर्याप्त हस्तक्षेप से बच गई है। इसलिए एक रणनीतिक योजना का सुझाव दिया गया था जिसमें ताज गंज के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों जैसे हितधारकों को शामिल किया गया, ताकि सड़क के चरित्र को बेहतर बनाया जा सके और बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को उन्नत करने में सहायता की जा सके। ताज गंज के शहरी पुनर्विकास के लिए विचाराधीन क्षेत्र, ताजमहल के पश्चिमी गेट रोड से फतेहाबाद रोड के पूर्वी गेट तक फैला है, प्रस्तावों में पैदल यात्री फुटपाथ, बाइक ट्रैक, लैंडस्केप पार्क, बैठने, शौचालय, सुरक्षा के प्रावधान को पुनर्जीवित करके शहरी सड़क विकास शामिल है। दक्षिणी गेट और पश्चिमी गेट ज़ोन पर ओपन स्पेस लैंडस्केप विकास सहित पूर्वी गेट, पश्चिम गेट और ताज गंज जिले के आसपास सुविधाएं, आदि। प्रस्तावों में शहरी सड़क विकास शामिल है।

ट्रांस गंगा प्रोजेक्ट उन्नाव

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्नाव में ट्रांस गंगा परियोजना की नींव रखी।

उन्नाव, राज्य की राजधानी लखनऊ और उद्योग नगर कानपुर के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। यह प्रस्तावित लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (LIDA) का ग्राउंड ज़ीरो है।

ट्रांस गंगा सिटी उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रांत उन्नाव जिले में नियोजित उपग्रह टाउनशिप है जो कानपुर महानगर के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में एनएच 25 और उन्नाव-शुक्लागंज राजमार्ग पर कानपुर के पास गंगा नदी के लिए उन्नाव नगर पालिका की सीमा से बढ़ाव शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित हाई-टेक शहर के पास कौशल विकास विश्वविद्यालय भी प्रस्तावित किया । कानपुर का इनर रिंग रोड ट्रांस गंगा शहर से गुजरता है जो आगे ट्रांस गंगा से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बदरका के पास प्रस्तावित कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है । इनर रिंग रोड कानपुर एयरपोर्ट के आगामी टर्मिनल से भी जुड़ा है एक कनेक्टर रोड द्वारा जो ट्रांस गंगा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हाई-टेक शहर से सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पर है।

शहर का डिजाइन दो स्तरों पर तैयार किया गया है। सबसे पहले, शहर को टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक डिज़ाइन स्तर के तत्वों के साथ। दूसरा, ग्रीन रूफ, अर्थ

कूलिंग, सोलर पैनल, भूजल पुनर्भरण और अपशिष्ट प्रबंधन का कार्यान्वयन। परियोजना के अंत में, एक प्रतिष्ठित ऑटो एक्सपो मार्ट की योजना है, जो इसे एक प्रमुख दृश्य मार्कर बनाता है।

परियोजना की विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 24x7 बिजली आपूर्ति का प्रावधान।
- अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन मानक।
- मॉल, प्रदर्शनी केंद्र, गोल्फ कोर्स, वाणिज्यिक, निवास और खुदरा दुकानों के लिए प्रावधान।
- जल निकायों के साथ सुंदर परिदृश्य।
- हरे भरे स्थान।
- मध्यम और परिवेश का तापमान।
- पानी की आपूर्ति और सीवेज के मामले में आत्मनिर्भर।
- पर्याप्त योजनाबद्ध सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)।
- औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों के लिए कई विकल्प।
- औद्योगिक इकाइयों के लिए वाणिज्यिक, आवासीय और प्राथमिक बुनियादी ढांचे की योजना बनाई।
- जल आपूर्ति, सड़कों, नालियों, स्ट्रीट लाइट की उपयोगिता अवसंरचना।
- पुलिस और फायर स्टेशनों की आपातकालीन अवसंरचना।
- निर्बाध जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए स्वतंत्र ओवरहेड पानी की टंकी।

- क्षेत्र में हरियाली के साथ पर्याप्त पार्किंग सुविधा, स्वस्थ परिवेश प्रदान करती है।
- गंगा रिवरफ्रंट के साथ डिज़ाइन किए जाने वाले प्रतिष्ठित टॉवर।

वरुणा नदी की कायाकल्प

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरुणा नदी के कायाकल्प के लिए वरुणा रिवर फ्रंट परियोजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लखनऊ में जनता को समर्पित किया। परियोजना के मॉडल क्षेत्र, जिसे वरुणा के कायाकल्प के लिए लॉन्च किया गया था, का उद्घाटन किया गया ।

वरुणा नदी सभी के लिए एक नया रास्ता तय करती है। जिस नदी ने पवित्र शहर वाराणसी को अपना नाम दिया, दुख की बात यह है कि हाल के दिनों में कचरे की एक धारा तक सिमट गई है। हालांकि, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का वरुणा कॉरिडोर का ड्रीम प्रोजेक्ट आशाजनक है और बदसूरत वास्तविकता को बदलने की उम्मीद करता है। परियोजना का उद्देश्य वरुणा नदी को शहर के एक प्रमुख पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना है।

साबरमती, सिंगापुर और मलेशिया से प्रभावित होकर, वरुणा कॉरिडोर वरुणा नदी को साफ करके,नदी के किनारों को चमचमाती रोशनी से सजी सड़कों के साथ एक ग्रीन बेल्ट में विकसित किया जाएगा जहाँ दर्शकों को लुभाने के लिए वाटर स्पोर्ट्स की सुविधाएं भी होंगी।

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और सिंचाई विभाग अखिलेश जी के सपने को साकार करने के लिए समय के साथ काम कर रहे थे। नदी के किनारे शश्री घाट और चौका घाट के बीच 300 मीटर की दूरी परियोजना के पहले चरण में पहले से ही विकसित हो गई थी | खुदाई के दौरान खुदाई की गई मिट्टी का इस्तेमाल एक रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए किया गया जो बारिश के मौसम में मिट्टी के कटाव को रोकती है। वाराणसी में अधिकांश होटल वरुणा नदी के किनारे बनाए गए हैं। इन होटलों से गंगा नदी तक पर्यटकों को पहुंचाने के लिए नाव और स्टीमर सेवाएं शुरू करें का प्रयास था | यह भीड़भाड़ वाली सड़कों से आगंतुकों को बचाएगा और वे कम समय में ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में सक्षम होंगे |

वरुणा नदी के आसपास के दो किलोमीटर क्षेत्र को वाटर स्पोर्ट्स जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र पानी के पोलो, कैनोइंग, राफ्टिंग आदि सुविधाओं के साथ एक समुद्र तट जैसा होगा।

आयातित रोशनी नदी की सुंदरता में इजाफा करेगी। नदी के पुलों पर एक कृत्रिम झरना बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन था । ग्रीन बेल्ट नदी के दोनों किनारों पर लगभग 25 मीटर क्षेत्र को कवर करेगा।

अधिकारियों ने गंगा के पानी को वरुणा नदी तक पहुंचाने के लिए रामेश्वर के पास एक चेक डैम बनाने की भी योजना बनाई थी । वर्तमान में नदी में गिरने वाले सीवेज के पानी को मोहना में ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाएगा।

एकीकृत पोर्टल 'जन-सुनवाई' (jansunwai.up.nic.in) का शुभारंभ किया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी आवास पर जन शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु देश के पहले एकीकृत पोर्टल 'जन-सुनवाई' (jansunwai.up.nic.in) के साथ-साथ देश की पहली मीडिया हेल्पलाइन (1800-1800-303) का शुभारम्भ किया। इस पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की छोटी-छोटी समस्याओं एवं शिकायतों के निस्तारण पर मुख्यमंत्री कार्यालय से 'जन-सुनवाई' पोर्टल के माध्यम से निगाह रखी जाएगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी और उनकी शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता आएगी। इस समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली की विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, तहसील दिवस व आनलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 फरवरी, 2016 से अन्य राज्य स्तरीय कार्यालयों में आनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी इस प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। इसमें ई-मार्किंग के जरिए जनता की शिकायतें व आवेदन, सम्बन्धित अधिकारियों एवं विभागों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से भेजे जाएंगे, जिससे

निस्तारण में गति आएगी। लोग अपनी शिकायतें एवं आवेदन घर बैठे आनलाइन कर सकते हैं, जिससे लोगों को अनावश्यक विभिन्न कार्यालयों में आने-जाने से राहत मिलेगी।

शिकायतों के निस्तारण की स्थिति पर इसी पोर्टल द्वारा जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और यदि निस्तारण की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इसी पोर्टल पर अपनी बात पुनः लिखने की सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों पर सीधे उनके कार्यालय द्वारा सतत नज़र रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण एवं अन्य प्रकरणों में फीडबैक प्राप्त करने के लिए अलग से काल सेण्टर भी स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस प्रयास से गवर्नेन्स में सहूलियत होगी।

कुछ अन्य प्रोजेक्ट

अखिलेश यादव एक युवा नेता हैं, जिनके विकास की कहानी उन्हें दूसरों से अलग करती है। उन्होंने इन पांच वर्षों में यूपी को बदल दिया है और वह चाहते हैं कि केवल विकास ही उनके नाम के साथ जुड़े। वह वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पार्टी की एक छवि बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं और उनका काम राज्य के लोगों में अच्छी तरह से गूंज रहा है।

अखिलेश यादव द्वारा शुरू किए गए कुछ अन्य कार्य निम्नानुसार हैं:

मुलायम सिंह जी के 74 वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने किसानों का कर्ज माफ किया:अखिलेश यादव ने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के 74 वें जन्मदिन पर सहकारी ग्रामीण विकास बैंक के ऋणी किसानों को उपहार देकर 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ किया। तत्कालीन सरकार के इस निर्णय से सात लाख बीस हजार किसान लाभान्वित हुए। ऋण माफी योजना का लाभ उन किसानों को दिया गया जिन्होंने 31 मार्च 2012 तक अपने ऋण का दस प्रतिशत भुगतान किया । इस अवसर पर अखिलेश ने बताया कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 1650 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और लगभग सात लाख बीस हजार किसान लाभान्वित होंगे।

ओलावृष्टि की मार झेल रहे किसानों को अखिलेश यादव ने दी हर संभव मदद: उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर, 12 जिलों के किसानों के लिए 102.18 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जिनकी फसल ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई थी। वर्ष 2016-17 में, इस निधि को राज्य आकस्मिकता निधि से अनुमोदित किया गया । मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह राशि जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराई गई थी। किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार संवेदनशील थी, फिरोजाबाद में प्रभावित किसानों को 60.90 लाख, बांदा (3.28 करोड़), कानपुर देहात (1.89 करोड़ र), महोबा (4.28 करोड़), फतेहपुर (36.14 करोड़), अलीगढ़ (3.22 करोड़), सीतापुर (3.24 करोड़)।), हमीरपुर रु। 7.87 करोड़, आगरा (85.55 लाख), इटावा (2.15 करोड़ रुपये), गाजीपुर (3.49 लाख) और जालौन के किसानों को 38.57 करोड़ दिए गए |

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव ने 26 दिसंबर, 2016 को लोक भवन, नए सचिवालय - लखनऊ में 'शिलान्यास' (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के साथ ग्यारह नई रसोई स्थापित करने की घोषणा की।

इन रसोईयों ने नए शैक्षणिक वर्ष में बच्चों को मध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal) देना शुरू किया और नियत समय में प्रति दिन 1 लाख से अधिक बच्चों तक पहुँच को बढाया |फाउंडेशन अपनी वृंदावन रसोई से 1,05,000 बच्चों को और लखनऊ रसोई से 66,000 बच्चोंको खिला रहा था, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 3021 स्कूलों में 1,71,000 बच्चे थे। (15 मार्च, 2015 को अखिलेश यादव द्वारा उद्घाटन किया गया) कार्यक्रम के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को हर बुधवार दोपहर के भोजन में एक गिलास - 200 मिली - उबला हुआ दूध भी प्राप्त होता । सप्ताह में एक बार उसी दुग्ध से खीर बना कर देने का निर्देश दिया गया | सभी जिलाधिकारियों को स्कूल डाइट पर दूध रखने का निर्देश दिया गया। इन नए 11 किचन की शुरुआत के साथ, प्रति दिन 13 लाख से अधिक लाभार्थियों की सेवा का विस्तार हुआ |

अखिलेश यादव ने लखनऊ वासियों के लिए मुफ्त वाई-फाई सुविधा शुरू की: अपनी लोकलुभावन योजनाओं में एक और आयाम जोड़ते हुए, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ के निवासियों के लिए अपने मुख्य बाजार हजरतगंज क्षेत्र में मुफ्त वाई-फाई सेवाओं की शुरुआत की। वाई-फाई सेवाएं प्रत्येक दिन नि: शुल्क उपलब्ध थीं, इस सेवा के शुभारंभ के साथ ही लखनऊ भारत में मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने वाला पहला शहर बन गया।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में शहीद पथ रिंग रोड के लिए हाई मास्ट एलईडी लाइट, मॉड्यूलर सार्वजनिक उपयुक्तता और प्रकाश व्यवस्था सहित अन्य योजनाओं की अधिकता के साथ मुफ्त वाई-फाई सेवा की शुरुआत की, जिसमें जन भागीदारी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक साप्ताहिक कार्निवल था। अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था में गति की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, "यदि हम गति को दोगुना करेंगे तो अर्थव्यवस्था तीन गुना होगी "।

जैव विविधता केंद्र कुकरैल: कुकरैल 5,000 हेक्टेयर में फैला एक आरक्षित वन है ,वन विभाग द्वारा तैयार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कुकरैल में मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीकरण का सुझाव दिया गया । इसमें म्यूज़ियम का निर्माण, शहर में मौजूद एक से बड़ा एक चिड़ियाघर और एक प्रकृति व्याख्या केंद्र, इसके अलावा कुकरैल पिकनिक स्थल पर बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं।

नई कुकरैल से न केवल पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है, बल्कि यह स्थान जंगल का रूप और अनुभव भी देगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन में काम करने वाले, जो राज्य में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं, वन विभाग ने कुकरैल के इको-टूरिज्म हब के रूप में एक प्रमुख बदलाव की योजना बनाई ।

अखिलेश यादव ने दिसंबर 2014 को स्वदेश - सिलिकॉन वैली और अवध के लोगो के लिए उद्यमी सेवाओं के विकास की परियोजना शुरू की: स्वदेश उत्तर प्रदेश और सिलिकॉन वैली के लोगों को एक साथ लाने की दिशा में पहला कदम है। अखिलेश ने एक एनआरआई विभाग बनाया और इसका उद्देश्य अधिक से अधिक

लोगों को जोड़ना था ... दुनिया भर में, स्वास्थ्य और आईटी क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। टेनासिटी और यूपी के बीच सहयोग में तकनीकी सहयोग, कौशल विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे सहित कई पहलू शामिल हैं, जो विश्व स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना करते हैं।

द्रष्टि-निगरानी परियोजना:12 अप्रैल 2015 को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्मार्ट सिटी निगरानी परियोजना का अनावरण किया जिसमें 280 कैमरों के साथ 70 क्रॉसिंग शामिल थे, इस परियोजना का शीर्षक Drishthi था ।

उत्तर प्रदेश की तत्कालीन राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अपने शहर को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए लखनऊ सिटी के लिए स्मार्ट निगरानी को लागू करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित नवीनतम तकनीकों के उपयोग की कल्पना की। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सड़कों पर अपराध नियंत्रण और यातायात प्रबंधन इस परियोजना का मुख्य केंद्र बिंदु था।

बुनकर बाजार के खुलने से उम्मीदों को पंख लगे:मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गाजियाबाद और नोएडा में बुनकर बाजार स्थापित करने की घोषणा से हथकरघा बिजली करघा व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई । इस घोषणा के बाद, एक तरफ, व्यापारियों को उत्पादन का उचित लाभ मिला, जबकि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। मुरादनगर शहर, जिसे हैंडलूम पावर लूम उद्योग के रूप में जाना जाता है, को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस शहर से बड़ी मात्रा में उत्पादित कपड़े की वजह से इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। अब तक, राज्य का यह उपहार उन उद्यमियों को बहुत भाता है, जो दूसरे राज्यों में कपड़े निर्यात करते हैं। कपड़ा उत्पादन के बाद व्यापारियों को अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता था, जिसके कारण माल ढुलाई आदि की लागत काफी अधिक थी। अब तक हथकरघा बिजली करघा व्यापारियों को सरकार से कोई सुविधा नहीं थी। न ही कोई हौसला था। इसकी स्थापना से व्यापारियों की सभी शिकायतें दूर हो गई । अब तक ऐसा लगता था कि सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह उपहार व्यापारियों के हित में था ।

लखनऊ में लुलू समूह ने किया 1,000 करोड़ का निवेश: जनवरी 2016 में खाड़ी स्थित कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, एक पांच सितारा होटल और एक मॉल स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया। यह घोषणा करते हुए, लुलु समूह के प्रबंध निदेशक एमए यूसुफ अली ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आगरा में पहले यूपी प्रवासी दिवस पर भारतीय प्रवासियों की एक सभा में बताया कि वह राज्य में किए जा रहे काम से प्रभावित हैंऔर निवेश करने के लिए तैयार हैं |सीएम अखिलेश यादव ने यूसुफ अली के उत्तर प्रदेश में निवेश करने के वादे का स्वागत

किया। और भूमि को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया और अन्य सहायता प्रदान का आश्वासन दिया ताकि वह काम शुरू कर सके।

लखनऊ में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS) परियोजना: उन्नत बस सेवा में कई प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे स्थिर मल्टी-नोडल केंद्रों पर ठहराव जहां एक यात्री सीधे एक टेम्पो या रिक्शा पर सवार हो सकता है और अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। मल्टी-नोडल केंद्र ऐसे स्थान होंगे जहां एक व्यक्ति एक परिवहन से दूसरे तक आसानी से जा सकता है। यह सेवा डिजिटल पीआईएस (यात्री सूचना प्रणाली) के साथ बस स्टॉप सुनिश्चित करेगी जो आने वाले समय, सटीक स्थान और बस का मार्ग बताएगी। बसों को जीपीएस-सक्षम किया जाएगा और केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली से जोड़ा जाएगा जहां अधिकारी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। यह एक एप्लिकेशन भी विकसित करेगा जिसके साथ अंतिम मिनट की परेशानियों से बचने के लिए यात्री पहले से सीट बुक कर सकता है। लो-फ्लोर बसों के अलावा, सिस्टम में अत्याधुनिक स्टेशन और स्मार्ट कार्ड के माध्यम से टिकट की सुविधा होगी। इसे फीडर बसों से जोड़ा जाएगा।

गोवर्धन हिल्स का पुनर्विकास:रुद्र कुंड की बहाली पूरी हो गई और 11 मार्च 2015 को यूपी के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा ब्रजवासियों को समर्पित किया गया। रुद्र कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह जतीपुरा में गिरिराज मुखारविंद के सामने स्थित है, जहाँ कृष्ण ने गिरिराज पूजा के दौरान अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया था। प्रस्तावित योजना रुद्र कुंड को एक ज्यामितीय आकृति में विकसित किया गया | यह कुंड शिव जी की कथा से जुड़ा है; शिव यंत्र ध्यान का मुख्य तत्व है। यन्त्र का केंद्र एक 'अष्ट कमल' है, और इसका प्रतिबिंब कुंड के पानी में दिखाई देगा। जल जीविका का प्रतिनिधित्व करता है। पानी पर शिव यंत्र का प्रतिबिंब हर और हरि के मिलन को दर्शाता है। कुंड के लिए बारहमासी जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। इस पानी के नियमित परिसंचरण के लिए इसके ऑक्सीकरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान हैं। पानी को बिजली के पंप के माध्यम से मुख्य कुंड से उठाया गया और कुंड के चारों ओर 4 साइड पूल में ले जाया गया। वहां से यह गायों के सफेद मार्बल मास्क के माध्यम से वापस कुंड में बहती है। इससे कुंड कि सुंदरता और बढ़ जाती है। कुंड के चारों ओर हरे-भरे बगीचे को परिकर्मार्थी के आनंद के लिए विकसित किया गया है।

अखिलेश यादव जी ने स्कूल यूनिफार्म और किताबों के लिए बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ रहे गरीब बच्चों को 5000 रुपये प्रदान किए बिना मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के गरीब बच्चों को ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए पांच हजार (एक बार) दिए गए। निजी स्कूलों के बच्चों उसी प्रकार लाभ दिया गया जैसे 16000 से अधिक सरकारी स्कूलों के छात्रों को योजना से लाभान्वित किया गया था ।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा, उनकी अन्य परियोजनाएं धार्मिक स्थानों में रोपवे,1,300 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए विस्ट्रॉन ऑप्टिमम के साथ जेवी की स्थापना, यूपी में ग्रीन कवर सीमांत वृद्धि, गोमती नदी पर नया पुल, मेगा फूड जगदीशपुर, कपड़ा पार्क बांदा , डिजाइन यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ताज ओरिएंटेशन सेंटर, आगरा में यमुना पर एक पुल का निर्माण, अवध हॉस्पिटल और अमौसी एयरपोर्ट फ्लाईओवर, हार्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ, फॉरेंसिक लैब यूनिवर्सिटी लखनऊ, फ़ोर्चूना-अवध टेक्नोलॉजी पार्क, अपर गंगा नहर एक्सप्रेसवे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम ऊद्योग (एमएसएमई) टाउनशिप नीति 2012, मथुरा नॉलेज सिटी, मंधना-भौंती एकीकृत टाउनशिप और इसके अतिरिक्त और भी कार्य हैं , जिनको कि एक किताब में लिखना बहुत ही कठिन है| क्यूंकि अखिलेश जी के द्वारा इतने कम समय में इतने अधिक कार्य किये गए हैं कि जिनका वर्णन एक छोटी किताब में करना असंभव है | अखिलेश जी को भारत के सबसे प्रभावशाली मुख्य मंत्रियों में से एक माना जाता है। अगर हम उनकी राजनीतिक उपलब्धियों पर विचार करें, तो बहुत कम नेता अपनी बातों पर कायम हैं। औद्योगिक विकास हो या ग्रामीण विकास, अखिलेश यादव ने इसके हर पहलू पर काम किया है। इसीलिए लोगों को लगता है कि वह भारत के सबसे प्रभावशाली नेता हैं -

लोगों की वृद्धि और विकास नेतृत्व का सर्वोच्च आह्वान है। सभी वृद्धि गतिविधि पर निर्भर करती है। बिना प्रयास के शारीरिक या बौद्धिक रूप से कोई विकास नहीं होता है, और प्रयास का अर्थ है काम ।

संदर्भ

- https://hindi.oneindia.com/news/lucknow/ratan-tata-praises-akhilesh-yadav-and-development-of-up-392145.html?story=1
- http://www.studyguideindia.com/news/education/News-details.asp?NID=15451&NY=2013
- https://www.oneindia.com/politicians/akhilesh-yadav-22828.html
- https://www.samajwadiparty.in/party-ideology
- https://economictimes.indiatimes.com//news/politics-and-nation/how-akhilesh-yadav-won-the-sp-power-struggle/articleshow/56301820.cms?tm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=
- https: //economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/how-akhilesh-yadav-won-the-sp-power-struggle/articleshow/56301820.cms \
- https://inshorts.com/en/news/akhilesh-yadav-a-man-with-clean-image-congress-1476678057166
- https://www.indiatvnews.com/news/india/up-government-uttar-pradesh-medical-aid-poor-akhilesh-yadav-40403.html
- https://www.news18.com/news/politics/sp-chief-akhilesh-yadav-demands-centres-rs-20-lakh-crore-economic-package-breakup-2656429.html
- https://www.moneycontrol.com/news/politics/akhilesh-yadav-drives-to-mayawatis-residence-thanks-her-2528349.html
- https://www.theweekendleader.com/Culture/2341/saviour-cm.html
- https://www.dnaindia.com/india/report-akhilesh-yadav-puts-up-a-brave-face-says-samajwadi-pariwar-united-2257005
- https://en.wikipedia.org/wiki/Agra_Lucknow_Expressway
  http://timesofindia.indiatimes.com/..n-Agra-Lucknow-e-way/articleshow/47774552.cms
  http://abpnews.abplive.in/india-new...tigation-on-agra-lucknow-expressway-2-432720/
- http://upeida.in/en/page/agra-to-lucknow-access-controlled-expressway

- https://en.wikipedia.org/wiki/Purvanchal_Expressway#:~:text=July%202019%3A%20The%20Purvanchal%20Expressway,2019%320%2020%25%20expressway%20complete
- http://www.museindia.com/welcome-to-samajwadi-purvanchal-expressway/
- https://www.amarujala.com/photo-gallery/delhi-ncr/akhilesh-yadav-posters-on-elevated-road-that-was-inaugrated-by-yogi-minister-in-noida
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/
- https://www.financialexpress.com/infrastructure/indias-longest-elevated-road-inaugurated-by-yogi-adityanath-top-10-facts-about-the-project/11161466
- https://www.news18.com/news/india/up-cm-yogi-adityanath-inaugurates-indias-longest-elevated-road-in-ghaziabad-akhilesh-yadav-tweets-snide-remark-1703747.html
- https://www.dailypioneer.com/2016/state-editions/complete-construction-work-of-four-lane-roads-within-deadline-akhilesh-yadav.html
- https://www.business-standard.com/article/economy-policy/expressway-and-roads-to-growth-115031701365_1.html
- https://timesofindia.indiatimes.com/uttar-pradesh/50-district-in-UP-are-connected-to-four-lane-roads-CM/articleshow/53536788.cms?bot=1
- https://www.makaan.com/iq/city/how-nh-24-expansion-will-change-the-face-of-ncr
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-2
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cycle_Tracks_in_Uttar_Pradesh
- https://www.amarujala.com/photo-gallery/lucknow/akhilesh-yadav-inaugrates-cycle-track-in-lucknow?pageId=9
- https://www.outlookindia.com/newswire/story/uttar-pradesh-govt-to-demolen-cycle-tracks-constructed-during-akhilesh-yadavs-tenure/97/8282
- https://www.freepressjournal.in/india/akhilesh-yadav-promotes-the-cycle-track-twitter-says-enough-of-marketing
- https://travelandy.com/bycl-highway-to-connect-agra-and-etawah/
- https://www.incredibleindia.org/content/incredible-india-v2/en/destinations/agra/agra-etawah-boline-highway.html
- https://www.samajwadiparty.in/development
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lucknow_Metro

- https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/Lucknow-Metro-construction-begins-Akhilesh-fulfils-promise-to-father/articleshow/43623937.cms
- https://inshorts.com/en/news/akhilesh-lays-foundation-stone-of-noidagr-noida-metro-link-1481801548292
- https://www.hindustantimes.com/noida/cm-lays-foundation-of-15km-metro-link/story-hLGm1lX3SAYxIgtWtATGeM.html
- http://ncrhomes.com/2010/noida-metro-extensions-to-sec-62-and-grait-noida/
- https://www.indiatvnews.com/business/india/metro-rail-between-noida-gitory-noida-by-2017-14722.html
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/noida/UP-clears-Metro-to-Grait-Noida/articleshow/43927104.cms
- https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/dilshad-narden-new-bus-metro-all-you-need-to-know-about-delhi-metro-red-line/story/ 319071.html
- http://zeenews.india.com/news/uttar...d-garden-new-bus-stand-metro-line_938885.html
- http://www.thehindu.com/news/cities..haziabad-to-take-more-time/article8038831.ece
- http://www.ndtv.com/delhi-news/delhi-metro-hurdles-in-ghaziabad-resolved-1270688
- http://epaperbeta.timesofindia.com/..-goes-hi-tech-with-first-model-21122016003023
- https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/akhilesh-yadav-launches-hightech-bus-in-noida-392269-2016-12-14
- https://www.amarujala.com/lucknow/akhilesh-yadav-congratulate-bridge-carporation
- https://www.bhaskar.com/news/UP-LUCK-akhilesh-inaugurated-ghazipur-over-bridge-news-hindi-5465226-NOR.html
- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-inaugurated-chanduli-sakaldiha-saidpur-road-bridge-built-across-the-ganges/
- http://timesofindia.indiatimes.com/...ive-in-Guinness-book/articleshow/53691459.cms
- https://www.bankbazaar.com/saving-s...d-to-know-about-samajwadi-pension-yojana.html
  http://www.atalpensionyojana.co.in/up-samajwadi-pension-list-2016-17-hindi-status-names-district/
- http://timesofindia.indiatimes.com/...gar-mill-in-Azamgarh/articleshow/48506463.cms

- https://www.jagranjosh.com/current-affairs/bhumi-sena-scheme-launched-in-up-for-transformation-of-barren-land-1376030777-1
- https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/uttar-pradesh-cm-akhilesh-yadav-distributed-one-thousand-bicycles-and-launchl-pension-scheme-for-workers-over-over 60-वर्ष की आयु -368902-2016-05-01
- https://www.business-standard.com/multimedia/video-gallery/general/cm-akhilesh-yadav-distributes-e-rickshaws-to-drivers-in-lucknow-24855.htm
- https://www.business-standard.com/multimedia/video-gallery/general/cm-akhilesh-yadav-distributes-tricycles-to-spatalog-abled-children-42625.htm
- https://www.amarujala.com/lucknow/cm-akhilesh-yadav-distributed-tricycle-on-international-disability-day
- https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/graft-allegations-halt-up-govts-free-bycles-scheme-in-moradabad-3076125/
- https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/after-laptops-akhilesh-hopes-to-ride-on-bycles-dole/
- https://www.bhaskar.com/news/UP-LUCK-akhilesh-yadav-launch-mid-day-meal-scheme-for-labourers-and-distribute-cycles-531377-PHO.html
- https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/subsidy-reform-seeding-dbt-on-the-ground/
- https://www.google.com/search?q=DBT+Model+of+UP+for+seed+subsidy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiivi9yvfxfAhWyIbcahedDCsAQ_AUoAnUQUBABABABABABABABABABABA
- https://indianexpress.com/article/india/india-news-india/up-shows-way-in-direct-subsidy-payment-to-farmers/
- https://www.jansamachar.com/uttar-pradesh/up-kanya-vidya-dhan-scheme-akhilesh-yadav/
- https://www.jagran.com/blogs/mithilesh2020/raksha-bandhan-and-akhilesh-yay/
- https://www.amarujala.com/lucknow/akhilesh-yadav-distributed-kanya-vidya-dhan-cheque
- https://www.uttarpradesh.org/uttarpradesh/cm-akhilesh-kisan-bazar-mandi-schemes-inauguration-9876/
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/govt-gives-145cr-for-waterstorage-plan-in-bundelkhand/articleshowprint/52368642.cms
- http://www.uniindia.com/completed-water-task-in-bundelkhand-in-record-time-shivpal/states/news/522425.html
- https://www.tupaki.com/politicalnews/article/Third-Samajwadi-Shravan-Yatra-to-Tirupati--Rameshwaram/121701

- https://pmjandhanyojana.co.in/samajwadi-shravan-yatra-scheme-list-pp
- https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/Akhilesh-Yadav-government-launches-unemployment-allowance-scheme-123958-2012-09-09
- https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/290416/up-cm-akhilesh-plans-special-mahila-bazaar-for-women-entrepreneurs.html
- https://qrius.com/up-government-2015-16-kisanvarsh-agricultural-progress-insurance-coverage-credit-facilities/
- https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/uttar-pradesh-chief-minister-akhilesh-yadav-launches-pension-scheme-for-poor-families/articleshow/45046336.cms?from=from=from एमडीआर
- https://www.patrika.com/lucknow-news/akhilesh-will-give-ration-every-month-to-bundelkhand-people-1258217/
- https://www.pradhanmantriyojana.co.in/hausla-poshan-yojana/
- https://www.amarujala.com/lucknow/hausla-poshan-yojna-of-sp-government-closed-by-yogi-government?pageId=1
- https://www.amarujala.com/lucknow/cm-akhilesh-inaugurates-dial-100?pageId=
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-4
- https://feedtrends.com/sheroes-cafe-lucknow-run-by-acid-attack-survivors-visit-special-place
- http://udyogbandhu.com/datafiles/cms/file/e_news_letter_march2014.pdf
- https://www.hindustantimes.com/lucknow/single-window-system-web-based-facility-to-help-in-setting-up-industrial-units/story-mQEyUnHtHFjE882vzQhhCIP.html
- https://in.news.yahoo.com/dial-1090-help-akhilesh-yadav-122000465.html
- https://www.jagranjosh.com/current-affairs/chief-minister-of-uttar-pradesh-inaugurated-new-helpline-service-for-women-1353062876-1
- https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/akhilesh-yadav-calls-review-meeting-over-women-helpline-bats-for-martial-arts-training-for-girls/
- https://egov.eletsonline.com/2016/09/micromax-oppo-to-set-up-mobile-manufacturing-units-in-grait-noida/
- http://epaperbeta.timesofindia.com/...ellphone-unit-in-Gr-Noida-gets-01092016005004

- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-inaugurated-of-samajwadi-abhinav-school-in-allahabad/
- https://www.bhaskar.com/news/UP-LUCK-samajwadi-abhinav-vidyalaya-will-established-as-model-school-in-up-5196316-Pw.html
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-2
- https://twitter.com/bennettuniv/status/767345157490903562 24
- https://www.hindustantimes.com/india-news/suneet-sharma-is-the-new-chairman-and-ceo-of-the-railway-board/story-ce2OJSz1Stc60nqGhMFL.html
- https://cancerinstitute.edu.in/about.php
- https://www.skyscrapercity.com/threads/lucknow-projects-thread.1440892/page-59
- http://dsmru.up.nic.in/User/s_centre.aspx#:~:text=About%20the%20Study%20Centre,of%20its%20kind%20in%20Asia।
- http://www.museindia.com/up-cm-akhilesh-yadav-will-inaugurate-cg-city-project-on-de-201-20/
- https://www.jagran.com/news/national-akhileshs-chuck-ganjria-project-cleared-11393971.html
- https://www.hindustantimes.com/lucknow/up-cs-cracks-the-whip-on-ganjaria-project/story-Gm7aVPxaOMocWlqVV7MTGP.html
- https://www.wikiwand.com/en/Vrindavan_Chandrodaya_Mandir
- https://newsonprojects.com/news/akhilesh-yadav-inaugurates-project-to-build-vrindavan-chandrodaya-mandir-the-tallest-temple
- https://www.deccanchronicle.com/140316/nation-current-affairs/article/akhilesh-yadav-inaugurates-project-build-tallest-temple-india
- http://dainikaaj.com/cm-akhilesh-commenced-work-for-a-5000-seat-bhajan-auditorium-in-ayodhya/
- https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/ballia/cm-akhilesh-yadav-in-ballia-dictict
- https://jncu.ac.in/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bara_Thermal_Power_Station
- http: //articles.economictimes.india..nit-uttar-pradesh-super-thermal-power-project
- http://www.financialexpress.com/economy/up-set-for-power-generation-bonanza/86622/
- http://www.cea.nic.in/reports/monthly/installedcapacity/2016/installed_capacity-03.pdf

- https://www.google.com/search?q=film+tv+institute+in+lucknow+akhilesh+yadav&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjrr-ISOnvjtAhUi8HMBHUzhCbQQQauauOQOQOQOBABAQQBABA&hl=hi
- https://www.bhaskar.com/news/UP-LUCK-cm-akhilesh-yadav-lays-foundation-stone-for-film-institute-in-lucknow-news-hindi-54942828-PHO.html
- http: //articles.economictimes.india..s/55279896_1_film-policy-rs-one-crore-2-crore
  http://timesofindia.indiatimes.com/..-the-National-Awards/articleshow/515985855ms
- http://information.up.nic.in/View_engnews.aspx?id=1140
- http://upnews360.in/E/36003300300036003000/Chief-Minister-inaugurates-the-Gomti-Riverfront-Development-Project-and-the-Gausaus-Mohammad-Stadium
- https://twitter.com/yadavakhilesh/status/798905378117296128?lang?hi
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-6
- https://www.telegraphindia.com/india/yogi-photo-finish-for-unfinished-stadium/cid/1674269
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ekana_Cricket_Stadium
- https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01Qa_OjMjoM82ogTFfuW9J4Y7FdgQ:1608815731803&source=univ&bbm=isch&q=ekana+cricket+stadium+khilesh=yafe.fi/free.fi/safe.com फर।
- https://m.youtube.com/watch?v=yATqeT7KwxQ
- https://wikivisually.com/wiki/Saifai_International_Cricket_Stadium
- https://m.jagran.com/cricket/headlines-safai-to-have-biggest-scoreboard-than-other-stadiums-in-country-15820103.html
- https://sportsbookservice03.blogspot.com/2019/06/lda-football-stadium-lucknow-uttar.html
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/World-class-stadium-to-kick-up-citys-football-passion/articleshowprint/51449019.cms
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/kannauj-perfume-park-yet-to-smell-reality/articleshowprint/58429467.cms
- https://www.thehindu.com/news/national/other-states/international-perfume-museum-park-at-kannauj/article8466370.ece
- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-inaugurates-an-international-swimming-pool-in-saifai/

- http://upsamachar.ictv.in/2020/02/28/etawah-akhilesh-yadav-international-swimming-pool-saifai-sports
- https://www.business-standard.com/article/companies/shiv-nadar-lauds-akhilesh-yadav-for-lucknow-it-city-113123000854_1.html
- https://www.hcl.com/wp-content/themes/Hcl/hcl-pdf/shri-akhilesh-yadav-addresses-inaugural-batch-of-HCL-IT-CITY-Lucknow.pdf
- https://.in
- https://www.hindustantimes.com/india/in-pics-floating-in-the-sky-balloon-festival-begins-in-lucknow/story-1Esa3L6KFnYSZxZZZPbXTO.html
- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-celebrated-the-first-uttar-pradesh-tourism-day-at-janeshwar-mishra-park-with-w-lucknow-balloon-fiesta/
- https://www.dailypioneer.com/2014/state-editions/janeshwar-mishra-park-inaugurated-at-lucknow.html
- https://www.google.com/search?q=janeshwar+mishra+park+inauguration+balloon&tbm=isch&ved=2ahUKEwjggorGm_vtAhVFD3IKHdW-BtkQ2-cCegQIABAA&oq=janeshwar+mishra+park+inauguration+balloon&gs_lcp=CgNpbWcQA1DJlVhYjrJYYNS6WGgAcAB4AIABkwKIAa8OkgEFMC4yLjaYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=61XvX6DhBcWeyAPV_ZrIDQ&bih=610&biw= 1280 # imgrc = 8lVdqfH02jqFMM
- http://www.wallpaper.com/altectu...dom-museum-of-socialism#WrieuxD4WaLRPAK5.99
- https://www.cladglobal.com/CLADnews/altecture-design/Jayaprakash-Narayan-Museum-of-Socialism-Uttar-Pradesh-Healthecture-design-Lucknow-327660
- http://www.businessworld.in/article/Work-for-Kushinagar-Airport-started-during-SP-govt-s-tenure-Akhilesh-Yadav/25-06-2020-290924/
- https://www.business-standard.com/article/current-affairs/kushinagar-international-airport-project-in-up-to-take-wings-116051100968_1.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Free_laptop_distribution_scheme_of_the_Uttar_Pradesh_government
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-3
- https://indianexpress.com/article/lucknow/akhilesh-yadav-approves-two-leather-clusters-in-hardoi-and-kanpur/

- http://www.hindustantimes.com/india...and-kanpur/story-qucl93uq44mwUSiZuHWhAM.html
  http://www.uttamup.com/leather-technology-park-kanpur/
- https://www.hindustantimes.com/india-news/etawah-lion-safari-ready-to-help-gir-national-park-probe-big-cat-mortality/story-zhiHK7yxhOmYnpVs04kgTP.html
- https://etawah.nic.in/tourist-place/safari-park-etawah/
- http://www.dailypioneer.com/state-e...-supplementary-grants-for-current-fiscal.html
  http://indianexpress.com/article/in..radesh-grapples-with-dying-lions-rising-cost/
- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-visited-etawah-lion-bafaf//
- https://www.amarujala.com/lucknow/akhilesh-yadav-will-inaugurate-buddha-statue
- https://www.copper.org/publications/newsletters/innovations/2003/04/Maitreya_ProG_gg.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Maitreya_Project#/media/File:Maitreya_Project_display.jpg
- https://www.amarujala.com/channels/downloads?tm_source=text_share
- https://www.amarujala.com/lucknow/akhilesh-yadav-visits-mughal-museum-in-agra
- https://www.business-standard.com/article/news-ians/akhilesh-lays-foundation-of-mughal-museum-in-agra-116010500303_1.html
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-3
- https://www.amarujala.com/lucknow/two-new-engineering-colospitals-for-uttar-pradesh-hindi-news
- https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/Lucknow-bench-of-Allahabad-HC-begins-work-from-new-campus/article15426981.ece
- https://english.newstrack.com/lead/akhilesh-yadav-new-office-36199.html
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-2
- https://www.upums.ac.in/StaticPages/CollegeofParamedical.aspx
- https://www.youtube.com/watch?v=Q8e-EP62zcE
- https://eservices.onlineupsidc.com/flagship_projects/PlasticCity.aspx
- https://www.business-standard.com/article/pti-stories/up-for-integrated-plastic-park-status-to-auraiya-plastic-city-114080400701_1.html

- https://qrius.com/108-samajwadi-swasthya-seva-success-stories-largest-ambulance-network-india/
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-3
- https://www.samajwadiparty.in/development
- https://www.skyscrapercity.com/threads/allahabad-upsidc-saraswati-high-tech-city-proposed.1848804/
- https://www.business-standard.com/multimedia/video-gallery/general/up-cm-akhilesh-lays-foundation-stone-of-saraswati-hi-tech-smart-city-in-allahabad-25417। htm
- https://www2.slideshare.net/arun-mishra-upsidc/upsidc-unveils-1150-acre-hightech-city-in-allahabad?from_action=save
- http://timesofindia.indiatimes.com/..a-mitras-appointment/articleshow/50082766.cms
  http://indianexpress.com/article/in... अनियमित--1-72-lakh-shiksha-mitras-illegal/
- http://indiatoday.intoday.in/story/...abhishek-mishra-abhishek-mishra/1/719057.html
  http://timesofindia.indiatimes.com/...r-skills-development/articleshow/51433332.cms
- https://www.skyscrapercity.com/threads/tracking-and-evaluating-akhilesh-yadav-development-work-and-policies.1943988/page-3
- https://economictimes.indiatimes.com/ind Industries/energy/power/akhilesh-yadav-inaugurates-ups-first-solar-power-plant/printarticle/13082550.cms
- https://qrius.com/solar-development-expands-uttar-pradesh-cm-akhilesh-yadav/
- http://www.merinews.com/article/utt..electricity-amid-plenty-of-sun/15914020.shml
  http://timesofindia.indiatimes.com/...olice-stations-in-UP/articleshow/49622298.cms
- https://wikivisually.com/wiki/Major_Dhyan_Chand_Sports_College%2C_Aaaiai
- https://www.patrika.com/agra-news/akhilesh-yadav-s-dream-project-ready-at-tajganj-taj-mahal-1447070/
- https://www.business-standard.com/article/economy-policy/akhilesh-lays-foundation-of-trans-ganga-city-project-114121100964_1.html
- https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_Ganga_City
- https://eservices.onlineupsidc.com/flagship_projects/TransGangaCity.aspx

- http://www.catchnews.com/india-news/up-s-varuna-river-a-cm-s-dream-and-transformation-in-progress-1467456567.html
- http://www.musingindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-launched-jansunwai-up-nic-in-web-portal/
- https://ndtv.in/india-news/akhilesh-yadav-government-waives-loans-of-lakhs-of-farmers-357349
- http://www.museindia.com/chief-minister-akhilesh-yadav-approves-rs-102-18-crore-for-relief-to-farmers-whose-crops-were-damaged-in-the-hailstorm/
- https://indiacsr.in/akhilesh-yadav-performs-ground-breaking-cerasion-for-11-mid-day-meal-kitchens-in-up/
- https://www.indiatoday.in/india/story/akhilesh-yadav-launches-free-wi-fi-facility-for-lucknow-residents-288589-2015-08-17
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/safaris-biodiversity-park-to-make-kukrail-eco-tourism-spot/articleshow/609b814.cms
- https://indianexpress.com/article/lucknow/chief-minister-launches-nri-initiative-to-partner-with-us-in-8-sector/
- https://india.smartcitiescatalog.com/article/lucknow-goes-hi-tech-security
- https://www.jagran.com/uttar-pradesh/ghaziabad-11887542.html
- https://archello.com/project/lucknow-memorial-gate
- https://www.business-standard.com/article/news-ians/lulu-group-offers-rs-1-000-crore-investment-in-lucknow-116010401121_1.html
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/up-to-get-mass-rapid-transport-sys/articleshowprint/62102932.cms
- http://www.brajfoundation.org/projects.php?brajfoundation=51
- https://timesofindia.indiatimes.com/city/meerut/milk-to-take-place-of-kheer-in-up-school-meals/articleshow/47843250.cms
- https://agraleaks.com/cm-akhilesh-yadav-inaugurate-inner-ring-road-agra/